● वर्ष : 17 ● अंक : 224 ● मूल्य : 02 रुपया मात्र ● पृष्ठ : 08

LKS

WWW.LKSTV.IN

दैनिक लोकतंत्र की शान

लोकतंत्र का स्तंभ

दिल्ली से प्रकाशित

गुरुवार 04 जून 2026

होटल अग्निकांड: भीषण आग में 21 लोगों की मौत, कई विदेशी नागरिक भी शामिल

होटल में अंदर जल रहे थे लोग, बाहर लगा था ताला, जान बचाने कूदे लोग

एजेंसी। नई दिल्ली

राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर स्थित फ्लरिश स्टे (Flourish Stay) होटल में बुधवार सुबह भीषण आग लगने से कम से कम 21 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से झुलस गए। मृतकों में बड़ी संख्या में विदेशी नागरिकों के होने की आशंका है, हालांकि उनकी सटीक संख्या की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है।

रेस्टोरेंट से शुरू हुई आग, पूरे होटल में फैली : जानकारी के अनुसार, सुबह करीब 8:50 बजे होटल परिसर के ग्राउंड फ्लोर पर स्थित बी-एन-बी रेस्टोरेंट में आग लगी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और छह मंजिला इमारत के ऊपरी हिस्सों में बने होटल के कमरों तथा बेसमेंट तक फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही दिल्ली फायर सर्विस, पुलिस और राहत-बचाव दल मौके पर पहुंच गए और आग बुझाने के साथ-साथ लोगों को सुरक्षित निकालने का अभियान शुरू किया।

जान बचाने के लिए ऊंची मंजिलों से कूदे लोग : हादसे के दौरान कई लोग आग और धुएं से घिर गए। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए तीसरी और चौथी मंजिल से नीचे कूदते दिखाई दिए। स्थानीय लोगों ने उनकी मदद के लिए जमीन पर गद्दे और अन्य सामान बिछाकर राहत पहुंचाने का प्रयास किया।

40 लोगों को सुरक्षित निकाला गया : राहत-बचाव अभियान के दौरान करीब 40 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। वहीं बेसमेंट में फंसे छह से अधिक लोगों को भी रेस्क्यू किया गया। कई घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।

होटल में रुके थे विदेशी मेहमान : प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, होटल में सेंट्रल एशिया और अफ्रीकी देशों के कई नागरिक ठहरे हुए थे। मृतकों में भी बड़ी संख्या में विदेशी नागरिक शामिल बताए जा रहे हैं। प्रशासन उनकी पहचान और राष्ट्रीयता की पुष्टि में जुटा हुआ है।

होटल मालिक और साझेदारों की जांच शुरू : दिल्ली पुलिस के अनुसार, होटल का मालिक लोकेश बजाज है। होटल का संचालन तीन साझेदार मिलकर कर रहे थे। पुलिस ने होटल के मालिकाना हक, संचालन व्यवस्था, भवन निर्माण मानकों और अग्नि सुरक्षा प्रबंधों की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि हादसे में किसी प्रकार की लापरवाही या नियमों के उल्लंघन की भूमिका सामने आने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

बचाव अभियान में 10 पुलिसकर्मी घायल : दिल्ली पुलिस ने बताया कि राहत और बचाव कार्य के दौरान 10 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। इनमें पांच हेड कांस्टेबल और पांच कांस्टेबल शामिल हैं। ये सभी शुरुआती टीम का हिस्सा थे, जिन्होंने आग से घिरी इमारत में प्रवेश कर लोगों को बाहर निकालने का प्रयास किया। घायल पुलिसकर्मियों का अस्पताल में इलाज जारी है और उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है।

जांच जारी, मौतों की संख्या बढ़ने की आशंका : प्रशासन ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। राहत और बचाव कार्य जारी है तथा घायलों का उपचार किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि गंभीर रूप से झुलसे लोगों की स्थिति को देखते हुए मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।

प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ने जताया दुख

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण आग की घटना पर दुख जताते हुए मुआवजे की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर कहा कि दिल्ली के मालवीय नगर में आग लगने की घटना में जनहानि बेहद दुखद है। अपनों को खोने वाले सभी लोगों के प्रति उनकी गहरी संवेदना है। वे घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। अधिकारी प्रभावित लोगों को हरसंभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री आपदा राहत कोष से 2 लाख की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50 हजार रुपये दिए जाएंगे। वहीं, दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने कहा कि वे मालवीय नगर के हौज रानी स्थित एक होटल में लगी भीषण आग से मैं अत्यंत व्यथित हैं। पुलिस, नागरिक और अग्निशमन दल घटनास्थल पर मौजूद हैं और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दुख जताते हुए कहा कि घटना की सूचना मिलते ही, दिल्ली अग्निशमन सेवा, दिल्ली पुलिस, डीडीएमए, सीएटीएस एम्बुलेंस सेवा और अन्य आपातकालीन प्रतिक्रिया एजेंसियों की टीमें तुरंत सक्रिय हुईं और बचाव एवं राहत अभियान शुरू किया।

भारत के लिए नेपाल नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में अहम और प्राथमिक साझेदार

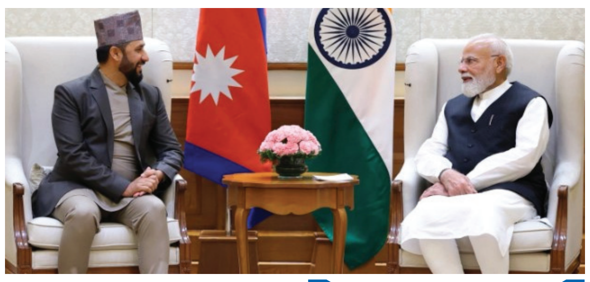

एजेंसी। नई दिल्ली

पीएम मोदी ने समृद्ध भविष्य के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई

नेपाल की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने दोनों देशों के साझा और समृद्ध भविष्य के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि रवि लामिछाने से मुलाकात का अवसर पाकर उन्हें बेहद खुशी हुई। उन्होंने कहा कि नेपाल के साथ मिलकर साझा समृद्धि और विकास के लिए काम करने की उनकी आकांक्षा का वह स्वागत करते हैं और इस सोच से पूरी तरह सहमत हैं। उन्होंने आगे कहा, भारत के लिए नेपाल उसकी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत एक अहम और प्राथमिक साझेदार है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पीएम मोदी ने अपनी नेबरहुड फर्स्ट नीति का जिक्र करते हुए कहा कि नेपाल भारत का एक प्राथमिकता वाला साझेदार है। उन्होंने भरोसा जताया कि नई सरकार के साथ मिलकर दोनों देशों के विशेष, बहुआयामी और ऐतिहासिक संबंधों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए भारत पूरी तरह प्रतिबद्ध है। भारत और नेपाल के बीच सहयोग व्यापार, ऊर्जा, कनेक्टिविटी, शिक्षा, पर्यटन और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे कई क्षेत्रों तक फैला हुआ है। भारत की पड़ोसी प्रथम नीति के तहत नेपाल के साथ घनिष्ठ सहयोग आने वाले समय में द्विपक्षीय संबंधों को और ज्यादा व्यापक और मजबूत बना सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक इससे पहले मंगलवार को लामिछाने ने बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नबीन, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी। लामिछाने ने एक्स पोस्ट पर इन मुलाकातों को बेहद अहम और उपयोगी बताया था।

संक्षिप्त समाचार

जी7 शिखर सम्मेलन में मोदी-ट्रंप मुलाकात की संभावना

नई दिल्ली। अगले सप्ताह होने वाले जी7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुलाकात की संभावना जताई जा रही है। फ्रांस की मेजबानी में 15 से 17 जून तक आयोजित होने वाले इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में दोनों नेताओं की उपस्थिति तय मानी जा रही है। ऐसे में दोनों नेताओं की मुलाकात से दोनों देशों के रिश्तों में छाई धुंध भी छंटने की उम्मीद जागी है। हालांकि अभी तक दोनों देशों की ओर से औपचारिक द्विपक्षीय बैठक की घोषणा नहीं की गई है। कूटनीतिक सूत्रों के अनुसार भारत और अमेरिका सम्मेलन के दौरान दोनों नेताओं की मुलाकात की संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं। यदि यह बैठक होती है तो पिछले कुछ महीनों से दोनों देशों के संबंधों में दिखाई दे रही दूरी को कम करने की दिशा में इसे अहम कदम माना जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति एम्मुएल मेक्रों सहित अन्य जी7 नेताओं के साथ भी अलग-अलग द्विपक्षीय बैठकें होने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की पिछली मुलाकात फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे के दौरान हुई थी। इसके बाद भारत-अमेरिका संबंधों में कुछ मुद्दों को लेकर मतभेद सामने आए।

कश्मीर में आतंकी नेटवर्क पर बड़ा प्रहार, छह जिलों में एक साथ छापेमारी

जम्मू। जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी नेटवर्क और उनके स्लीपर सेल के खिलाफ सुरक्षा एजेंसियों ने अभियान तेज कर दिया है। बुधवार को जम्मू-कश्मीर पुलिस की आतंकवाद-रोधी जांच इकाई काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर (सीआईके) ने घाटी के छह जिलों में एक साथ व्यापक छापेमारी कर संदिग्ध गतिविधियों की जांच को नई गति दी। यह कार्रवाई पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठनों और उनके स्थानीय नेटवर्क से जुड़े एक दशक पुराने मामले के सिलसिले में की गई। अधिकारियों के अनुसार हाल ही में प्राप्त खुफिया सूचनाओं, तकनीकी विश्लेषण और चल रही जांच के आधार पर आठ संदिग्ध ठिकानों की पहचान की गई थी। इन्हीं सूचनाओं के आधार पर बुधवार तड़के श्रीनगर और बांदीपोरा में दो-दो स्थानों तथा कुपवाड़ा, अनंतनाग, कुलगाम और बारामूला में एक-एक स्थान पर एक साथ छापेमारी की गई। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक यह मामला वर्ष 2015 में दर्ज किया गया था और इसका संबंध पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी संगठनों, उनके स्लीपर सेल नेटवर्क तथा जम्मू-कश्मीर में युवाओं की भर्ती, कट्टरपंथी विचारधारा के प्रसार और आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने से है। जांच में यह भी सामने आया है कि कुछ संदिग्ध गोपनीय संचार माध्यमों के जरिए पाकिस्तान में बैठे आतंकी संचालकों के संपर्क में थे।

टीएमसी के 58 एमएलए ने अलग गुट बनाया ऋतब्रत को विधायक दल का नेता चुना

एजेंसी। कोलकाता

अब ममता के पास सिर्फ 22 विधायक, बागी गुट ने पत्र में ममता को अध्यक्ष बताया

पश्चिम बंगाल में ममता की टीएमसी में फूट पड़ गई है। सोमवार को पार्टी से निकाले गए विधायक ऋतब्रत बनर्जी को पार्टी के 58 बागी एमएलए ने विधायक दल का नेता घोषित कर दिया। बुधवार को विधानसभा अध्यक्ष रथींद्र बोस से मिलकर समर्थन पत्र भी सौंपा। जावेद खान, संदीपन साहा और सिउली साहा को उपनेता बनाया गया है। वहीं अखरुज्जमान को चीफ व्हिप बनाया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बंगाल में हुए चुनाव में टीएमसी ने 80 सीटें जीतीं थीं। 58 विधायकों की बगावत के बाद अब ममता के पास सिर्फ 22 विधायक बचे हैं। हालांकि बागी गुट ने अपने पत्र में ममता बनर्जी को अब भी पार्टी अध्यक्ष बताया है, लेकिन वे अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व और विधायक दल से जुड़े फैसलों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। सोमवार को अभिषेक बनर्जी के लेटर हेड पर स्पीकर को भेजे गए पत्र में शोभनदेव को नेता विपक्ष बनाने का प्रस्ताव भेजा था। विधायक संदीपन साहा और ऋतब्रत बनर्जी ने शिकायत की थी कि इस प्रस्ताव पर उनके हस्ताक्षर फर्जी हैं। शिकायत के बाद ममता ने दोनों विधायकों को पार्टी से निकाल दिया था। पार्टी के अंदर बगावत के बीच ममता बनर्जी ने बुधवार को राज्य की सभी कमेटियों और फ्रंटल संगठनों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। पार्टी अब पूरे संगठन का पुनर्गठन करेगी।

आदिवासी समुदाय को मुख्यधारा से जोड़ने पर ही पूरा होगा विकसित भारत का लक्ष्य : राष्ट्रपति

एजेंसी। नई दिल्ली

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने बुधवार को एकीकृत जनजातीय विकास अभिकरणों (आईटीडीए) और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं (आईटीडीपी) के राष्ट्रीय सम्मेलन में कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य तभी पूरा होगा जब आदिवासी समुदाय भी विकास की मुख्यधारा से जुड़ सके। आदिवासी समाज सांस्कृतिक रूप से अत्यंत समृद्ध है लेकिन योजनाओं की जानकारी और उनतक समय पर लाभ नहीं पहुंच पाते। आदिवासी परिवार आत्मसम्मान के साथ जीवन जीते हैं और उनके कल्याण के लिए योजनाओं को बार-बार उनके दरवाजे तक ले जाना आवश्यक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने बुधवार को एकीकृत जनजातीय विकास अभिकरणों (आईटीडीए) और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं (आईटीडीपी) के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम, राज्यमंत्री दुर्गादास उइके, मंत्रालय की सचिव रंजना चोपड़ा और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। राष्ट्रपति ने कहा कि यह सम्मेलन जनजातीय परिवर्तन कारकों का सम्मेलन है। आप सब पर यह जिम्मेदारी है कि जनजातीय समुदाय के कल्याण और विकास कार्यक्रमों को उनके गांव और घर तक पहुंचाएं। ऐसा करने से जनजातीय समुदाय के भाई-बहनों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। राज्य और परियोजना स्तर पर काम करने वाले सभी लोग जब एक बड़े उद्देश्य के साथ विचार-विमर्श करेंगे तो अनेक उपयोगी समाधान सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि आदिवासी समुदाय के गांव और बस्तियां दूरदराज के इलाकों में जंगलों और पहाड़ों में स्थित हैं। ऐसे क्षेत्रों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना अधिकारियों का कर्तव्य है। प्रधानमंत्री जन योजना के तहत 20,000 से अधिक आदिवासी गांवों तक विकास कार्यक्रम पहुंचाने का लक्ष्य है। विशेष रूप से पीबीटीजी समूहों को घर, जमीन और आजीविका उपलब्ध कराना आवश्यक है। राष्ट्रपति ने कहा कि आईटीडीए और आईटीडीपी जैसी संस्थाओं का गठन इसी उद्देश्य से किया गया है ताकि आदिवासी समुदाय को विशेष ध्यान देकर आगे बढ़ाया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रत्येक गर्भवती मां को पोषण, प्रत्येक बच्चे को शिक्षा और प्रत्येक युवा को गरिमापूर्ण आजीविका उपलब्ध कराना सभी एजेंसियों का दायित्व है। राष्ट्रपति ने कहा कि आदिवासी समुदाय के पास पारंपरिक ज्ञान और कौशल है, जिसे आधुनिक विकास प्रयासों के साथ जोड़ना चाहिए।

खान सर के कोचिंग सेंटर पर हमले के बाद भड़के छात्रों ने किया प्रदर्शन

पटना। पटना में चर्चित शिक्षक खान सर के कोचिंग सेंटर के बाहर हुई तोड़फोड़, मारपीट और कथित फायरिंग की घटना के बाद छात्रों का आक्रोश सड़क पर दिखाई दिया। बुधवार सुबह सैकड़ों छात्र-छात्राएं खान सर के घर के बाहर सड़क पर बैठकर प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शन के दौरान इलाके में भारी भीड़ जमा हो गई, जिसके कारण सड़क पर लंबा जाम लग गया और यातायात व्यवस्था प्रभावित हो गई। स्थिति को देखते हुए मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया। हालांकि खान सर ने छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील की। प्रदर्शन के दौरान सामने आए वीडियो में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं सड़क पर बैठे नजर आए। सभी घटना को लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे थे और मामले में सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे थे। इस बीच खान सर अपने घर की बालकनी में आए और छात्रों से कई बार हाथ जोड़कर प्रदर्शन समाप्त करने तथा घर लौट जाने की अपील की। उन्होंने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि पुलिस पूरी रात कोचिंग सेंटर के बाहर मौजूद रही और कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है।

संविधान की प्रति हाथ में लेकर शिवकुमार ने कर्नाटक सीएम पद की ली शपथ

बेंगलुरु। कर्नाटक की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत करते हुए डीके शिवकुमार ने बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान उन्होंने हाथ में संविधान की प्रति लेकर पद और गोपनीयता की शपथ ली। उनके साथ 13 अन्य विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ग्रहण की। इस अवसर पर कांग्रेस नेतृत्व ने इसे राज्य के विकास और सुशासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। शपथ ग्रहण समारोह में जी परमेश्वर ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इससे पहले राज्य में एक से अधिक उपमुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चाएं चल रही थीं, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व ने फिलहाल परमेश्वर को ही यह जिम्मेदारी सौंपी है। नई मंत्रिपरिषद में कई वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं को शामिल किया गया है। मंत्री पद की शपथ लेने वालों में के.एच. मुनियप्पा, के.जे. जॉर्ज, एम.बी. पाटिल, रामलिंगा रेड्डी, सतीश जारकीहोली, कृष्णा बायरेगौड़ा, प्रियंक खड़गे, यू.टी. खादर, ईश्वर खंड्रे, यतींद्र सिद्धारमैया, यरथी सुरेश और शरण प्रकाश पाटिल सहित अन्य शामिल हैं। नई सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के पुत्र यतींद्र सिद्धारमैया और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र प्रियंक खड़गे को भी मंत्री बनाया गया है।

चार राज्यों में 24 हजार करोड़ की प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी

एजेंसी। नई दिल्ली

केंद्र सरकार ने सड़क संपर्क, तटीय संपर्क और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना और बिहार में महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। लगभग 24 हजार करोड़ की इन परियोजनाओं से यातायात सुगम होगा और औद्योगिक तथा पर्यटन गतिविधियों को गति मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने बुधवार को विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की। केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में इन फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में एनएच-347बी के हिवारखेड़ी-रोशनी-आशापुर-रुधी खंड में मौजूदा मध्यवर्ती लेन को पक्के शोल्डर मानक के साथ दो लेन में अपग्रेड किया जाएगा। इसके अलावा देशगांव-जुलवानिया खंड में मौजूदा दो लेन मार्ग को चार लेन तक चौड़ा किया जाएगा। 233.653 किमी की इस परियोजना पर 4415.60 करोड़ रुपये का खर्च होने का अनुमान है। परियोजना के तहत खरगोन तक 16.20 किमी का ग्रीनफिल्ड बायपास भी निर्मित किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163.18 किलोमीटर लंबी नई तटीय राजमार्ग परियोजना को भी मंजूरी दी है। इस परियोजना की कुल लागत 8,300.79 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है। इसके निर्माण से तटीय क्षेत्रों में संपर्क बेहतर होगा तथा बंदरगाह आधारित आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा। इस परियोजना से 9 आर्थिक और 5 रसद केंद्रों को जोड़ेगा। इससे रामेश्वरम और पारादीप के बीच यात्रा समय में ढाई घंटे की कमी आएगी। तेलंगाना में एनएच-63 के आर्मूर-जगतियाल-मंचरियाल खंड तथा एनएच-563 के जगतियाल-करीमनगर खंड को चार लेन मानक तक विकसित किया जाएगा। 190.76 किलोमीटर लंबी इस परियोजना पर 7,597.16 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। इससे राज्य के उत्तरी और मध्य क्षेत्रों में यातायात क्षमता बढ़ेगी तथा माल परिवहन अधिक सुगम होगा। परियोजना से आर्मूर से मंचेरियल के बीच यात्रा समय में डेढ घंटा और जगतियाल से करीमनगर के बीच लगभग 45 मिनट की कमी आएगी। इसके अलावा बिहार में एनएच-31 और एनएच-231 के खगड़िया-पूर्णिया खंड को टोल आधारित बीओटी मॉडल पर चार लेन मानक में अपग्रेड करने को मंजूरी दी गई है।

ज्वलंत मुद्दा | संपादकीय

रिजर्व बैंक ने खोली अर्थव्यवस्था के ढोल की पोल

भारतीय रिजर्व बैंक की हालिया रिपोर्ट और देश की आर्थिक स्थिति से जुड़े विभिन्न संकेतक यह सवाल खड़ा कर रहे हैं। आखिर भारत की अर्थव्यवस्था किस दिशा में जा रही है? पिछले कुछ वर्षों में सरकार और उसके समर्थकों द्वारा भारत को दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बताया जा रहा था। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में दिखाई देने वाली वास्तविकताएं एक अलग कहानी कह रही हैं। भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए विदेशों पर निर्भर होता जा रहा है। एक समय देश अपनी जरूरत का लगभग 18 प्रतिशत कच्चा तेल और गैस स्वयं उत्पादित कर लेता था। शेष 82 प्रतिशत आयात करना पड़ता था। अब आयात पर निर्भरता और बढ़ गई है। कच्चे तेल, गैस, उर्वरक और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च हो रही है। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, औद्योगिक सामान और अनेक उपभोक्ता वस्तुओं के लिए भारत की विदेशों पर निर्भरता बढ़ती जा रही है।

आयात और निर्यात के बीच बढ़ता असंतुलन चिंता का विषय है। यदि किसी देश का आयात लगातार निर्यात से अधिक रहेगा तो अंततः विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ना स्वाभाविक है। भारत का व्यापार घाटा साल दर साल लगातार बढ़ रहा है। विदेशी मुद्रा अर्जित करने में वृद्धि दिखाई नहीं दे रही। जिस गति से आयात बढ़ा है, उस अनुपात में निर्यात नहीं बढ़ पाया है। इसका सीधा असर रुपये की मजबूती पर पड़ रहा है। डॉलर और युआन जैसी मुद्राओं के मुकाबले रुपया लगातार गिर रहा है। जिसके कारण आयातित वस्तुओं की कीमत बढ़ रही है। पिछले वर्षों में सरकार ने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियान चलाए, आलोचकों का मानना है, इन अभियानों का प्रभाव औद्योगिक उत्पादन और रोजगार सृजन के रूप में कहीं पर दिखाई भी दिए तो वो भी बहुत नीचे स्तर पर हैं। भारत में उत्पादन बढ़ाने के बजाय आयात आधारित उपभोग अर्थव्यवस्था को सरकारी नीतियों से बढ़ावा मिला है। अर्थव्यवस्था को लेकर चिंता का एक दूसरा कारण देश में बढ़ता कर्ज है।

केंद्र और राज्य सरकारें लगातार उधार लेकर खर्च बढ़ा रही हैं। निजी क्षेत्र और आम नागरिकों के ऊपर कर्ज बढ़ रहा है। गोल्ड लोन, व्यक्तिगत ऋण और क्रेडिट कार्ड आधारित उधारी में तेजी से वृद्धि हुई है। जब किसी अर्थव्यवस्था में विकास का आधार उत्पादन और आय की बजाय कर्ज बनने लगे, तो यह स्थिति लंबे समय तक टिकाऊ नहीं मानी जाती। जब खर्च करने के लिये पैसे नहीं होंगे, तो आर्थिक विकास कैसे संभव है। नोटबंदी, जीएसटी और कोरोना महामारी के प्रभावों पर भी गंभीर चर्चा आवश्यक है। इन तीनों घटनाओं ने छोटे और मध्यम उद्योगों को गहरा झटका दिया। असंगठित क्षेत्र, जो भारत में रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत था, आज भी वह उबर नहीं पाया है। बेरोजगारी और महंगाई ने आम परिवारों की आर्थिक स्थिति को कमजोर किया है। लोगों की आय कई वर्षों से सीमित है। आय की तुलना में अधिक तेजी से जीवन-यापन का खर्च बढ़ रहा है।

शेयर बाजार को लंबे समय तक भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती का प्रतीक बताया जाता रहा। पिछले कुछ महीनों में विदेशी निवेशकों द्वारा भारी मात्रा में पूंजी निकासी की जा रही हैं। यदि विदेशी निवेश कम होता है, घरेलू उत्पादन नहीं बढ़ता, तो आर्थिक विकास की रफ्तार पर इसका असर पड़ना स्वाभाविक है। दूसरी ओर एशिया के कई शेयर बाजार अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन करते दिखाई दे रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों ने भी भारत की चुनौतियां बढ़ा दी हैं। पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव, कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता भारत जैसे आयात-निर्भर देशों पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव डाल रही है।

सैयद जकी हैदर | सम्पदक/प्रकाशक
MOBE NO.9911371802
EMAIL. SYEDZAKIHAIDER786@GMAIL.COM

संक्षिप्त समाचार

एक ही कार से कैबिनेट बैठक में पहुंचे तीन कैबिनेट मंत्री, शिवराज सिंह बोले- पेट्रोलियम पदार्थों की बचत करना मकसद

लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली। पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोलियम उत्पादों की बचत की अपील पर बुधवार को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और केंद्रीय कोयला एवं खनन मंत्री जी किशन रेड्डी एक ही कार से (कार पूलिंग करके) कैबिनेट बैठक में पहुंचे।केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सीआर पाटिल, जी किशन रेड्डी और उन्होंने कार पूलिंग करके यात्रा की। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पूरे देश से अनावश्यक पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने का आह्वान किया है और इस पर देशभर में अमल किया जा रहा है। मंत्रिमंडल के सहयोगी होने के नाते उन्होंने भी कार पूलिंग का निर्णय लिया। चौहान ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में यह आवश्यक है कि पेट्रोल और डीजल की अनावश्यक खपत को कम किया जाए। जितना संभव हो सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए और ऊर्जा बचत के उपायों को अपनाना चाहिए।

आआपा ने निगमायुक्त को लिखा पत्र, साकेत भवन हादसे में निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग

लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली। साकेत के सैदुलाजाब इलाके में पांच मंजिला इमारत गिरने की घटना को लेकर दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में नेता प्रतिपक्ष और आम आदमी पार्टी (आआपा) के नेता अंकुश नारंग ने बुधवार को निगमायुक्त को पत्र लिखकर निष्पक्ष जांच और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।अंकुश नारंग ने पत्र में लिखा कि साकेत भवन हादसा कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि निगम के भ्रष्टाचार, लापरवाही और अधिकारियों की मिलीभगत का नतीजा है।उन्होंने कहा कि आज निगमायुक्त को पत्र लिखकर इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच, दोषी अधिकारियों की जवाबदेही तय कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई, पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा तथा पूरे दिल्ली में जर्जर और अवैध इमारतों का सर्वे कराने की मांग की।नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि स्थानीय लोगों की शिकायतों और अवैध निर्माण की जानकारी होने के बावजूद कार्रवाई नहीं की गई, जिसका खामियाजा आज निर्दोष लोगों को अपनी जान देकर भुगतना पड़ा। अंकुश नारंग ने कहा कि दिल्लीवासियों की जान से खिलवाड़ करने वाले भ्रष्ट अधिकारियों और उन्हें संरक्षण देने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए।

आईआईएमसी में एमए और पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू

लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली। भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए एमए और पीजी डिप्लोमा कार्यक्रमों में प्रवेश हेतु ई-काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक अभ्यर्थी 7 जून तक ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं, जबकि प्रथम सीट आवंटन 9 जून को जारी किया जाएगा।आईआईएमसी ने इस वर्ष तीन नए एमए कार्यक्रम की शुरुआत की है जिसमें हेल्थ कम्युनिकेशन, मीडिया एंड कम्युनिकेशन गवर्नेंस तथा कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन एंड ब्रांड मैनेजमेंट शामिल हैं। इसके साथ ही संस्थान अब अपने छह परिसरों में कुल छह एमए कार्यक्रम संचालित करेगा।बुधवार को संस्थान के प्रवेश प्रभारी एवं परीक्षा नियंत्रक प्रो. राकेश कुमार गोस्वामी ने बताया कि सभी एमए और पीजी डिप्लोमा कार्यक्रमों में प्रवेश, केवल ई-काउंसलिंग के माध्यम से किया जाएगा। संस्थान के चार पारंपरिक पीजी डिप्लोमा कार्यक्रम- अंग्रेजी पत्रकारिता, हिंदी पत्रकारिता, रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता तथा विज्ञापन एवं जनसंपर्क भी इस वर्ष उपलब्ध रहेंगे।एमए कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों के पास न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक डिग्री और सीयूईटी-पीजी (सीओक्यूपी17) में वैध स्कोर होना आवश्यक है। वहीं, पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए स्नातक डिग्री के साथ सीयूईटी-पीजी स्कोर अनिवार्य है। चयनित अभ्यर्थियों को प्रवेश के लिए 20 हजार रुपये की सीट स्वीकृति शुल्क जमा करनी होगी। संस्थान ने अभ्यर्थियों को आवेदन से पूर्व प्रवेश सूचना और प्रॉस्पेक्टस ध्यानपूर्वक पढ़ने तथा अपनी प्राथमिकताएं सोच-समझकर भरने की सलाह दी है।

तीन हाई कोर्ट में जज की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 10 नामों की अनुशंसा की

लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने तीन उच्च न्यायालय में जज के रुप में नियुक्त करने के लिए 10 नामों की अनुशंसा की है। कॉलेजियम ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दो एडिशनल जजों को स्थायी जज के रुप में नियुक्त करने की अनुशंसा की है। कॉलेजियम की 02 जून को हुई बैठक में इस आशय की सिफारिश की गई। कॉलेजियम ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के लिए 06, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के लिए 01 और हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के लिए 03 जजों को नियुक्त करने की सिफारिश की है। कॉलेजियम ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के जज के रुप में जिन नामों की अनुशंसा की है उनमें राघवेंद्र सीताराम श्रीवास्तव, हेमा कुलकर्णी, एस रंगाराव, टीपी विवेकानंद, बी प्रमोद और एचजीएस भूषण शामिल हैं। कॉलेजियम ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के जज के रुप में नियुक्त करने के लिए वकील अमित लाहोटी के नाम की अनुशंसा की है। इसी तरह हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के जज के रुप में जिन नामों की अनुशंसा की गई है उनमें चिराग भानु सिंह, भूपेश शर्मा और योगेश जसवाल शामिल हैं। कॉलेजियम ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के एडिशनल जजों जस्टिस हरमीत सिंह ग्रेवाल और जस्टिस दीपिंदर सिंह नालवा को स्थायी जज के रुप में नियुक्त करने की अनुशंसा की है।

जयराम रमेश ने ग्रेट निकोबार परियोजना में पर्यावरणीय नियमों की अनदेखी का लगाया आरोप

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। पूर्व केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री और कांग्रेस महासचिव (संचार) जयराम रमेश ने ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना को लेकर केंद्र सरकार पर पर्यावरणीय नियमों और प्रक्रियाओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव को फिर पत्र लिख कर कहा कि परियोजना के पर्यावरणीय प्रभावों का आकलन करते समय कानून के शब्द और भावना दोनों स्तरों पर पूर्ण अनुपालन नहीं किया गया। उन्होंने परियोजना के लिए किए गए पर्यावरण प्रभाव आकलन अध्ययनों, मंजूरी प्रक्रिया और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) द्वारा गठित उच्चाधिकार समिति की रिपोर्ट को लेकर कई सवाल उठाए।रमेश ने बुधवार को लिखे पत्र में कहा कि मार्च 2022 की पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट में स्वयं यह स्वीकार किया गया था कि अध्ययन केवल एक प्रारंभिक और त्वरित आकलन था। पर्यावरण मंत्रालय ने भी यह माना कि परियोजना की पर्यावरणीय मंजूरी व्यापक ईआईए अध्ययनों पर आधारित नहीं थी, जिनमें तीन मौसमों के प्राथमिक आंकड़ों का उपयोग किया जाता है। परियोजना से संबंधित विभिन्न अध्ययन केवल कुछ सप्ताह के दौरान जुटाए गए आंकड़ों पर आधारित थे, जबकि इतने बड़े और संवेदनशील क्षेत्र के लिए विस्तृत और बहु-मौसमी अध्ययन आवश्यक थे।उन्होंने कहा कि मंत्रालय द्वारा पुराने और उपलब्ध आंकड़ों के उपयोग का तर्क दिया जा रहा है, जबकि परियोजना स्थल और उसके प्रभाव क्षेत्र से एकत्र किए गए प्राथमिक आंकड़ों का कोई विकल्प नहीं हो सकता। किसी भी बड़े विकास परियोजना के लिए परियोजना-विशेष अध्ययन और प्रत्यक्ष आंकड़ों का संग्रह पर्यावरणीय मूल्यांकन का मूल आधार होना चाहिए।रमेश ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण के फैसलों का जिक्र करते हुए कहा कि तीन अप्रैल 2023 के आदेश में स्वयं अधिकरण ने परियोजना को दी गई पर्यावरणीय मंजूरी में कुछ अनुत्तरित कमियों का उल्लेख किया था। अधिकरण ने व्यापक पर्यावरण प्रभाव आकलन की आवश्यकता सहित कई मुद्दों पर पुनर्विचार का निर्देश दिया था। उन्होंने कहा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर की रिपोर्ट में गलाथिया खाड़ी के पूर्वी हिस्से के कई तटीय क्षेत्रों में कटाव का संकेत दिया गया है। द्वीप तटीय विनियमन क्षेत्र नियम-2019 के तहत तटीय कटाव वाले क्षेत्रों में बंदरगाह परियोजनाओं के लिए व्यापक पर्यावरणीय अध्ययन आवश्यक हैं। ऐसी स्थिति में विभिन्न मौसमों को ध्यान में रखते हुए विस्तृत पर्यावरण प्रभाव आकलन क्यों नहीं कराया गया।कांग्रेस सांसद ने कहा कि परियोजना के लिए पर्यावरणीय अध्ययन तैयार करने वाले और उनकी समीक्षा करने वाले संस्थान एक ही प्रशासनिक ढांचे के अंतर्गत आते हैं, जिससे निष्पक्षता को लेकर सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने पर्यावरण मंत्रालय के 2009 के कार्यालय ज्ञापन और बंदरगाह एवं हार्बर परियोजनाओं के लिए जारी ईआईए मार्गदर्शिका का भी जिक्र किया, जिनमें द्वीपीय क्षेत्रों की बंदरगाह परियोजनाओं के लिए व्यापक पर्यावरण प्रभाव आकलन और विभिन्न मौसमों में आंकड़े एकत्र करने की आवश्यकता बताई गई है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने जयराम रमेश के पिछले पत्र में लगाए आरोपों के जवाबी पत्र में सारे आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना का पर्यावरणीय मूल्यांकन पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना 2006, द्वीप तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना 2019 और अन्य लागू प्रावधानों के अनुरूप व्यापक एवं बहुस्तरीय तरीके से किया गया है। परियोजना से जुड़े पर्यावरणीय और जैव विविधता संबंधी मुद्दों की वैधानिक मूल्यांकन तथा न्यायिक समीक्षा प्रक्रिया के दौरान विस्तार से जांच की जा चुकी है। ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना लगभग 166 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में प्रस्तावित है। इसमें एक ट्रांसशिपमेंट कंटेनर बंदरगाह, अंतरराष्ट्रीय स्तर का द्वैध उपयोग हवाई अड्डा, ऊर्जा अवसंरचना तथा हरित तटीय शहर विकसित किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना के लिए लगभग 13 हजार हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित होने का अनुमान है।

माय भारत ने शुरू किया 'विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2026', सीमावर्ती गांवों में युवा भागीदारी को मिलेगा बढ़ावा

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के युवा कार्य विभाग के अंतर्गत मेरा युवा भारत (माय भारत) ने विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (वीवीवीपी) 2026 के पहले चरण की शुरुआत कर दी है। इस पहल का उद्देश्य सीमावर्ती गांवों में युवाओं की सक्रिय भागीदारी बढ़ाना, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना और सतत विकास को प्रोत्साहित करना है। कार्यक्रम को दो चरणों में लागू किया जाएगा। इसके तहत देशभर से चुने गए 500 एमवाई भारत स्वयंसेवक सीमावर्ती क्षेत्रों में एक सप्ताह तक रहकर स्थानीय समुदायों के साथ काम करेंगे। इन स्वयंसेवकों का चयन देशव्यापी ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता के माध्यम से किया गया, जिसमें 3 लाख से अधिक युवाओं ने भाग लिया। पहले चरण में 250 स्वयंसेवक लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के 43 सीमावर्ती गांवों में काम करेंगे, जबकि शेष 250 स्वयंसेवक इसी महीने दूसरे चरण में 50 गांवों में गतिविधियों में भाग लेंगे।यह कार्यक्रम युवाओं को सीमावर्ती क्षेत्रों के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन को करीब से समझने का अवसर देगा। स्वयंसेवक गांवों के निवासियों, पंचायत संस्थाओं, स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा बलों के साथ संवाद करेंगे तथा इन क्षेत्रों के विकास और रणनीतिक महत्व को जानेंगे।सात दिवसीय कार्यक्रम को कई विषयों पर आधारित किया गया है, जिनमें सीमावर्ती जागरूकता, सांस्कृतिक आदान-प्रदान, सामुदायिक जीवन, सुशासन, सामाजिक-आर्थिक अध्ययन, ग्राम विकास योजना, स्वयंसेवा और राष्ट्रीय एकीकरण शामिल हैं।स्वयंसेवक घर-घर सर्वेक्षण करेंगे, ग्राम सभा गतिविधियों में भाग लेंगे, स्वच्छता और पर्यावरण अभियानों में सहयोग देंगे और गांवों में विकास की संभावनाओं की पहचान करेंगे।

कार्यक्रम का एक प्रमुख हिस्सा 'नेशन फर्स्ट चैलेंज' अभियान भी है। इसके तहत स्वयंसेवक पांच प्रमुख विषयों पर जागरूकता फैलाएंगे—

स्वदेशी उत्पादों को अपनाना

स्वस्थ भोजन पद्धति को बढ़ावा देना

सार्वजनिक परिवहन और ईंधन संरक्षण

प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन

स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देना

इस कार्यक्रम को गृह मंत्रालय और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के सहयोग से लागू किया जा रहा है। इसका उद्देश्य विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को युवाओं की भागीदारी के माध्यम से मजबूत करना है। कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष, नोडल अधिकारी, ग्राम कार्ययोजना, प्रशिक्षण सत्र और अन्य व्यवस्थाएं पहले से तैयार की गई हैं।

मनोज तिवारी के आवास पर आआपा विधायक संजीव झा का समर्थकों के साथ हंगामा, सांसद ने लगाए आरोप

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। दिल्ली के जगतपुर गांव में ओ-जोन को लेकर प्रशासन की कार्रवाई के मामले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद मनोज तिवारी के आवास पर आम आदमी पार्टी (आआपा) विधायक संजीव झा के समर्थकों के साथ मंगलवार देर रात पहुंचने के बाद हंगामा शुरू हो गया। आआपा विधायक और उनके समर्थकों को पुलिस ने वहां से हटाया।सांसद मनोज तिवारी ने यहां पत्रकारों को संबोधित करते हुए आज कहा कि बुराड़ी के आआआ विधायक संजीव झा और झड़ौदा पार्षद गगन चौधरी खुद सरकारी जमीन पर किए गए कब्जे को बचाने के लिए जनता को भ्रमित कर उन्हें भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि विधायक संजीव झा और पार्षद गगन चौधरी उनके घर आए थे। सांसद ने दावा किया कि अवैध रूप से हथियाई गई जमीन को बचाने के लिए इन दोनों ने साजिश रची और ग्रामीणों को गुमराह करके सरकार को बदनाम कर रहे हैं।सांसद मनोज तिवारी ने स्पष्ट कहा कि ओ-जोन नियमों के तहत उन क्षेत्रों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जो पहले से ही तटबंध के पीछे हैं और यमुना की तरफ नहीं हैं, जहां पिछले 25 से 30 वर्षों से तटबंध का बाढ़ का पानी नहीं पहुंचा है।आआपा विधायक संजीव झा ने आज सोशल मीडिया एक्स पर वीडियो जारी करते हुए कहा कि कल जगतपुर गांव में ओ-जोन के नाम पर तोड़फोड़ हुई, जबकि सांसद मनोज तिवारी ने कहा था कि कोई तोड़फोड़ नहीं होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि मंगलवार को गांव के सम्मानित पंचों और ग्रामीणों के साथ जब वे समाधान पूछने सांसद के पास गए तो जवाब देने के बजाय उन्हें और आआपा पार्षद को गिरफ्तार करवा दिया गया।संजीव झा ने एक अन्य वीडियो जारी करते हुए कहा कि आज सुबह-सुबह सांसद ने पुलिस भेज कर उन्हें घर से दोबारा गिरफ्तार करा दिया है। दिल्ली पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर बुराड़ी थाने ले जा रही है। इसकी तस्वीर भी उन्होंने एक्स पर साझा की।

दिल्ली में आग ही आगः हादसे बढ़ते जा रहे, जिम्मेदार कौन?

लोकतंत्र की शान, दिल्ली ब्यूरो चीफ सना खान की रिपोर्ट

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में लगातार हो रही आग की घटनाओं ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हाल ही में शास्त्री पार्क फर्नीचर मार्केट में लगी भीषण आग के बाद मालवीय नगर के एक होटल में हुए अग्निकांड ने कई लोगों की जान ले ली और प्रशासनिक तैयारियों की पोल खोल दी। विशेषज्ञों के अनुसार अवैध निर्माण, जर्जर बिजली व्यवस्था, अग्नि सुरक्षा नियमों की अनदेखी और नियमित निरीक्षण का अभाव ऐसे हादसों की बड़ी वजह हैं। कई बाजारों, होटलों और व्यावसायिक परिसरों में फायर सेफ्टी व्यवस्था केवल कागजों तक सीमित दिखाई देती है।

जिम्मेदार कौन? इन हादसों की जिम्मेदारी केवल भवन मालिकों की नहीं, बल्कि संबंधित विभागों, स्थानीय प्रशासन और निगरानी एजेंसियों की भी है। हर बड़ी दुर्घटना के बाद जांच और मुआवजे की घोषणा तो होती है, लेकिन स्थायी समाधान नजर नहीं आता।

सरकार की जिम्मेदारी–सरकार का दायित्व है कि अग्नि सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए, अवैध निर्माणों पर कार्रवाई हो, फायर विभाग को आधुनिक संसाधन उपलब्ध कराए जाएं और संवेदनशील क्षेत्रों का नियमित सुरक्षा ऑडिट कराया जाए।

निष्कर्ष- मुंडका, अनाज मंडी, बवाना, शास्त्री पार्क और अब मालवीय नगर जैसे अग्निकांड यह संकेत दे रहे हैं कि यदि सुरक्षा मानकों को लेकर ठोस कदम नहीं उठाए गए तो ऐसी त्रासदियां भविष्य में भी दोहराई जाती रहेंगी। अब समय आ गया है कि जवाबदेही तय हो और सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए।

मालवीय नगर अग्निकांड स्थल पहुंचे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा- ठोस कदम उठाने की जरूरत

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने मालवीय नगर अग्निकांड के बाद घटनास्थल पर बुधवार को पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि दिल्ली में नियमों की अनदेखी के कारण इस तरह के हादसे बार-बार हो रहे हैं और निर्दोष लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। यह जानकारी उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर साझा करते हुए कहा कि सरकार और प्रशासन को इस बार सिर्फ खानापूर्ति करने के बजाय सुरक्षा व्यवस्था की कमियों को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी दो-तीन बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं, चाहे वह पालम त्रासदी हो या विवेक विहार की घटना। वहां भी स्थिति एक जैसी थी। दावे किए गए कि एयर कंडीशनर फट गया था या किसी अन्य कारण से आग लगी थी, लेकिन आज तक आग लगने के सटीक कारणों का पता नहीं चल पाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सरकार को बार-बार चेतावनी दी है और सतर्क किया है।उन्होंने कहा कि विवेक विहार घटना के बाद और फिर पालम घटना के बाद इन चिंताओं को उठाया गया। कांग्रेस के बार-बार ऐसे गंभीर मुद्दे उठाने के बाद भी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया।

मालवीय नगर होटल अग्निकांड पर कार्रवाई के निर्देश, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगाः आशीष सूद

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। दिल्ली के मालवीय नगर में बुधवार सुबह फ्लोरिश स्टे बीएंडबी रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई। इसमें कई अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस घटना के बाद दिल्ली सरकार के गृह मंत्री आशीष सूद और विधायक सतीश उपाध्याय ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया।घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद मंत्री आशीष सूद ने कहा कि आग से इमारत पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। उन्होंने बताया कि संबंधित अधिकारी सभी आवश्यक दस्तावेज एकत्र कर रहे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि इमारत के पास वैध अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) था या नहीं, होटल और रेस्तरां संचालन की अनुमति ली गई थी या नहीं तथा बेड एंड ब्रेकफास्ट (बीएनबी) के रूप में संचालित किए जा रहे कमरों के लिए आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त थीं या नहीं। आशीष सूद ने कहा कि इस घटना के लिए जिम्मेदार इमारत मालिक और किसी भी प्रकार की लापरवाही में शामिल लोगों की पहचान पुलिस जांच के माध्यम से की जाएगी और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस घटना में जांच के लिए पुलिस टीमों को पहले ही भेज दिया गया है।आशीष सूद ने कहा कि जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) की निगरानी में नगर निगम, अग्निशमन विभाग, बिजली विभाग और जल विभाग सहित सभी संबंधित एजेंसियों को पूरे क्षेत्र में व्यापक निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा या नियामकीय मानकों का उल्लंघन करने वाली किसी भी इमारत को बख्शा नहीं जाएगा और उल्लंघन पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।मंत्री ने कहा कि सरकार यह जांच कर रही है कि इमारत को आवश्यक एनओसी प्राप्त थी या नहीं और बीएनबी संचालन के लिए सभी जरूरी अनुमति ली गई थीं या नहीं। किसी भी अवैध निर्माण और दोषी पाए गए व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस दर्दनाक घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा नेता दिनेश शर्मा ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों ने मामले का संज्ञान लिया है और घटना की गंभीरता से जांच की जा रही है।साथ ही सांसद मनोज तिवारी ने इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताते हुए कहा कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार होटल के रेस्तरां क्षेत्र में भीषण आग लगी थी। उन्होंने कहा कि 21 लोगों की मौत कैसे हुई, यह जांच का विषय है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार लगातार व्यवस्थागत कमियों को दूर करने और सुरक्षा मानकों को मजबूत करने के प्रयास कर रही है।

एनडीटीएल और एसजीटी विश्वविद्यालय के बीच समझौता, खेल विज्ञान और एंटी-डोपिंग शोध को मिलेगा बढ़ावा

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (एनडीटीएल), नई दिल्ली और श्री गुरु गोविंद सिंह त्रिशताब्दी (एसजीटी) विश्वविद्यालय, गुरुग्राम के बीच खेल विज्ञान, एंटी-डोपिंग अनुसंधान और खिलाड़ियों के कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।भारत सरकार के स्वायत्त निकाय एनडीटीएल और एसजीटी विश्वविद्यालय के बीच यह साझेदारी खेलों में वैज्ञानिक शिक्षा, स्वच्छ खेल संस्कृति और शोध को नई दिशा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इस अवसर पर दोनों संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे और खेलों में नैतिकता, वैज्ञानिक उत्कृष्टता तथा खिलाड़ियों के समग्र विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।समझौते के तहत छात्रों और शिक्षकों को उन्नत प्रशिक्षण, इंटर्नशिप, शोध परियोजनाओं, विशेषज्ञ व्याख्यान और अत्याधुनिक प्रयोगशाला प्रणालियों का अनुभव प्राप्त होगा। इसके साथ ही विश्लेषणात्मक परीक्षण, एंटी-डोपिंग विज्ञान, फोरेंसिक विश्लेषण और स्वास्थ्य परीक्षण से जुड़े क्षेत्रों में संयुक्त शोध एवं ज्ञान आदान-प्रदान कार्यक्रम भी संचालित किए जाएंगे।एनडीटीएल के निदेशक डॉ. पी. एल. साहू ने इस साझेदारी को वैज्ञानिक अनुसंधान और कुशल मानव संसाधन निर्माण की दिशा में अहम बताया। उन्होंने कहा कि एनडीटीएल का उद्देश्य हमेशा भारत में खेलों की शुचिता बनाए रखना रहा है और विश्वविद्यालय के साथ यह सहयोग भविष्य के वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और स्वास्थ्य विशेषज्ञों को तैयार करने में मदद करेगा।एसजीटी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. हेमंत वर्मा ने कहा कि यह समझौता विश्वविद्यालय के लिए गर्व का विषय है और यह नवाचार, अनुभव आधारित शिक्षा तथा शोध आधारित शिक्षण की उनकी सोच के अनुरूप है। इससे छात्रों को आधुनिक तकनीकों और प्रयोगशाला प्रक्रियाओं का व्यावहारिक अनुभव मिलेगा।एनडीटीएल की संचालन एवं सामान्य निकाय के सदस्य तथा प्रख्यात वैज्ञानिक प्रो. वाई. के. गुप्ता ने कहा कि यह साझेदारी शैक्षणिक सहयोग, संयुक्त अनुसंधान, संकाय विकास कार्यक्रम और छात्र इंटर्नशिप जैसे कई नए अवसर पैदा करेगी। दोनों संस्थानों ने इस समझौते के माध्यम से वैज्ञानिक ज्ञान, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कुशल स्वास्थ्य एवं शोध कार्यबल के विकास के लिए मिलकर कार्य करने की प्रतिबद्धता दोहराई।

संक्षिप्त समाचार

संभल के विकास इतिहास में दर्ज हुआ ईओ डॉ. मणि भूषण तिवारी का कार्यकाल, विदाई पर उमड़ा सम्मान और आभार

लोकतंत्र की शान , सैय्यद कुमैल ज़ैदी , संभल। नगर पालिका परिषद संभल में अपने कार्यकाल के दौरान विकास कार्यों को नई दिशा देने वाले अधिशासी अधिकारी डॉ. मणि भूषण तिवारी का स्थानांतरण उन्नाव जनपद में अधिशासी अधिकारी के रूप में किया गया। उनके विदाई अवसर पर नगर पालिका परिसर में भावुक और सम्मानपूर्ण माहौल देखने को मिला। उनके कार्यकाल को संभल के विकास इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय माना जा रहा है। उनके नेतृत्व में शहर में सड़क चौड़ीकरण, अतिक्रमण हटाओ अभियान, स्वच्छता व्यवस्था में सुधार तथा धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य संपन्न हुए। इन कार्यों से नगर की छवि और व्यवस्था दोनों में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला। डॉ. तिवारी की कार्यशैली को ईमानदारी, पारदर्शिता और जनहित के प्रति समर्पण के लिए सराहा गया। उनके नेतृत्व में चलाए गए स्वच्छता अभियानों और विकास कार्यों ने संभल को एक नई पहचान दी। विदाई समारोह के अवसर पर नगर पालिका परिषद संभल का समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। सभी कर्मचारियों ने उन्हें भावभीनी विदाई दी और उनके साथ कार्य करने के अनुभव को प्रेरणादायक बताया। इस दौरान माहौल भावुक हो गया और कई लोगों ने उनके योगदान को याद करते हुए आभार व्यक्त किया। स्थानीय नागरिकों और जनप्रतिनिधियों ने भी उनके कार्यकाल की सराहना करते हुए कहा कि जब भी संभल के विकास की बात होगी, उनका नाम सम्मान के साथ लिया जाएगा। कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

रम्पुरा के राशन डीलर पर बढ़ती शिकायतें, फिर भी प्रशासन मौन- आखिर पीड़ित जाएं तो कहां जाएं?

आयुष मान कार्ड में बड़ा घोटाले होने के आरोप की तहरीर डीएम बिजनौर को दी गई है

लोकतंत्र की शान , खिज़्र अहमद, नजीबाबाद: रम्पुरा क्षेत्र में एक राशन डीलर के खिलाफ लगातार शिकायतें सामने आने के बावजूद प्रशासन की चुप्पी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। ग्रामीणों का आरोप है कि राशन वितरण में अनियमितताओं, पात्र लाभार्थियों को पूरा राशन न मिलने तथा मनमानी के संबंध में कई बार शिकायतें की जा चुकी हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई होती दिखाई नहीं दे रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब भी शिकायत की जाती है तो जांच का आश्वासन देकर मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। इससे ग्रामीणों में रोष बढ़ता जा रहा है। कई परिवारों का आरोप है कि सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए उन्हें बार-बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा। ग्रामीणों का कहना है कि यदि शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं होती है तो आम जनता का प्रशासन पर विश्वास कमजोर होता है। लोगों ने मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी पाए जाने पर संबंधित राशन डीलर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि पात्र लाभार्थियों को उनका हक मिल सके। अब बड़ा सवाल यह है कि जब शिकायतों की संख्या लगातार बढ़ रही है और पीड़ित अपनी बात अधिकारियों तक पहुंचा चुके हैं, तो आखिर कार्रवाई में देरी क्यों हो रही है? क्षेत्रवासियों का कहना है कि यदि स्थानीय स्तर पर सुनवाई नहीं होती तो उन्हें उच्च अधिकारियों और शासन स्तर तक अपनी आवाज पहुंचानी पड़ेगी। क्षेत्रीय जनता ने जिलाधिकारी एवं खाद्य एवं रसद विभाग के अधिकारियों से मामले का संज्ञान लेकर जल्द कार्रवाई करने की मांग की है।

जिला केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन की संपर्क बैठक संपन्न, संगठन को मजबूत बनाने पर हुआ मंथन

लोकतंत्र की शान, खिज़्र अहमद , नजीबाबाद। बुधवार, 3 जून 2026 को जिला केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन बिजनौर के तत्वावधान में संगठन को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण संपर्क बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का आयोजन स्थानीय प्रतिष्ठान पर किया गया, जिसमें जिले के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े केमिस्ट प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में चांदपुर से श्री प्रदीप चौधरी, नूरपुर से श्री इंद्र सिंह चौहान, बाष्टा से मोहम्मद कासिम, ताजपुर से मोहम्मद नसीम, रहमान मेडिकल स्टोर के स्वामी तथा कासमपुर गढ़ी से श्री संतोष चौहान विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत जिला महामंत्री श्री अश्वनी शर्मा द्वारा सभी अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत करने के साथ हुई। अपने संक्षिप्त संबोधन में श्री शर्मा ने संगठन की एकता एवं मजबूती पर जोर देते हुए कहा कि संगठित प्रयासों से ही केमिस्ट समुदाय की समस्याओं का प्रभावी समाधान संभव है। बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों ने एक स्वर में संगठन को और अधिक सशक्त बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। वक्ताओं ने कहा कि यदि संगठन मजबूत होगा तो आम केमिस्टों की समस्याओं को प्रशासन एवं संबंधित विभागों के समक्ष मजबूती से उठाया जा सकेगा तथा उनके समाधान के लिए प्रभावी प्रयास किए जा सकेंगे। सभी सदस्यों ने विश्वास व्यक्त किया कि जिला महामंत्री श्री अश्वनी शर्मा के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में संगठन नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। इस अवसर पर श्री अश्वनी शर्मा ने सभी को आश्वस्त किया कि वह संगठन को मजबूत एवं सक्रिय बनाने के लिए अपने स्तर से हरसंभव प्रयास करेंगे। बैठक सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई तथा भविष्य में संगठन विस्तार एवं सदस्य हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर निरंतर कार्य करने का संकल्प लिया गया।

भूमि संबंधी प्रकरणों में लापरवाही पर हो सख्त कार्रवाई: मुख्यमंत्री

लोक तंत्र की शान , गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में भूमि संबंधी शिकायतों पर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने डीएम को निर्देशित किया कि भूमि संबंधी शिकायतों के निस्तारण में किसी भी स्तर पर लापरवाही मिलने पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए। प्रकरण की गंभीरता के अनुसार संबंधित के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की जाए। किसी भी स्तर पर शिथिलता या लापरवाही कतई क्षम्य नहीं है। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर प्रवास के दौरान लगातार दूसरे दिन बुधवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। कुछ लोगों ने जमीन से जुड़े मामलों में राजस्व कर्मियों की तरफ से लापरवाही किए जाने की शिकायत की तो उन्होंने डीएम को तत्काल कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। इस अवसर पर इलाज के लिए आर्थिक सहायता की गुहार लेकर पहुंचे लोगों से उन्होंने कहा कि सरकार इलाज में पूरी मदद करेगी। इसके लिए जरूरतमंद लोगों का आयुष्मान कार्ड बनवाया जाएगा और इसके बाद भी जरूरत पड़ी तो विवेकाधीन कोष से सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री ने मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर जरूरतमंद, पात्र व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड बनवाना सुनिश्चित किया जाए, ताकि उन्हें इलाज के लिए परेशान न होना पड़े।

बिजनौर में 'फर्जी इन्फ्लुएंसरों' का बढ़ता जाल, क्या प्रशासन करेगा कार्रवाई ?

बिना अनुमति दिखाए जा रहे चेहर

लोकतंत्र की शान

बिजनौर: जनपद में इन दिनों सोशल मीडिया के नाम पर एक नया चलन तेजी से फैल रहा है। हर गली, मोहल्ले और चौराहे पर मोबाइल कैमरा लेकर घूम रहे कुछ युवक स्वयं को इन्फ्लुएंसर, पत्रकार और समाजसेवी बताकर सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड कर रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर इन गतिविधियों पर कोई निगरानी क्यों नहीं है? स्थिति यह है कि सार्वजनिक स्थानों पर वीडियो बनाने के नाम पर राह चलती महिलाओं, छात्राओं, बुजुर्गों और आम नागरिकों की निजता तक दांव पर लगाई जा रही है। कई वीडियो में बिना अनुमति लोगों के चेहरे दिखाए जा रहे हैं। ऐसे मामलों में महिलाओं और परिवारों की भावनाओं तथा उनकी सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं की अनदेखी की जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ तथाकथित इन्फ्लुएंसर लोकप्रियता और लाइक्स पाने की होड़ में सामाजिक मर्यादाओं की सीमाएं लांघ रहे हैं। युवतियों पर टिप्पणियां करना, लोगों को उकसाने वाले वीडियो बनाना और बिना पुष्टि के सूचनाएं प्रसारित करना अब आम बात होती जा रही है। इससे समाज में भ्रम और तनाव की स्थिति पैदा होने का खतरा बढ़ रहा है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि सोशल मीडिया पर हजारों लोगों तक पहुंचने वाली सामग्री बिना किसी तथ्यात्मक जांच के प्रसारित की जा रही है। कुछ लोग कैमरा और मोबाइल हाथ में आते ही स्वयं को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ घोषित कर देते हैं, जबकि पत्रकारिता केवल वीडियो बनाने का नाम नहीं बल्कि सत्यता, निष्पक्षता और जिम्मेदारी का विषय है। जनपद के जिम्मेदार नागरिकों का मानना है कि यदि समय रहते इस प्रवृत्ति पर नियंत्रण नहीं किया गया तो आने वाले समय में साइबर अपराध, निजता के उल्लंघन और सामाजिक विवादों के मामले बढ़ सकते हैं। प्रशासन, पुलिस और साइबर सेल को इस विषय पर गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और नागरिकों की निजता के बीच संतुलन बना रहे। आज आवश्यकता इस बात की है कि सोशल मीडिया का उपयोग समाज को जागरूक करने के लिए हो, न कि लोगों की निजता, सम्मान और सामाजिक मर्यादाओं को नुकसान पहुंचाने के लिए। बिजनौर के नागरिक अब यह सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कब तक कुछ लोग लाइक्स और व्यूज़ के नाम पर समाज की संवेदनशीलता से खिलवाड़ करते रहेंगे?

प्लॉट ठगी मामले में नया मोड़: पीड़ित को बंधक बनाकर वसूली का आरोप, बारादरी थाने के चार पुलिसकर्मी निलंबित

लोकतंत्र की शान

(बरेली, उत्तर प्रदेश | संदीप चंद्रा) जनपद बरेली में पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। प्लॉट खरीद के नाम पर कथित 10 लाख रुपये की ठगी और उसके बाद पीड़ित को अवैध रूप से बंधक बनाकर उससे रुपये वसूलने के आरोपों ने पुलिस महकमे में हलचल पैदा कर दी है। मामले की प्रारंभिक जांच में आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए जाने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) अनुराग आर्य ने थाना बारादरी में तैनात चार पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर विभागीय जांच शुरू करा दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार हाफिजगंज थाना क्षेत्र के गांव आसपुर हसन अली निवासी सोमवीर कश्यप एक प्लॉट खरीदने के सिलसिले में प्रॉपर्टी डीलर प्रेम बाबू यादव के संपर्क में आया था। पीड़ित के मुताबिक 12 मई 2026 को प्रेम बाबू यादव ने उसे एग्रीमेंट कराने के बहाने न्यू विलयधाम स्थित अपने ढाबे पर बुलाया। इसके बाद उसे अपने साथ डोहरा रोड ले जाया गया, जहां पहले से मौजूद कुछ लोगों को 10 लाख रुपये से भरा बैग सौंप दिया गया। आरोप है कि रकम लेने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना के बाद सोमवीर लगातार अपनी रकम वापस लेने के लिए प्रयास करता रहा और कथित तौर पर प्रॉपर्टी डीलर की तलाश में लगा रहा। पीड़ित के अनुसार 14 मई को जब वह संबंधित ढाबे पर मौजूद था, तभी दो वर्दीधारी और दो सादे कपड़ों में पहुंचे पुलिसकर्मियों ने उसे जबरन अपनी गाड़ी में बैठाकर थाना बारादरी ले गए।

अमरोहा का प्रभारी मंत्री बनने पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी को विधायक व भाजपाइयों ने दी बधाई

लोक तंत्र की शान प्रवीण अग्रवाल जिला प्रभारी अमरोहा

अमरोहा/हसनपुर: उत्तर प्रदेश सरकार में माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी जी को जनपद अमरोहा का प्रभारी मंत्री नियुक्त किए जाने पर भाजपा कार्यकर्ताओं में हर्ष की लहर है। हसनपुर विधायक महेंद्र सिंह खड़गवंशी, धनोरा विधायक राजीव तरारा सहित जनपद के वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। विधायक महेंद्र सिंह खड़गवंशी ने कहा कि गुलाब देवी जी का प्रशासनिक अनुभव बेजोड़ है। उनके कुशल नेतृत्व एवं जनसेवा के प्रति समर्पण से जनपद अमरोहा विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। हमें पूर्ण विश्वास है कि उनके मार्गदर्शन में जनपद के सर्वांगीण विकास को नई गति मिलेगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा तथा जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरते हुए अनेक जनकल्याणकारी कार्य संपन्न होंगे। भाजपा जिला अध्यक्ष उदयगिरि गोस्वामी ने कहा कि गुलाब देवी जी जमीन से जुड़ी नेता हैं। वह हमेशा गरीब, किसान, महिला और युवा के हितों के लिए संघर्षरत रही हैं। अमरोहा को प्रभारी मंत्री के रूप में उनका मिलना सौभाग्य की बात है। उनके आने से जिले की कानून व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी और लंबित विकास कार्यों में तेजी आएगी।

इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने मिष्ठान वितरण कर खुशी जताई। कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में कहा कि प्रभारी मंत्री के रूप में गुलाब देवी जी के आने से संगठन और सरकार के बीच बेहतर समन्वय बनेगा। जनसमस्याओं का त्वरित निस्तारण होगा और अमरोहा प्रदेश के अग्रणी जिलों में शामिल होगा। सभी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताते हुए कहा कि उनके इस निर्णय से कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है।

बरेली में TGT परीक्षा में बड़ा खेल: पुलिस ने दबोचे दो फर्जी सॉल्वर, डेढ़ लाख में हुआ था सौदा

लोकतंत्र की शान

(बरेली, उत्तर प्रदेश | संदीप चंद्रा) उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती परीक्षा की पारदर्शिता पर सवाल खड़े करने वाला एक बड़ा मामला बरेली से सामने आया है। जिले में आयोजित TGT परीक्षा के दौरान पुलिस और प्रशासन ने दो ऐसे फर्जी सॉल्वर पकड़ लिए जो वास्तविक अभ्यर्थियों की जगह परीक्षा देने पहुंचे थे। दोनों आरोपियों को अलग-अलग परीक्षा केंद्रों से हिरासत में लिया गया। शुरुआती जांच में सामने आया है कि परीक्षा पास कराने के लिए लाखों रुपये का सौदा तय हुआ था। इस कार्रवाई के बाद शिक्षा विभाग और पुलिस प्रशासन में हलचल तेज हो गई है। माना जा रहा है कि यह किसी बड़े सॉल्वर गैंग का हिस्सा हो सकता है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में संगठित तरीके से फर्जीवाड़ा कर रहा है।

इस्लामिया गर्ल्स इंटर कॉलेज से पहला सॉल्वर गिरफ्तार–पहला मामला शहर कोतवाली क्षेत्र स्थित इस्लामिया गर्ल्स इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्र का है। परीक्षा के दौरान ड्यूटी पर मौजूद अधिकारियों को एक अभ्यर्थी के व्यवहार पर संदेह हुआ। जांच के दौरान आधार कार्ड, प्रवेश पत्र और बायोमेट्रिक सत्यापन कराया गया। जांच में सामने आया कि परीक्षा दे रहा युवक असली अभ्यर्थी नहीं था। पूछताछ में उसकी पहचान आजमगढ़ निवासी प्रमोद कुमार के रूप में हुई। वह फर्रुखाबाद निवासी विमल कुमार के स्थान पर परीक्षा दे रहा था। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि परीक्षा देने के लिए डेढ़ लाख रुपये का सौदा तय हुआ था। कुछ रकम एडवांस के रूप में पहले ही मिल चुकी थी जबकि बाकी राशि परीक्षा परिणाम आने के बाद दी जानी थी।

बरेली कॉलेज में भी पकड़ा गया दूसरा फर्जी अभ्यर्थी–दूसरा मामला बरेली कॉलेज परीक्षा केंद्र से सामने आया। यहां फ्लाइंग स्क्वाड को एक परीक्षार्थी की गतिविधियां संदिग्ध लगीं। जांच के लिए जब बायोमेट्रिक सत्यापन कराया गया तो थंब इंप्रेशन रिकॉर्ड से मेल नहीं खाया।

दहेज के दानवों ने एक और विवाहिता को उतारा मौत के घाट मयके बालों ने हत्या का आरोप लगाकर मार्ग जाम किया

लोक तंत्र की शान प्रवीण अग्रवाल जिला प्रभारी अमरोहा

हसनपुर : कोतवाली क्षेत्र के गांव शाहपुर कला में दहेज लोभियों की हैवानियत का दर्दनाक मामला सामने आया है। तीन माह की गर्भवती 24 वर्षीय विवाहिता प्रतिभा उर्फ पिंकी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर गला घोटकर हत्या का आरोप लगाते हुए हसनपुर-रहरा मार्ग पर शव रखकर जाम लगा दिया। करीब आधे घंटे तक मार्ग बाधित रहा। इस दौरान पुलिस से जमकर नोंक-झोंक हुई और गुस्साए परिजनों ने आरोपी के घर में तोड़फोड़ भी की। मृतका की चाची ने बताया कि सैदनगली के निचला तरारा निवासी शीशपाल सिंह ने तीन साल पहले बेटी पिंकी की शादी शाहपुर कला निवासी सोनू पुत्र चेतराम से की थी। शादी में स्विफ्ट कार सहित भरपूर दहेज दिया गया। इसके बाद भी ससुराल वाले अतिरिक्त आभूषण व बड़ी गाड़ी की मांग को लेकर पिंकी को प्रताड़ित करते थे। तंग आकर पिंकी लंबे समय तक मायके में रही, जहां उसने एक बेटी को जन्म दिया। वह तीन माह की गर्भवती थी। मंगलवार शाम मायके वालों को पिंकी के फांसी लगाने की सूचना मिली। जब परिजन पहुंचे तो शव घर के बाहर पड़ा था। गले पर निशान देख परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। शव सड़क पर रखकर जाम लगा दिया गया। सूचना पर कोतवाल राजेश तिवारी फोर्स के साथ पहुंचे। स्थिति बिगड़ती देख सीओ मंडी धनौरा अंजलि कटारिया, रहरा, आदमपुर व सैदनगली थानाध्यक्ष भी दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई का आश्वासन देकर जाम खुलवाया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। सीओ अंजलि कटारिया ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट व जांच के आधार पर कड़ी कार्रवाई होगी। फिलहाल गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है। दहेज हत्या की इस घटना से इलाके में आक्रोश है।

रहरा पुलिस ने 10 लीटर कच्ची शराब के साथ एक युवक को किया गिरफ्तार

लोक तंत्र की शान प्रवीण अग्रवाल जिला प्रभारी अमरोहा

हसनपुर/रहरा: जनपद में अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना रहरा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एक अभियुक्त को 10 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक अखिलेश भदौरिया के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी हसनपुर पंकज कुमार त्यागी के निकट नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। प्रभारी निरीक्षक अखिलेश प्रधान के नेतृत्व में थाना रहरा पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान अभियुक्त सोनू केवट पुत्र बलवन्त निवासी ग्राम पौरारा थाना रहरा को एक जरीकेन में 10 लीटर कच्ची शराब के साथ पकड़ा। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह कच्ची शराब बनाकर आसपास के गांवों में बेचता था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ थाना रहरा पर मु0अ0सं0 133/2026 धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में का0 1242 गुलफाम व का0 115 आकाश आर्य शामिल रहे। पुलिस अधीक्षक ने टीम को बधाई देते हुए कहा कि अवैध शराब के कारोबार में लिप्त लोगों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। आम जनता से भी अपील की गई है कि अवैध शराब की सूचना तत्काल पुलिस को दें।

अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी) परीक्षा केन्द्रों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का लिया जायजा

लोक तंत्र की शान, मंडल प्रभारी अवनीत कुमार शर्मा

रामपुर । उत्तर प्रदेश / रामपुर अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह, द्वारा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी) परीक्षा को सकुशल, निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से सम्पन्न कराने के उद्देश्य से जनपद के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों का भ्रमण कर सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था संबंधी व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक ने केन्द्र व्यवस्थापकों एवं संबंधित अधिकारियों से परीक्षा संचालन के संबंध में जानकारी प्राप्त की । परीक्षा केन्द्रों पर तैनात पुलिस बल को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान करते हुए परीक्षा की शुचिता बनाए रखने, अभ्यर्थियों की सुगम एवं व्यवस्थित प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित करने तथा किसी भी प्रकार की अवांछनीय गतिविधि पर सतर्क दृष्टि रखने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने परीक्षा केन्द्रों पर स्थापित सीसीटीवी कैमरों, प्रवेश द्वारों पर की जा रही सघन चेकिंग एवं अन्य सुरक्षा प्रबंधों का भी जायजा लिया।

हसनपुर के जीहल गांव में प्रथमा किसान क्लब देहरा मिलक की बैठक, किसानों की समस्याओं पर मंथन

लोक तंत्र की शान प्रवीण अग्रवाल जिला प्रभारी अमरोहा

हसनपुर: ग्राम जीहल में रविवार को प्रथमा किसान क्लब देहरा मिलक की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता क्लब अध्यक्ष रामचंद्र सिंह ने की। इस दौरान क्षेत्र के किसानों की ज्वलंत समस्याओं पर गहन विचार-विमर्श किया गया और सरकार से समाधान की मांग उठाई गई। बैठक को संबोधित करते हुए अध्यक्ष रामचंद्र सिंह ने कहा कि आज किसान दोहरी मार झेल रहा है। एक ओर घरेलू गैस सिलेंडर समय पर नहीं मिल पा रहे, वहीं खेती के लिए जरूरी उर्वरक की किल्लत से भी जूझना पड़ रहा है। कालाबाजारी के चलते किसानों को महंगे दामों पर खाद खरीदनी पड़ रही है। उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार को गोबर गैस प्लांट लगाने पर सब्सिडी देकर बढ़ावा देना चाहिए। इससे रसोई गैस की समस्या खत्म होगी और जैविक खाद भी मिलेगी। किसान परमसिंह चौधरी ने खाद वितरण में हो रही धांधली का मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि किसान अपनी जरूरत के हिसाब से 1-2 बोरी खाद लेने जाता है, लेकिन विक्रेता पोर्टल पर 5-6 बोरी खरीदी हुई दिखा देता है। इससे कोटा पूरा हो जाता है और जरूरतमंद किसान को खाद नहीं मिलती। इस पर तुरंत अंकुश लगाने की जरूरत है। कृष्ण कुमार शर्मा ने कहा कि रासायनिक खादों के अंधाधुंध प्रयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति लगातार घट रही है। मानव स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा है। इससे बचने का एकमात्र उपाय गौ आधारित जैविक खेती को अपनाना है। इससे लागत भी कम होगी और फसल का दाम भी अच्छा मिलेगा। बैठक में भारतीय किसान संघ के जिलाध्यक्ष चंद्र प्रकाश शर्मा ने कहा कि सरकार को किसानों की बात सुननी चाहिए। महिपाल सिंह प्रांत गन्ना प्रमुख ने गन्ना भुगतान की समस्या रखी। इस अवसर पर बुद्ध प्रकाश सिंह, अजय त्यागी, करन सिंह चौहान सहित दर्जनों किसान मौजूद रहे। अंत में सभी ने एकजुट होकर किसानों के हित में संघर्ष का संकल्प लिया।

संक्षिप्त समाचार

हाजीपुर गंडक पुल से बच्चों का खतरनाक स्टंटःवीडियो वायरल, लोग बोले- '4 लाख का चेक तैयार है'

लोकतंत्र की शान : हाजीपुर। हाजीपुर-सोनपुर गंडक पुल से बच्चों द्वारा खतरनाक स्टंट करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद लोग इसे बेहद खतरनाक बता रहे हैं और टिप्पणी कर रहे हैं कि '4 लाख रुपए का चेक तैयार है'। यह टिप्पणी इस ओर इशारा करती है कि यदि स्टंट के दौरान कोई दुर्घटना या मौत होती है, तो आश्रित परिवार को सरकारी खजाने से 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाता है। वायरल वीडियो

इंस्टाग्राम पर साझा किया गया है। यह स्टंट हाजीपुर-सोनपुर के पुराने गंडक पुल पर किया गया, जहां चार-पांच बच्चे खतरनाक तरीके से स्टंट करते हुए कैमरे में कैद हुए। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक के बाद एक दो बच्चे गंडक नदी में छलांग लगाते हैं। तीसरा बच्चा संशय में दिख रहा है, क्योंकि पुल से नदी की गहराई लगभग 40 से 50 फुट है। पहले और दूसरे लड़के अन्य बच्चों को छलांग लगाने के लिए बार-बार इशारा कर रहे थे। पुल से बच्चे नदी में लंबी छलांग लगा रहे थे। गौरतलब है कि गंडक पुल के दोनों ओर पुलिस बल तैनात रहता है। एक तरफ हाजीपुर नगर थाने की पुलिस और दूसरी तरफ छपरा जिले की सोनपुर पुलिस की तैनाती होती है। इसके बावजूद पुलिस अधिकारियों द्वारा इस तरह की गतिविधियों की अनदेखी की जा रही है। इसी पुल से पहले भी कई बार युवक-युवतियों ने आत्महत्या के इरादे से छलांग लगाई है। हालांकि, कई मौकों पर हाजीपुर पुलघाट पर तैनात एसडीआरएफ टीम ने उनकी जान बचाई है। इस घटना के बाद, वहां से गुजरने वाले लोग पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि यदि पुल पर पुलिसकर्मियों को ठीक से तैनात किया जाए, तो ऐसी असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सकता है।

पिकअप ने व्यक्ति को रौंदा, मौत, वैशाली में नाराज स्थानीय लोगों ने बांस लगा किया सड़क जाम

लोकतंत्र की शान : हाजीपुर। वैशाली के कटहरा थाना क्षेत्र अंतर्गत चेहराकलां मुख्यालय चौक पर एक तेज रफ्तार बालू लदी पिकअप ने एक व्यक्ति को कुचल दिया। इस हादसे में 45 वर्षीय मिंटू राय की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए। उन्होंने सड़क पर शव रखकर टायर जलाए और बांस लगाकर सड़क जाम कर दिया। प्रदर्शनकारी मृतक के परिजनों के लिए उचित मुआवजे और पिकअप चालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे थे। जानकारी मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आक्रोशित लोगों को समझाने का प्रयास कर रही है। मृतक के भाई महेंद्र राय ने बताया कि मिंटू राय सड़क किनारे खड़े थे, तभी तेज रफ्तार पिकअप ने उन्हें टक्कर मार दी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इस सड़क पर अनियंत्रित वाहनों का परिचालन होता है और पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता, जिससे आए दिन छोटे-बड़े हादसे होते रहते हैं। महेंद्र राय ने पिकअप चालक पर कार्रवाई और मृतक के परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग पुलिस और जिला प्रशासन से की है। पुलिस अभी भी लोगों को शांत करने में जुटी है।

गंडक नदी में डूबे किशोर का शव मिला, वैशाली में लालगंज के बसंत जहानाबाद घाट से 3 किमी दूर बरामद

लोकतंत्र की शान : हाजीपुर। वैशाली जिले में गंडक नदी में डूबे 13 वर्षीय किशोर विक्की कुमार का शव 48 घंटे बाद बरामद कर लिया गया है। लालगंज के बसंत जहानाबाद घाट पर सोमवार दोपहर स्नान के दौरान वह गहरे पानी में डूब गया था। उसका शव घटना स्थल से लगभग 3 किलोमीटर दूर घटारो बलहा घाट पर मिला। विक्की कुमार नगर परिषद क्षेत्र के अताउल्लाहपुर पोंझिया, वार्ड संख्या 25 निवासी विन्देश्वर महतो का पुत्र था। वह अपने चार दोस्तों के साथ गंडक नदी में स्नान करने गया था, तभी गहरे पानी में जाने के कारण डूब गया। उसके साथियों ने तुरंत परिजनों को घटना की सूचना दी। सूचना मिलने पर परिजन और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। उन्होंने निजी गोताखोरों की मदद से किशोर की तलाश शुरू की, लेकिन सोमवार देर शाम तक उसका कोई पता नहीं चल सका। प्रशासन को भी इस घटना की जानकारी दी गई थी। मंगलवार सुबह करीब 10 बजे राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) की टीम घटनास्थल पर पहुंची और खोज अभियान शुरू किया। एसडीआरएफ अधिकारी बुद्धि बहादुर ने बताया कि दो टीमें भेजी गई थीं, जिसमें से एक टीम के उपकरण में तकनीकी खराबी आ गई थी। शेष टीम ने लगातार खोजबीन जारी रखी और बुधवार को किशोर का शव बरामद किया। मुखिया संघ के अध्यक्ष गणेश राय ने बसंत जहानाबाद घाट को खतरनाक बताया है। उन्होंने लोगों से सावधानी बरतने की अपील करते हुए घाट पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस घाट पर दूर-दराज से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा-पाठ और स्नान के लिए आते हैं, लेकिन सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं हैं। उनका आरोप है कि लगातार डूबने की घटनाओं के बावजूद प्रशासन ने न तो बैरिकेडिंग कराई है और न ही चेतावनी संबंधी कोई प्रभावी व्यवस्था की है। शव मिलने के बाद पुलिस ने उसे कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल हाजीपुर भेज दिया है।

हाजीपुर में जुआ अड्डे पर छापा, 6 गिरफ्तार, पुलिस ने 23 हजार कैश और ताश बरामद किए

लोकतंत्र की शान : हाजीपुर। हाजीपुर नगर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जुआ के एक अड्डे पर छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने छह लोगों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 23,510 रुपए नगद तथा ताश के बंडल बरामद किए। यह कार्रवाई एसडीओ रोड मोड़ स्थित मछली मंडी के पीछे की गई। पुलिस को देखकर जुआ खेल रहे लोग भागने लगे, लेकिन पुलिस बल की मदद से सभी को पकड़ लिया गया। बरामद सामान में ताश के बंडल और अन्य संबंधित वस्तुएं शामिल हैं। एसपी विक्रम सिहाग ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इस कार्रवाई की जानकारी दी। गिरफ्तार किए गए सभी व्यक्तियों से थाने में पूछताछ के बाद उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई और उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान अमन कुमार पोद्दार , अजीत कुमार , बबलू कुमार , दीपक कुमार , रोहित कुमार और हिमांशु कुमार के रूप में हुई है। सभी के विरुद्ध बंगाल जुआ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

जॉर्ज फर्नांडिस की जयंती राजकीय समारोह के रूप में मनाई, मुजफ्फरपुर में मंत्री श्रवण कुमार हुए शामिल

लोकतंत्र की शान : मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में पूर्व रक्षा मंत्री और महान समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस की जयंती राजकीय समारोह के रूप में मनाई गई। यह कार्यक्रम शहर के कंपनीबाग स्थित जॉर्ज स्मृति उद्यान सिटी पार्क में आयोजित की गई। इस अवसर पर राज्य सरकार के ग्रामीण विकास सह सूचना जनसंपर्क विभाग के मंत्री श्रवण कुमार ने हिस्सा लिया। उनके साथ जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन और एसएसपी कांतेश कुमार मिश्र सहित कई अतिथियों और अधिकारियों ने जॉर्ज फर्नांडिस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मंत्री श्रवण कुमार ने इस मौके पर जॉर्ज फर्नांडिस को देश का क्रांतिकारी नेता बताया। उन्होंने कहा कि फर्नांडिस इंदिरा गांधी की तानाशाही के खिलाफ अडिग रहे और जीवनभर संघर्ष करते हुए गरीब व बेसहारा लोगों के सहारा बने रहे। श्रवण कुमार ने फर्नांडिस के संकल्पों को आगे बढ़ाने का वादा किया। उन्होंने कहा कि हम सभी उनसे प्रेरणा लेते हैं और देश व राज्य की बेहतरी के लिए लगातार काम करते रहेंगे, ताकि जनता की बेहतर सेवा की जा सके। मंत्री ने इस राजकीय समारोह की जिम्मेदारी मिलने को अपने लिए गर्व का विषय बताया। उन्होंने कहा कि आज उनके आदर्शों पर चलने की आवश्यकता है।

पटना में प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या, 2 आरोपी गिरफ्तार

लोकतंत्र की शान , पटना

पटना के दानापुर के नासरीगंज बिस्कुट फैक्ट्री मोड़ के पास 31 मई की रात गैस वेंडर इंदल कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पटना पुलिस की ओर से खुलासा किया गया है। पटना पश्चिमी एसपी भानु प्रताप सिंह ने बताया, इसकी जांच खुलासा के लिए SIT गठित की गई थी। जिसमें टेक्निकल टीम, SHO दानापुर और अन्य पुलिस पदाधिकारी शामिल थे। 24 घंटे के भीतर इस घटना में संलिप्त दो आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया है। जिस कट्टा से गोली मारकर हत्या की गई थी, इनकी निशानदेही पर उसे भी बरामद किया गया है। इसके अलावा एक बाइक, एक मोबाइल बरामद किए गए हैं।

मास्टरमाइंड सहित 2 आरोपी गिरफ्तारः पश्चिमी एसपी भानु प्रताप सिंह ने बताया कि इस मामले में भोजपुर के रहने वाले घटना के मास्टरमाइंड आलोक कुमार उर्फ बप्पी और विश्वजीत कुमार उर्फ छोटू को अरेस्ट किया है। घटना की पूरी प्लानिंग बप्पी की थी। विश्वजीत और बप्पी भाई हैं। मृतक इंदल कुमार और आलोक उर्फ बप्पी के बीच एक महिला को लेकर विवाद चल रहा था। एक महिला को लेकर दोनों आपस में लड़ते झगड़ते रहे हैं। महिला का संबंध दोनों से समय समय पर रहा है।

आलोक से महिला की दूरी हो गई थी। उसे लगता था कि वो इंदल के साथ अफेयर में है।इसी आक्रोश में आकर उसने इंदल की गोली मारकर हत्या कर दी थी। बता दें कि रविवार की रात गैस वेंडर की गोली मारकर हत्या हुई हुई थी। उसे तीन गोलियां लगी थी। एक सीना, दूसरी पसली और तीसरी बाएं हाथ में लगी थी। मृतक इंदल के भाई संजीत ने आलोक और उसके छोटे भाई छोटू के खिलाफ FIR कराई थी। पुलिस अब पता लगा रही कि छोटू का हत्या में क्या रोल है। मामला नासरीगंज बिस्कुट फैक्ट्री रोड स्थित तक्षशिला कॉलोनी के पास का है। मामला 31 मई की रात का है। 1 जून को हत्या का कारण पता चला।

महिला के घर के बगल में रहता था आरोपीः महिला की पति की मौत 6 साल पहले बीमारी की वजह से हो गई थी। आरोपी आलोक महिला के ससुराल के बगल में किराए पर रहता था। इसी दौरान दोनों का संपर्क हुआ। मृतक इंदल से भी पहचान थी।

विश्व साइकिलिंग दिवस पर सहरसा में साइकिल रैली और प्रतियोगिता का आयोजन बालक-बालिकाओं ने दिखाया उत्साह

लोकतंत्र की शान

सहरसा, मो. जियाउद्दीन, जिला संवाददाताः विश्व साइकिलिंग दिवस के अवसर पर आज सहरसा स्टेडियम के बाहरी एवं भीतरी परिसर में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत "स्मिता विमेंस साइकिल लीग" का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भव्य साइकिल रैली भी निकाली गई तथा बालक एवं बालिकाओं के लिए साइकिल रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। जिला साइकिलिंग संघ के सचिव श्री दर्शन कुमार गुड्डू ने जानकारी देते हुए बताया कि इस प्रतियोगिता में कुल 87 बालिकाओं ने भाग लिया, जबकि लगभग 210 बालक-बालिकाओं ने साइकिल रैली में सहभागिता की। प्रतियोगिता में बालिका वर्ग में 87 तथा बालक वर्ग में 113 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। 5 किलोमीटर की रेस का आयोजन बालिकाओं के तीन आयु वर्गों एवं बालकों के ओपन वर्ग में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सिमरी बख्तियारपुर के विधायक श्री संजय कुमार सिंह एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में ईस्ट एंड वेस्ट फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉ. रजनीश रंजन तथा भाजपा के जिला मंत्री गौरव सिंह उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि एवं अन्य अतिथियों ने विजेता प्रतिभागियों को मेडल, प्रमाण पत्र एवं पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया।

अपने संबोधन में विधायक श्री संजय कुमार सिंह ने कहा कि उनके घर में भी खेल का अच्छा माहौल रहा है और वे सहरसा सहित अपने क्षेत्र में खेल के विकास के लिए हरसंभव प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि खेल सुविधाओं के लिए सरकार से मांग करने में भी वे पीछे नहीं हटेंगे और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर कार्य करते रहेंगे।

पटना सदर सीओ का सरकारी नंबर हैक, साइबर थाना में शिकायत दर्ज

लोकतंत्र की शान , पटना

पटना सदर के अंचलाधिकारी रजनी कांत का सरकारी CUG मोबाइल नंबर 9031671824 हैक कर लिया गया है। उनकी ओर से इस बाबत में पटना के साइबर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। उन्होंने बताया है कि सरकारी नंबर पर 9861832938 से कॉल आया। उसने बताया कि वह कुरियर डिलीवरी करने वाला है। उसने कुरियर बॉय को कॉल करने के लिए कहा। इसके बाद मेरे सह कर्मी ने उसके बताए अनुसार *21* 7764987536# डायल किया। इस कॉल के बाद मेरा मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर दोनों हैक हो गया।

क्यूआर कोड भेजकर 25000 रुपए की ठगीः CO ने बताया कि मेरे बॉबी नाम के परिचित को सबसे पहले क्यूआर कोड भेजकर मेरे नाम पर 25000 रुपए ठग लिए। फिर मल्टीपल लोगों को क्यूआर कोड भेजकर रुपए मांगे गए। मेरे नंबर पर जो भी कॉल किया जा रहा है, वह

7764987536 पर फॉरवार्ड हो जा रहा है।

साइबर DYSP नीतीश चंद्र धारिया ने बताया कि, 'प्राथमिकी दर्ज कर के मामले की छानबीन की जा रही है। पिछले दो महीने में इस तरीके के 15 से अधिक मामले आ चुके हैं। लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है।' सबसे पहले व्हाट्सएप में टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करें। इससे जल्दी हैक नहीं होगा। इसके लिए व्हाट्सएप की सेटिंग में जाएं। इसके बाद एकाउंट पर क्लिक करें। एकाउंट पर क्लिक करने के बाद टू स्टेप वेरिफिकेशन आएगा। उस पर क्लिक करने के बाद 6 डिजिट नंबर डालकर सेव कर लें। इससे व्हाट्सएप हैक आसानी से नहीं होगा।

जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की बैठक में विकास योजनाओं की समीक्षा, अवैध नर्सिंग होम पर सख्त कार्रवाई के निर्देश

लोकतंत्र की शान

सहरसा, मो. जियाउद्दीन, जिला संवाददाताः स्थानीय विकास भवन में आज शिक्षा मंत्री सह माननीय प्रभारी मंत्री श्री मिथिलेश तिवारी की अध्यक्षता में आयोजित बीस सूत्री अर्थात जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की बैठक में जिले के समेकित एवं समावेशी विकास पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में संचालित योजनाओं के पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन तथा प्राप्त शिकायतों के त्वरित निष्पादन की आवश्यकता पर विशेष बल दिया गया। समीक्षा के दौरान पूर्व बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की जांच की गई तथा विभिन्न विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा चापाकलों की मरम्मत कार्य की प्रगति की जानकारी देते हुए बताया गया कि लगभग 500 चापाकलों का कार्य पूर्ण हो चुका है और शेष कार्य शीघ्र पूरा किया जाएगा। कार्यपालक

अभियंता को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का निर्देश दिया गया, जिसमें जनप्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाएगा। लापरवाही बरतने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई। बैठक में जनप्रतिनिधियों द्वारा अवैध रूप से संचालित नर्सिंग होम का मुद्दा उठाया गया, जिस पर प्रभारी मंत्री ने अनिबंधित एवं अवैध नर्सिंग होम के विरुद्ध व्यापक अभियान चलाने का निर्देश दिया। इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा वरीय अधिकारियों के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया जाएगा। समीक्षा के क्रम में सिमरी बख्तियारपुर नगर परिषद क्षेत्र के काली मंदिर के समीप स्थित जलमीनार के अक्रियाशील होने का मामला सामने आया। इस पर परियोजना निदेशक, बुडको को इसे अविलंब चालू कराने एवं नगर परिषद को हस्तांतरित करने का निर्देश दिया गया। नगर निगम क्षेत्र में भू-अतिक्रमण के मामलों पर भी गंभीरता दिखाते हुए निर्देश दिया गया कि नापी के पश्चात अतिक्रमण की पुष्टि होने पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही तुलसियाही ग्राम में तिलावे नदी पर बने पुल के पहुंच पथ निर्माण हेतु डीपीआर तैयार होने की जानकारी दी गई तथा शीघ्र ही कार्य प्रारंभ कर आवागमन सुगम बनाने की बात कही गई।

मोहनपुर में जीविका भवन का उद्घाटन, महिलाओं के स्वरोजगार और उद्यमिता को मिलेगा नया संबल

लोकतंत्र की शान

सहरसा, मो. जियाउद्दीन, जिला संवाददाताः सहरसा जिले के नौहट्टा प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत मोहनपुर में नवनिर्मित जीविका भवन का भव्य उद्घाटन उप विकास आयुक्त श्री गौरव कुमार (IAS), डायरेक्टर श्री पुलक कुमार, जिला परियोजना प्रबंधक (जीविका) श्री श्लोक कुमार एवं अन्य गणमान्य अतिथियों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। उद्घाटन समारोह में बड़ी संख्या में जीविका दीदियों, जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों की सहभागिता रही। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप विकास आयुक्त श्री गौरव कुमार ने कहा कि जीविका भवन का निर्माण ग्रामीण महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि जीविका दीदियां अब केवल स्वयं सहायता समूहों तक सीमित न रहकर सामूहिक उद्यमों और उत्पादन आधारित गतिविधियों को

अपनाएं, जिससे आत्मनिर्भरता की दिशा में मजबूत कदम बढ़ाया जा सके। उन्होंने जीविका दीदियों को दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद, मखाना प्रसंस्करण, मक्का आधारित उत्पाद, सहजन से निर्मित उत्पाद तथा अपराजिता फूल के प्रसंस्करण एवं विपणन जैसे कुटीर उद्योगों की संभावनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इन क्षेत्रों में अपार संभावनाएं हैं और यदि महिलाएं संगठित होकर उत्पादन कंपनी के माध्यम से कार्य करें तो उनकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि संभव है। प्रखंड प्रमुख श्री शमीम अख्तर ने अपने संबोधन में जीविका दीदियों द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें आत्मनिर्भरता की दिशा में निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि जीविका योजना महिलाओं के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का एक सशक्त माध्यम बनकर उभरी है। इस अवसर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रिया भारती, प्रखंड परियोजना प्रबंधक आलोक मिश्रा, कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा मनीष झा, क्षेत्रीय समन्वयक संतोष मिश्रा तथा प्रभावती संकुल स्तरीय संघ की अध्यक्ष ललिता देवी सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सैकड़ों जीविका दीदियों की सक्रिय सहभागिता ने आयोजन को विशेष उत्साह और गरिमा प्रदान की। नवनिर्मित जीविका भवन अब स्थानीय जीविका समूहों की बैठकों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं आजीविका संवर्धन गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बनेगा, जिससे ग्रामीण महिलाओं को अपने सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए एक सशक्त मंच प्राप्त होगा।

बाढ़ में 7 वर्षीय बच्चे की करंट लगने से मौत

लोकतंत्र की शान , पटना

पटना जिले के बाढ़ अनुमंडल अंतर्गत गोपाईचक गांव में करंट लगने से सात वर्षीय एक बच्चे की मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। मृतक की पहचान सूरज कुमार के रूप में हुई है। घटना सकसोहरा थाना क्षेत्र की है।

दरवाजे के पास बेहोश पड़ा मिला बच्चाः जानकारी के अनुसार, परिजन रोजाना की तरह खेतों में काम करने गए हुए थे, जबकि मासूम सूरज घर पर अकेला था। जब परिवार के सदस्य खेत से लौटकर घर पहुंचे तो उन्होंने बच्चे को दरवाजे के पास बेहोश पड़ा देखा। परिजन आनन-फानन में बच्चे को इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल ले गए। वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।

करंट लगने की आशंकाः परिजनों के मुताबिक, सूरज को घर

♦ **खेत से लौटे परिजनों को दरवाजे पर मिला बेहोश, डॉक्टर ने किया मृत घोषित**

में किस स्थान पर और कैसे करंट लगा, इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं मिल सकी है। आशंका जताई जा रही है कि घर के दरवाजे के पास से गुजर रहे किसी तार में करंट रहा होगा, जिसकी चपेट में बच्चा आ गया। मृतक के दादा अरविंद प्रसाद ने बताया कि अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद करंट लगने से मौत की पुष्टि की है।

तेजप्रताप बोले- भाषा की मर्यादा रखिए, राबड़ी के पैर छूते सम्राट की तस्वीर शेयर की

लोकतंत्र की शान , पटना

राबड़ी आवास खाली करने के नोटिस पर विवाद बढ़ता जा रहा है। राबड़ी देवी ने कहा था हम बंगला खाली नहीं करेंगे। फोर्स बुलाकर खाली करवा लो। इस पर CM ने जवाब देते हुए कहा, बंगला खाली होकर रहेगा। कोई माई का लाल बंगला खाली करवाने से नहीं रोक सकता। ये किसी की बपौती नहीं। अब राबड़ी देवी के बेटी तेज प्रताप यादव कहा है कि, हम भविष्यवाणी करते हैं, 9 महीने के अंदर सम्राट सीएम की कुर्सी से हटेंगे। मुख्यमंत्री के पद की गरिमा का सम्मान करना चाहिए, लेकिन वह अपनी कुर्सी का सम्मान करने में असफल साबित हो रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने कहा कि सम्राट चौधरी उम्र में उनसे बड़े हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के पद पर बैठने के बावजूद वह उस पद की मर्यादा नहीं

रख पा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि आने वाले 6 से 9 महीनों के भीतर सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। इससे पहले तेजप्रताप ने फेसबुक पर राबड़ी के पैर छूते सम्राट चौधरी की तस्वीर पोस्ट की थी। उन्होंने लिखा कि, भाषा की मर्यादा बनाए रखिए। मुजफ्फरपुर में सहयोग शिविर में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राबड़ी देवी के बयान का जवाब दिया था। उन्होंने कहा था, 'कुछ लोगों को लगता है मेरा घर खाली हो जाएगा। पक्का खाली होगा।

बिहार के 4 जिलों का तापमान 40 डिग्री से ज्यादा, 7 दिनों तक रहेगी भीषण गर्मी

लोकतंत्र की शान , पटना

बिहार में पिछले दिनों से लगातार आंधी-बारिश हुई, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली थी। लेकिन अब मौसम का मिजाज बदल गया है। राज्य के अधिकतर जिलों में मौसम सामान्य है। 4 जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार बिहार में बुधवार को 5 जिलों में भीषण गर्मी पड़ने की संभावना है, हीटवेव का कोई अलर्ट नहीं है। इसमें कैमूर, रोहतास (डेहरी), औरंगाबाद, गया और पटना जिला शामिल हैं। इन जिलों में अधिकतम तापमान 43 डिग्री तक पहुंच सकता है। मंगलवार को कैमूर (भभुआ) 41.4 डिग्री के साथ सबसे गर्म रहा, जबकि डेहरी, भागलपुर और शेखपुरा में भी तापमान 40 डिग्री के आसपास दर्ज किया

गया। वहीं, सासाराम, गयाजी में आंधी-तूफान के साथ बारिश हुई। जबकि बक्सर, औरंगाबाद में बादल छाए रहे।

मानसून अभी बिहार से दूरः दक्षिण-पश्चिम मानसून अभी बिहार नहीं पहुंचा है। 12 से 16 जून के बीच बिहार पहुँचेगा। जब

♦ **44 डिग्री पहुंचेगा तापमान, 24 घंटे में गया-सासाराम में हुई बारिश**

तक मानसूनी बादल राज्य में सक्रिय नहीं होते, तब तक गर्म हवाओं और उमस का असर बना रहेगा। मानसून के आगे बढ़ने में हो रही देरी भी गर्मी बढ़ने का एक बड़ा कारण मानी जा रही है। दक्षिण-पश्चिम मानसून के 4 जून के आसपास केरल, तमिलनाडु, लक्षद्वीप तथा बंगाल की खाड़ी के कई और हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। इसके बाद मानसून धीरे-धीरे पूर्वी भारत की ओर बढ़ेगा। हालांकि बिहार में मानसून पहुंचने में अभी समय लगेगा। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि राज्य में मानसून की सक्रियता शुरू होने तक लोगों को गर्मी और उमस का सामना करना पड़ सकता है।

संक्षिप्त समाचार

साक्षी लॉ कॉलेज बढ़ौरा को मिली एलएलएम की मान्यता

(ऋचा पाण्डेय ब्यूरो प्रमुख) लोकतंत्र की शान सीधी। सिंगरौली का बना एकमात्र लॉ संस्थान , सेमरिया। शिक्षा के क्षेत्र में लगातार नए आयाम स्थापित कर रहे साक्षी लॉ कॉलेज बढ़ौरा ने एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। कॉलेज को अब एलएलबी के साथ एलएलएम पाठ्यक्रम संचालित करने की मान्यता प्राप्त हो गई है। जानकारी के अनुसार सीधी एवं सिंगरौली जिले में यह सुविधा उपलब्ध कराने वाला साक्षी लॉ कॉलेज वर्तमान में एकमात्र संस्थान बताया जा रहा है। कॉलेज के संचालक देवेन्द्र मिश्रा गुड्डू ने लंबे समय से क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत हैं। उन्होंने विद्यालय स्तर से लेकर उच्च शिक्षा तक विद्यार्थियों को बेहतर अवसर प्रदान करने की दिशा में लगातार कार्य किया है। संस्थान में कक्षा 1 से 12वीं तक की शिक्षा व्यवस्था संचालित है। इसके बाद बीएड. पाठ्यक्रम की मान्यता प्राप्त हुई और फिर लॉ कॉलेज की स्थापना की गई। अब एलएलएम की मान्यता मिलने से क्षेत्र के विद्यार्थियों को उच्च विधि शिक्षा के लिए बाहर जाने की आवश्यकता कम होगी। साक्षी लॉ कॉलेज की स्थापना का उद्देश्य क्षेत्र के विद्यार्थियों को बेहतर और सुलभ शिक्षा प्रदान करना है।

इनका कहना है। एलएलएम की मान्यता मिलना हमारे लिए गर्व का विषय है। इससे सीधी और सिंगरौली जिले के छात्र-छात्राओं को उच्च विधि शिक्षा के लिए बड़े शहरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। आगे भी हम शिक्षा की गुणवत्ता और नए पाठ्यक्रमों के विस्तार के लिए प्रयासरत रहेंगे। देवेन्द्र मिश्रा, संचालक साक्षी लॉ कॉलेज बढ़ौरा।

आईसीएसएसआर फेलोशिप से डॉ. अलका मिश्रा सम्मानित

(ऋचा पाण्डेय ब्यूरो प्रमुख) लोकतंत्र की शान सीधी। नई दिल्ली स्थित भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएसएसआर द्वारा डॉ. अलका मिश्रा पति भूपेश द्विवेदी को प्रतिष्ठित पोस्टडॉक्टोरल फेलोशिप प्रदान की गई है। यह फेलोशिप पीएचडी उपरांत उच्च स्तरीय शोध कार्य के लिए देशभर के चुनिंदा शोधार्थियों को कड़ी प्रतिस्पर्धा और कठोर चयन प्रक्रिया के बाद प्रदान की जाती है। इस उपलब्धि ने न केवल डॉ. मिश्रा के शैक्षणिक जीवन में एक नया आयाम जोड़ा है, बल्कि क्षेत्र के शोधार्थियों एवं विद्यार्थियों के लिए भी प्रेरणा का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। डॉ. अलका मिश्रा का शोध विषय रिवोल्यूशन इन इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इट्स इंपैक्ट ऑन सोशल इंस्टीट्यूशन एंड कल्चर ए कंपारेटिव स्टडी ऑफ रूरल एंड अर्बन सोसायटीज वर्तमान समय की सामाजिक आवश्यकताओं और चुनौतियों से गहराई से जुड़ा हुआ है। डॉ. मिश्रा ने विशेष रूप से अपने गुरु डॉ. महेश शुक्ला, सेवानिवृत्त प्राध्यापक एवं पूर्व विभागाध्यक्ष, टीआरएस कॉलेज रीवा के प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी यह उपलब्धि उनके मार्गदर्शन, प्रेरणा और आशीर्वाद का प्रत्यक्ष परिणाम है। इसके साथ ही उन्होंने महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. आलोक चौबे द्वारा समय-समय पर दिए गए महत्वपूर्ण सुझावों के लिए आभार व्यक्त किया।

फतेहाबादः नहर में नहाने गया नवविवाहित युवक तेज बहाव में बहा

लोकतंत्र की शान : फतेहाबाद। जिले के टोहाना क्षेत्र के गांव रहनवाली के पास नहर में नहाने गया एक 21 वर्षीय नवविवाहित युवक पानी के तेज बहाव की चपेट में आने से बह गया। यह दर्दनाक हादसा मंगलवार को उस समय हुआ जब युवक अपने दोस्तों और चचेरे भाई के साथ नहर में उतरा था। सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुँची और राहत कार्य शुरू किया। लापता युवक की तलाश के लिए बुधवार को हिसार से गोताखोरों की विशेष टीम बुलाई गई है, जो नहर में गहन सर्च ऑपरेशन चला रही है। मिली जानकारी के अनुसार, जाखल की नायक बस्ती का रहने वाला 21 वर्षीय राहुल अपने चचेरे भाई सुमित और दोस्तों गौरव व प्रिंस के साथ गांव रहनवाली के पास नहर में नहाने आया था। चारों युवक पानी में उतरे ही थे कि अचानक पानी का बहाव बेहद तेज हो गया। राहुल इस तेज धार की चपेट में आ गया और बहने लगा। उसके दोस्तों ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाने का काफी प्रयास किया, लेकिन पानी का थपेड़ा इतना जोरदार था कि वे खुद को संभाल नहीं पाए और देखते ही देखते राहुल उनकी आँखों के सामने से ओझल हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही सदर थाना के एडिशनल थाना प्रभारी हरदयाल सिंह पुलिस टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुँचे। स्थानीय स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने के साथ ही बुधवार को हिसार से गोताखोरों की टीम को रेस्क्यू के लिए बुलाया गया। समाचार लिखे जाने तक राहुल का कोई सुराग नहीं मिल पाया था। पुलिस ने एहतियात के तौर पर नहर के किनारे बसे आसपास के अन्य गाँवों में भी अलर्ट जारी कर दिया है, ताकि शव दिखने पर तुरंत सूचना मिल सके।सात महीने पहले ही हुई थी शादी, परिवार में कोहरामइस हादसे के बाद से राहुल के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। राहुल की मां मंजू का रो-रोकर बुरा हाल है। उन्होंने बताया कि राहुल की शादी अभी महज 7 महीने पहले ही हुई थी। वह अपने पीछे दो बहनें, एक भाई और पत्नी को छोड़ गया है।

नशा तस्करों पर नागौर पुलिस का बड़ा प्रहार, 37 लाख की संपत्ति फ्रीज

लोकतंत्र की शान

नागौर/ मेड़ता रोड , एजाज़ अहमद उस्मानी। नागौर जिले में चलाए जा रहे "नशा मुक्त नागौर अभियान" के तहत नागौर पुलिस ने नशे के कारोबार से अर्जित संपत्ति के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक तस्कर की लाखों रुपये की संपत्ति फ्रीज करवा दी। यह कार्रवाई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) नागौर श्री आशाराम चौधरी के निर्देशन में की गई। पुलिस के अनुसार थाना पांचौड़ी क्षेत्र के रामस्वरूप बिश्नोई द्वारा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित आय से गांव चावण्डिया में एक आलीशान मकान तथा एक बड़े हॉल का निर्माण करवाया गया था। जांच में सामने आया कि उक्त संपत्ति नशे के अवैध कारोबार से प्राप्त धन से बनाई गई थी। इसके बाद पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 68 एफ के तहत कार्रवाई करते हुए संपत्ति को फ्रीज करवाने की प्रक्रिया शुरू की। पुलिस की प्रभावी पैरवी और साक्ष्यों के आधार पर सक्षम प्राधिकारी, नई दिल्ली द्वारा फ्रीजिंग आदेश को भी पुष्टि प्रदान कर दी गई। फ्रीज की गई संपत्ति की बाजार कीमत लगभग 37 लाख रुपये आंकी गई है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार रामस्वरूप बिश्नोई एवं उसके साथियों के विरुद्ध पूर्व में की गई कार्रवाई में काले रंग के प्लास्टिक के 51 कट्टों में कुल 801 किलो 600 ग्राम डोडा पोस्त बरामद किया गया था। जांच में आरोपी को डोडा पोस्त तस्करी का बड़ा कारोबारी पाया गया, जिसने अवैध कमाई से यह संपत्ति खड़ी की थी। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी ने उक्त मकान और हॉल अपनी माता के नाम करवा रखे थे, ताकि संपत्ति को कानूनी कार्रवाई से बचाया जा सके। हालांकि पुलिस की गहन जांच और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर संपत्ति को फ्रीज कराने में सफलता मिली। नागौर पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नशे का कारोबार कर समाज को नुकसान पहुंचाने वाले अपराधियों के विरुद्ध आगे भी इसी प्रकार की कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। इस पूरी कार्रवाई में थाना पांचौड़ी पुलिस टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिसकी जिलेभर में सराहना की जा रही है।

41 नव आरक्षकों को नियुक्ति आदेश जारी, पुलिस अधीक्षक श्री अभिनय विश्वकर्मा ने सौंपे नियुक्ति पत्र

लोकतंत्र की शान हसन रसीद जिला ब्यूरो चीफ जबलपुर कटनी मध्य प्रदेश

पुलिस अधीक्षक कटनी अभिनय विश्वकर्मा के द्वारा आज दिनांक 03 जून 2026 को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में नव नियुक्त 41 नव आरक्षकों को औपचारिक रूप से नियुक्ति आदेश प्रदान किए गए। नियुक्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद अभ्यर्थियों में खुशी और उत्साह का माहौल देखने को मिला। उन्होंने सभी नव आरक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि "आरक्षक पद पुलिस संगठन की रीढ़ होता है। समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखने, आमजन में सुरक्षा का भाव स्थापित करने और अपराधों पर नियंत्रण हेतु आरक्षक की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है।" पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित आरक्षक भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई। भर्ती प्रक्रिया में लिखित परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन, शारीरिक दक्षता परीक्षण, मेडिकल एवं चरित्र सत्यापन किया गया। शारीरिक दक्षता परीक्षण में 800 मीटर दौड़, लंबी कूद एवं गोला फेंक शामिल थे। मेडिकल बोर्ड द्वारा वीडियोग्राफी की मौजूदगी में चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। इसके बाद पात्र पाए गए अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रमाण पत्र दिए गए। कटनी पुलिस परिवार में शामिल हुए सभी नव नियुक्त आरक्षकों को उनके सफल एवं गौरवपूर्ण पुलिस जीवन के लिए शुभकामनाएं दी गईं।

रूपनगर में प्रशासन की बड़ी कार्रवाईः वर्षों से बंद पड़ा सार्वजनिक मार्ग हुआ बहाल

लोकतंत्र की शान

नागौर/ मेड़ता रोड , एजाज़ अहमद उस्मानी। जिला प्रशासन नागौर द्वारा चलाए जा रहे "रास्ता खोलो अभियान" के तहत जायल तहसील के ग्राम रूपनगर में वर्षों पुराने अतिक्रमण को हटाकर एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक रास्ते को आमजन के लिए पुनः खोल दिया गया। इस कार्रवाई से ग्रामीणों को आवागमन में होने वाली परेशानियों से राहत मिली है। जानकारी के अनुसार ग्राम रूपनगर स्थित खसरा संख्या 568 में दर्ज गैर मुमकिन रास्ता, जो बरनानाडा से बालाजीनगर होते हुए खसरा संख्या 567 एवं 634 तक जाता है, लंबे समय से कच्चे अतिक्रमण की चपेट में था। करीब एक किलोमीटर से अधिक लंबे और पर्याप्त चौड़ाई वाले इस मार्ग के बाधित होने से ग्रामीणों को रोजमर्रा के आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार के निर्देश एवं उपखंड अधिकारी जायल के मार्गदर्शन में तहसीलदार जायल के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का निरीक्षण किया। प्रशासन द्वारा ग्रामीणों से संवाद स्थापित कर आपसी सहमति एवं समझाइश के माध्यम से अतिक्रमण हटवाया गया। मार्ग खुलने के बाद क्षेत्र के लोगों में खुशी का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से बंद पड़े रास्ते के खुलने से अब आवागमन सुगम हो गया है और समय की भी बचत होगी। प्रशासन की इस पहल को ग्रामीणों ने जनहित में उठाया गया सराहनीय कदम बताया है। "रास्ता खोलो अभियान" के तहत जिले में सार्वजनिक रास्तों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार जारी है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आमजन को उनके वैध मार्गों का लाभ मिल रहा है।

अवैध रेत भंडारण पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 30 ट्रॉली रेत जब्त

(ऋचा पाण्डेय ब्यूरो प्रमुख) लोकतंत्र की शान

सीधी। जिले में अवैध खनन एवं भंडारण के विरुद्ध प्रशासन का अभियान लगातार जारी है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी विकास मिश्रा तथा पुलिस अधीक्षक संतोष कोरी के निर्देशन में खनिज विभाग और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने ग्राम निधिपुरी, तहसील मड़वास में अवैध रेत भंडारण के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करते हुए लगभग 30 ट्रॉली रेत जब्त की है। जिला खनिज अधिकारी कपिलमुनि शुक्ला के मार्गदर्शन में की गई इस कार्रवाई के दौरान ग्राम पंचायत धुम्माडोल के सरपंच, सचिव एवं ग्रामीणजन उपस्थित रहे। खनिज रेत के अवैध उत्खनन एवं भंडारण संबंधी लगातार प्राप्त शिकायतों के आधार पर संयुक्त दल ने ग्राम निधिपुरी के विभिन्न स्थलों का निरीक्षण किया। जांच में विभिन्न स्थानों पर खनिज रेत लावारिस अवस्था में भंडारित पाई गई। मौके पर उपस्थित ग्रामीणों ने बताया कि निकट स्थित गोपद नदी घाट से आसपास के क्षेत्रों के लोगों द्वारा अवैध रूप से रेत का उत्खनन कर उसका भंडारण किया गया था। अधिकारियों द्वारा की गई पैमाइश में लगभग 30 ट्रॉली रेत का अवैध भंडारण पाया गया। संयुक्त दल ने नियमानुसार कार्रवाई करते हुए जब्त रेत को हाइवा वाहन के माध्यम से उठवाकर अभिरक्षा में लिया। मामले में अवैध भंडारण एवं उत्खनन में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम-2022 एवं मध्यप्रदेश खनिज रेत नियम-2019 के तहत प्रकरण तैयार कर अग्रिम कार्रवाई के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी तथा खनिज संपदा के अवैध दोहन में संलिप्त व्यक्तियों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा।

मेड़ता रोड–ढावा जलापूर्ति लाइन में अवैध कनेक्शन पकड़ा

» विभाग ने हटाया, कहा एफआईआर भी होगी दर्ज

लोकतंत्र की शान

मेड़ता रोड , एजाज़ अहमद उस्मानी। जलदाय विभाग ने अवैध जल कनेक्शनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बुधवार को मेड़ता रोड पम्प हाउस से ढावा उच्च जलाशय तक जाने वाली 150 एमएम राइजिंग पाइपलाइन पर किया गया एक अवैध कनेक्शन हटाया। विभागीय जांच में यह अवैध कनेक्शन भेरा राम भाकल निवासी ढावा के नाम से पाया गया, जिसे मौके पर ही हटाकर पाइपलाइन को पुनः व्यवस्थित किया गया। जानकारी के अनुसार ग्राम ढावा में लंबे समय से अवैध जल कनेक्शनों की शिकायतें विभाग को प्राप्त हो रही थीं। शिकायतों के आधार पर जलदाय विभाग की टीम ने जांच अभियान चलाया, जिसमें मुख्य जलापूर्ति लाइन से किया गया अवैध कनेक्शन पकड़ा गया। विभाग का कहना है कि ऐसे अवैध कनेक्शनों के कारण जलापूर्ति व्यवस्था प्रभावित होती है तथा अन्य उपभोक्ताओं को पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता। एईएन निशा बुगालिया ने बताया कि विभाग द्वारा अवैध जल कनेक्शन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। बुधवार को पकड़े गए अवैध कनेक्शन को तत्काल प्रभाव से हटाया गया है। उन्होंने कहा कि ग्राम ढावा सहित अन्य क्षेत्रों में भी जांच अभियान जारी रहेगा और जहां कहीं भी अवैध कनेक्शन पाए जाएंगे, उन्हें हटाया जाएगा। बुगालिया ने चेतावनी देते हुए कहा कि अवैध रूप से जलापूर्ति लाइन से कनेक्शन लेने वाले लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी तथा नियमानुसार जुर्माना भी वसूला जाएगा। उन्होंने आमजन से अपील की कि वे वैध प्रक्रिया के तहत ही जल कनेक्शन लें और जलदाय विभाग को अवैध कनेक्शनों की जानकारी देकर सहयोग करें। विभाग की इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में अवैध जल कनेक्शन करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। अधिकारियों का कहना है कि जल संसाधनों के संरक्षण और सुचारू जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भविष्य में भी ऐसे अभियान लगातार चलाए जाएंगे।

मासिक क्राइम मीटिंग में पुलिस अधीक्षक के सख्त निर्देश

अपराध नियंत्रण, महिला सुरक्षा, साइबर अपराध एवं आगामी त्यौहारों की सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष फोकस

(ऋचा पाण्डेय ब्यूरो प्रमुख) लोकतंत्र की शान

सीधी। पुलिस अधीक्षक सीधी संतोष कोरी के नेतृत्व में आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय सीधी में जिले की मासिक क्राइम मीटिंग आयोजित की गई। बैठक में जिले की कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण एवं पुलिस कार्यप्रणाली की विस्तृत समीक्षा करते हुए आगामी कार्ययोजना निर्धारित की गई। बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा जिले के अपराधों की त्रिवर्षीय तुलनात्मक समीक्षा की गई तथा गंभीर अपराधों के त्वरित निराकरण, महिला एवं बाल सुरक्षा, साइबर अपराधों की रोकथाम, मादक पदार्थों के विरुद्ध कार्रवाई, लंबित प्रकरणों के निष्पादन एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के प्रभावी उपयोग पर विशेष जोर दिया गया। पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना एवं चौकी प्रभारियों को निर्देशित किया कि आमजन की सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की कार्यवाही परिणाममूलक एवं समयबद्ध होनी चाहिए।

भवन के अभाव से जूझ रहा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मझौली

» बंद हो गया कई योजनाओं का क्रियान्वयन,
» बढ़ती मरीजों की संख्या बन रहा परेशानी का सबब

(ऋचा पाण्डेय ब्यूरो प्रमुख) लोकतंत्र की शान

सीधी। जिला अंतर्गत संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मझौली इन दिनों भवन के अभाव से जूझ रहा है जिस कारण एक तरफ जहां कई योजनाओं का क्रियान्वयन बंद हो गया है वहीं दूसरी तरफ बढ़ती मरीजों की संख्या से मरीज और अस्पताल के स्टाफ भी परेशान हो रहे हैं। बताते चलें कि चार दशक पूर्व से जहां अस्पताल संचालित रहती थी उसे डिस्मेंटल घोषित कर दिया गया है और वहां नये अस्पताल भवन की निविदा जारी हो गई है लेकिन चार माह पूर्व उस भवन को खाली कर वैकल्पिक भवन जिसमें आजीविका केंद्र संचालित होता था उसमे अस्पताल संचालित करा दिया गया है जिसमें भवन एवं कक्षों की संख्या काफी कम है ऐसे में जब गर्मी के सीजन में मरीजों की संख्या लगभग 150 के औसत से रहती है जो बरसात में सीधे दो से तीन गुना हो सकती है जिस कारण अस्पताल रोग निदान के बजाय रोग संक्रामक केंद्र बन सकता है जिससे बड़ी समस्या पैदा हो सकती है।

निविदा स्वीकृति होने के बाद भी नहीं शुरू हुआ कम

निविदा स्वीकृत होने के 4 माह बाद भी ना तो पुराने भवन को डिस्मेंटल किया जा सका और ना ही कार्य शुरू किया गया है जिससे सोचा जा सकता है कि निर्माण कार्य की रफ्तार क्या होगी। वैसे भी जानकारों की माने तो अगर नियमित रूप से कार्य जारी रहेगा तो भी लगभग 5 वर्ष निर्माण कार्य में लग सकते हैं ऐसे में 5 वर्षों तक जिस वैकल्पिक भवन में अस्पताल संचालित है वह नाकाफी होगा और स्थानीय प्रशासन को अन्य भवन के बारे में विचार करना जरूरी होगा।

सोशल मीडिया वॉरियर अभियान से युवाओं को मिलेगा कांग्रेस से जुड़ने का अवसर : अमित शुक्ला

» उपशीर्षकः कांग्रेस कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में सोशल मीडिया वॉरियर अभियान की दी गई जानकारी

लोकतंत्र कि शान हसन रशीद जिला ब्यूरो चीफ जबलपुर कटनी मध्य प्रदेश

कटनी। जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में कांग्रेस के पदाधिकारियों ने "सोशल मीडिया वॉरियर अभियान" की जानकारी देते हुए इसे संगठन विस्तार और जनसंपर्क को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी शहर अध्यक्ष एडवोकेट अमित शुक्ला ने कहा कि सोशल मीडिया वॉरियर अभियान के माध्यम से युवाओं को कांग्रेस संगठन से जुड़ने का सीधा, खुला और सरल अवसर प्रदान किया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य सोशल मीडिया पर सक्रिय लोगों को वर्तमान राजनीतिक संघर्ष में सकारात्मक भूमिका निभाने का मंच उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि यह अभियान विशेष रूप से राइटर, डिज़ाइनर, एडिटर्स, कार्टूनिस्ट, कवि, गजलकार, ऑथर्स, ब्लॉगर्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स, सोशल वर्कर्स तथा एंटरटेनमेंट और लोक कला से जुड़े कलाकारों को कांग्रेस की विचारधारा से जोड़ने का माध्यम बनेगा। इसके जरिए संगठन में रहकर अथवा परोक्ष रूप से कांग्रेस के लिए कार्य करने के इच्छुक लोगों को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। अभियान के तहत प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा से नई पीढ़ी के युवाओं को तलाशकर संगठन से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही महिला वर्ग को भी सोशल मीडिया के माध्यम से सक्रिय भूमिका निभाने और संगठन को सहयोग प्रदान करने का अवसर मिलेगा। पत्रकार वार्ता में बताया गया कि मीडिया जगत से जुड़े फ्रीलांस पत्रकारों, न्यूज एंकरों और इंडिपेंडेंट रिपोर्टर्स को भी एक सीधा संवाद मंच उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे वे जनहित के मुद्दों को प्रभावी ढंग से सामने ला सकें। अभियान के माध्यम से कांग्रेस जनता के साथ अपने संवाद और पब्लिक कम्युनिकेशन को और अधिक मजबूत एवं प्रभावी बनाने का प्रयास करेगी। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी शहर अध्यक्ष एड अमित शुक्ला,प्रदेश उपाध्यक्ष आईटी सेल विवेक भोसले, सेवा अध्यक्ष मुकेश परोहा, ब्लॉक अध्यक्ष जितेन्द्र गुप्ता, अभय खरे, रमेश अहिरवार, विनोद अहिरवार, हर्षित मिश्रा एवं शाहिल नामदेव सहित अन्य कांग्रेस पदाधिकारी उपस्थित रहे।उपशीर्षकः कांग्रेस कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में सोशल मीडिया वॉरियर अभियान की दी गई जानकारी, युवाओं, महिलाओं और सोशल मीडिया से जुड़े लोगों को संगठन से जोड़ने पर जोर।

संक्षिप्त समाचार

होर्मुज खोलने भर से नहीं हटेंगे प्रतिबंध, अमेरिका ने ईरान को दिया स्पष्ट संदेश

वॉशिंगटन। अमेरिका ने स्पष्ट कर दिया है कि केवल होर्मुज जलडमरूमध्य को पूरी तरह खोल देने से ईरान पर लगाए गए आर्थिक और व्यापारिक प्रतिबंध समाप्त नहीं किए जाएंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि प्रतिबंधों में किसी भी प्रकार की राहत के लिए ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम और उच्च स्तर पर संवर्धित यूरेनियम से जुड़े मुद्दों पर ठोस समझौता करना होगा। रूबियो ने अमेरिकी सांसदों के साथ बातचीत में कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य को खोलने के बदले प्रतिबंध हटाने का कोई प्रस्ताव न तो ईरान को दिया गया है और न ही ऐसी किसी व्यवस्था पर विचार किया जा रहा है। उनके अनुसार, प्रतिबंधों में ढील तभी संभव है जब परमाणु गतिविधियों को लेकर अंतरराष्ट्रीय समुदाय की चिंताओं का समाधान हो। इस बीच, अमेरिकी विदेश मंत्री ने ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल की हालिया सैन्य कार्रवाई को भी सफल बताया। उन्होंने कहा कि "ऑपरेशन एपिक फ्यूरी" ने अपने प्रमुख सैन्य लक्ष्य हासिल किए हैं और इससे ईरान के रक्षा ढांचे को गंभीर क्षति पहुंची है। रूबियो के मुताबिक, इस अभियान को लेकर अलग-अलग मत हो सकते हैं, लेकिन सैन्य दृष्टि से यह अपने उद्देश्यों को पूरा करने में सफल रहा है। उन्होंने दावा किया कि कार्रवाई के परिणामस्वरूप ईरान की नौसैनिक क्षमताओं को भी भारी नुकसान पहुंचा है। अमेरिकी प्रशासन का यह बयान ऐसे समय आया है जब पश्चिम एशिया में तनाव कम करने और समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगातार चर्चा चल रही है। होर्मुज जलडमरूमध्य वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि दुनिया के बड़े हिस्से का तेल और गैस निर्यात इसी मार्ग से होकर गुजरता है।

दक्षिणी लेबनान में बढ़ती हिंसा पर स्पेन चिंतित, युद्धविराम के पालन की अपील

मैड्रिड। स्पेन ने दक्षिणी लेबनान में फिर बढ़ रही हिंसा पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए सभी पक्षों से संयम बरतने और युद्धविराम समझौते का सम्मान करने की अपील की है। स्पेन के विदेश मंत्रालय ने जारी बयान में कहा है कि इजराइल के सैन्य अभियानों और हिजबुल्लाह के हमलों के कारण क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति लगातार बिगड़ रही है। मंत्रालय के अनुसार, दोनों पक्षों की कार्रवाई से तनाव कम होने के बजाय और बढ़ रहा है। स्पेन ने विशेष रूप से 16 अप्रैल को हुए युद्धविराम समझौते के पालन पर जोर दिया और कहा कि क्षेत्र में स्थायी शांति के लिए सभी पक्षों को अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करना चाहिए। मंत्रालय का मानना है कि दक्षिणी लेबनान में इजराइली जमीनी अभियानों के विस्तार से शांति बहाली के प्रयासों को झटका लग सकता है। विदेश मंत्रालय ने चेतावनी दी कि बढ़ती सैन्य गतिविधियां न केवल मानवीय संकट को और गंभीर बना रही हैं, बल्कि क्षेत्रीय स्तर पर जारी कूटनीतिक प्रयासों और वार्ताओं को भी प्रभावित कर सकती हैं। स्पेन ने नागरिकों की मौत, आवासीय क्षेत्रों और आवश्यक बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान पर भी चिंता जताई। इसके अलावा स्वास्थ्यकर्मियों और चिकित्सा संस्थानों पर पड़ रहे प्रभाव को लेकर भी गंभीर चिंता व्यक्त की गई। स्पेन ने अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के सम्मान की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में नागरिकों और राहत कार्यों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। साथ ही उसने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से भी क्षेत्र में तनाव कम करने और राजनीतिक समाधान को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया।

कुवैत में भारतीयों की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस महासचिव ने विदेश मंत्री को लिखा पत्र

नई दिल्ली। कांग्रेस महासचिव (संगठन) और संसद की लोक लेखा समिति (पीएसी) के अध्यक्ष केसी वेणुगोपाल ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को पत्र लिखकर कुवैत हवाई अड्डे पर ईरानी ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद वहां फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर तत्काल कदम उठाने की अपील की है। केसी वेणुगोपाल ने पत्र में कहा कि हमलों के बाद हवाई अड्डा और उसके आसपास बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं और वे भय तथा अनिश्चितता की स्थिति में हैं। उन्होंने विदेश मंत्रालय से संकट प्रबंधन उपायों को युद्धस्तर पर शुरू करने का अनुरोध किया है। उन्होंने पत्र में विदेश मंत्री से भारतीय दूतावास को निर्देश देकर कि सभी भारतीय नागरिकों को तुरंत सुरक्षित शरणस्थलों स्थानांतरित कराने की अपील की। साथ ही, उन्होंने पत्र में हवाई अड्डा प्राधिकरण और कुवैत सरकार के साथ समन्वय कर भोजन और चिकित्सा सहायता की तत्काल व्यवस्था करने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को सभी संबंधित एयरलाइनों को सख्ती से निर्देश देना चाहिए कि वे यह पक्का करें कि सभी प्रभावित यात्रियों के लिए यात्रा री-शेड्यूलिंग पूरी तरह से फ्री की जाए।

वेणुगोपाल ने पत्र में यात्रियों की सुविधा के लिए 24x7 आपातकालीन टोल-फ्री हेल्पलाइन स्थापित करने का सुझाव भी दिया। उन्होंने कहा कि आपातकालीन टोल-फ्री हेल्पलाइन स्थापित होने से वहां फंसे हुए भारतीयों को समय पर जानकारी और सहायता मिल सकेगी। उन्होंने उन यात्रियों के लिए आपातकालीन सर्टिफिकेट जारी करने की भी मांग की है जिनके यात्रा दस्तावेज खो गए हैं, ताकि उनकी भारत वापसी सुनिश्चित हो सके। उल्लेखनीय है कि कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ईरान ने मिसाइल और ड्रोन से हमला कर दिया। एयरपोर्ट के टर्मिनल-1 को निशाना बनाकर मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए, जिनमें कई लोग घायल हो गए और एयरपोर्ट की इमारत को भारी नुकसान पहुंचा है। अब तक एक व्यक्ति की मौत की खबर भी है। घटना के बाद सभी उड़ानों की आवाजाही तत्काल प्रभाव से रोक दी गई है। कुवैत की पब्लिक अथॉरिटी फॉर सिविल एविएशन (पीएसीए) ने बताया कि हमले के बाद एयरपोर्ट का इमरजेंसी प्लान सक्रिय कर दिया गया है। पीएसीए प्रवक्ता अब्दुल्ला अल-राजही ने कहा कि यात्रियों, कर्मचारियों और एयरपोर्ट सुविधाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी निर्धारित प्रोटोकॉल लागू किए जा रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि टर्मिनल-1 पर ड्रोन और मिसाइलों के हमले के बाद एयर ट्रैफिक पूरी तरह निलंबित कर दिया गया है। कई उड़ानों को आसपास के दूसरे एयरपोर्ट की ओर डायवर्ट किया गया है। तकनीकी और सुरक्षा एजेंसियां इरान के ताजा हमले के बाद नुकसान का आकलन कर रही हैं।

आईआईएमसी में एमए और पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू

नई दिल्ली। भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए एमए और पीजी डिप्लोमा कार्यक्रमों में प्रवेश हेतु ई-काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक अभ्यर्थी 7 जून तक ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं, जबकि प्रथम सीट आवंटन 9 जून को जारी किया जाएगा। आईआईएमसी ने इस वर्ष तीन नए एमए कार्यक्रम की शुरुआत की है जिसमें हेल्थ कम्युनिकेशन, मीडिया एंड कम्युनिकेशन गवर्नेंस तथा कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन एंड ब्रांड मैनेजमेंट शामिल हैं। इसके साथ ही संस्थान अब अपने छह परिसरों में कुल छह एमए कार्यक्रम संचालित करेगा। बुधवार को संस्थान के प्रवेश प्रभारी एवं परीक्षा नियंत्रक प्रो. राकेश कुमार गोस्वामी ने बताया कि सभी एमए और पीजी डिप्लोमा कार्यक्रमों में प्रवेश, केवल ई-काउंसलिंग के माध्यम से किया जाएगा। संस्थान के चार पारंपरिक पीजी डिप्लोमा कार्यक्रम- अंग्रेजी पत्रकारिता, हिंदी पत्रकारिता, रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता तथा विज्ञापन एवं जनसंपर्क भी इस वर्ष उपलब्ध रहेंगे। एमए कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों के पास न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक डिग्री और सीयूईटी-पीजी (सीओक्यूपी17) में वैध स्कोर होना आवश्यक है। वहीं, पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए स्नातक डिग्री के साथ सीयूईटी-पीजी स्कोर अनिवार्य है। चयनित अभ्यर्थियों को प्रवेश के लिए 20 हजार रुपये की सीट स्वीकृति शुल्क जमा करनी होगी। संस्थान ने अभ्यर्थियों को आवेदन से पूर्व प्रवेश सूचना और प्रॉस्पेक्टस ध्यानपूर्वक पढ़ने तथा अपनी प्राथमिकताएं सोच-समझकर भरने की सलाह दी है।

पुराने ट्रक-बस बदलने की 9,585 करोड़ की योजना को मंजूरी

एजेंसी, नई दिल्ली

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली-एनसीआर में पुराने ट्रक और बसों को बदलने के लिए 9,585 करोड़ रुपये की दो वर्षीय योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत पुराने ट्रक और बसों को बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एनसीआरपीबी) को सहयोग दिया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य वायु प्रदूषण कम करना और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देना है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इससे जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में पत्रकारों को बताया कि इस योजना को आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के तहत एनसीआरपीबी द्वारा वित्तपोषित किया जाएगा और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा लागू किया जाएगा। इसमें दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारें भी भागीदार होंगी।

योजना के तहत केंद्र सरकार 5,041 करोड़ रुपये देगी और राज्यों द्वारा लगभग 1,601 करोड़ रुपये कर रियायतों के रूप में दिए जाएंगे। योजना का लाभ दिल्ली-एनसीआर में पंजीकृत बीएस-IV या उससे पुराने मानक वाले ट्रक और बस मालिकों को मिलेगा, जिन्हें बीएस-VI या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण गंभीर चुनौती बना हुआ है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआई) और टेरी की रिपोर्टों में बताया गया है कि परिवहन क्षेत्र से पीएम 2.5 का 14 प्रतिशत, कार्बन मोनोऑक्साइड का 40 प्रतिशत और नाइट्रोजन ऑक्साइड का 63 प्रतिशत उत्सर्जन होता है। ट्रक और बसें कुल बेड़े का केवल 3 प्रतिशत होते हुए भी पीएम 2.5 उत्सर्जन में 36 प्रतिशत योगदान करती हैं।

योजना से लगभग 2.07 लाख वाहन मालिकों (1.91 लाख ट्रक और 16,329 बसें) को लाभ मिलेगा। बीएस-III या पुराने वाहनों को पंजीकृत स्क्रैपिंग केंद्रों पर नष्ट करना अनिवार्य होगा, जबकि बीएस-IV वाहनों को स्क्रैप या एनसीआर के बाहर गैर-एनसीएपी शहरों में बेचा जा सकेगा। दिल्ली में हल्के मालवाहक वाहन केवल इलेक्ट्रिक ही होंगे, जबकि बसें बीएस-VI सीएनजी या इलेक्ट्रिक ही होंगी। योजना के लाभों में केंद्र सरकार द्वारा पांच वर्ष तक ऋण पर 5 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी, मासिक ईंधन वाउचर (अधिकतम 4,800 रुपये), इलेक्ट्रिक वाहन खरीद पर एकमुश्त लाभ और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ट्रेडिंग शामिल हैं। राज्य सरकारें पंजीकरण शुल्क माफ करेंगी और नए वाहनों पर 100 प्रतिशत तक मोटर वाहन कर रियायत तथा पुराने वाहनों पर 50 प्रतिशत तक रियायत देंगी। लंबित देनदारियां भी माफ की जाएंगी। वैष्णव ने बताया कि ऑटोमोबाइल कंपनियां एक्स-शोरूम कीमत पर 8 प्रतिशत तक की छूट देंगी। योजना का क्रियान्वयन पूरी तरह डिजिटल पोर्टल के माध्यम से होगा, जिसमें वास्तविक समय में पात्रता जांच, ब्याज सब्सिडी दावे, ईंधन वाउचर क्रेडिट और प्रदूषण घटाने के परिणामों की निगरानी होगी।

पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सभी कमेटियां और फ्रंटल संगठन भंग

एजेंसी, कोलकाता

पश्चिम बंगाल की राजनीति में चल रहे उथल-पुथल के बीच तृणमूल कांग्रेस ने बुधवार को बड़ा संगठनात्मक फैसला लेते हुए राज्य में पार्टी की सभी कमेटियों और सभी फ्रंटल संगठनों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। यह घोषणा पार्टी की ओर से आधिकारिक बयान जारी कर की गई। यह फैसला ऐसे समय आया है जब विधानसभा में पार्टी के 58 विधायकों द्वारा उलूबेड़िया से तृणमूल विधायक ऋतब्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता बनाने की मांग करते हुए विधानसभा अध्यक्ष को हस्ताक्षरयुक्त पत्र सौंपे जाने की खबर सामने आई है। इसके बाद से तृणमूल कांग्रेस के भीतर बढ़ते असंतोष और संगठनात्मक संकट को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं।

पार्टी ने अपने बयान में कहा है कि पश्चिम बंगाल में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की सभी कमेटियां तथा उसके सभी फ्रंटल संगठन को तत्काल प्रभाव से भंग किए जाते हैं। साथ ही संगठन के हर स्तर पर आत्ममंथन, कार्य निष्पादन की समीक्षा और संगठनात्मक मूल्यांकन की व्यापक प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तृणमूल कांग्रेस ने स्पष्ट किया है कि इस समीक्षा प्रक्रिया के निष्कर्षों के आधार पर पार्टी के मूल संगठन और सभी फ्रंटल संगठनों की नई संरचना तैयार की जाएगी। पुनर्गठित संगठन की घोषणा उचित समय पर की जाएगी।

पार्टी ने अपने बयान में यह भी कहा कि वह संगठन को और अधिक मजबूत बनाने तथा भविष्य की चुनौतियों का सामना नई ऊर्जा और उद्देश्य के साथ करने के लिए प्रतिबद्ध है। दरअसल, हाल के दिनों में कथित हस्ताक्षर विवाद, विपक्ष के नेता के पद को लेकर खींचतान और विधायकों के एक वर्ग की खुली नाराजगी के बाद तृणमूल कांग्रेस का यह फैसला संगठन के भीतर व्यापक बदलाव और शक्ति संतुलन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

मणिपुर में हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद, दो उग्रवादी कैडर गिरफ्तार

एजेंसी, इम्फाल

मणिपुर में सुरक्षा बलों ने अलग-अलग अभियानों में बड़ी सफलता हासिल करते हुए भारी मात्रा में हथियार एवं विस्फोटक बरामद किए हैं, जबकि प्रतिबंधित उग्रवादी संगठनों के दो कैडरों को गिरफ्तार किया गया है। मणिपुर पुलिस द्वारा बुधवार को जारी सूचना के अनुसार सुरक्षा बलों ने मंगलवार को थौबल जिले के यारिपोक थाना क्षेत्र स्थित पेची चिंगलाक इलाके की पहाड़ी तलहटी में तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान एक एके राइफल, एक डबल बैरल बंदूक, दो सिंगल बैरल बंदूकें, तीन 36 एचई हैंड ग्रेनेड, एक चीनी हैंड ग्रेनेड, चार डेटोनेटर, विभिन्न मैगजीन, 25 जिंदा एके कारतूस, सात 12 बोर कारतूस तथा एक बाओफेंग रेडियो हैंडसेट और चार्जर सहित बड़ी मात्रा में हथियार एवं गोला-बारूद बरामद किया गया।

इसके अलावा, एक अन्य अभियान में सुरक्षा बलों ने प्रतिबंधित संगठन केसीपी (पीडब्ल्यूजी) के सक्रिय कैडर कोमोल मुक्तार अबास उर्फ कराती (25) को इम्फाल पूर्व जिले के एंड्रो थाना क्षेत्र अंतर्गत यारिपोक तुलिहाल तौपोकपी स्थित उसके आवास से गिरफ्तार किया। एक अलग कार्रवाई में प्रतिबंधित संगठन प्रेपाक (प्रो) के सक्रिय कैडर यांगलेम अनाओबा सिंह उर्फ याम्बा (23) को इम्फाल पश्चिम जिले के वांगोई थाना क्षेत्र अंतर्गत हियांगथांग पुल के पूर्वी हिस्से से गिरफ्तार किया गया। वह इम्फाल पश्चिम जिले के सिंगजामेई चिंगामाखा यांगलेम लीराक का निवासी है। सुरक्षा एजेंसियों ने बताया कि राज्य में उग्रवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने और शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से अभियान लगातार जारी हैं।

किसानों के लिए खाद-बीज की भरपूर उपलब्धता, 24 हजार मीट्रिक टन उर्वरक का सुरक्षित भंडारण

एजेंसी, कोलकाता

रायगढ़। जिले में खरीफ सीजन की तैयारियां पूरी गति से चल रही हैं और किसानों को खाद-बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन एवं कृषि विभाग द्वारा व्यापक स्तर पर व्यवस्थाएं की गई हैं। किसानों को समय पर कृषि आदान उपलब्ध कराने, उर्वरकों की कालाबाजारी पर प्रभावी नियंत्रण रखने तथा प्रत्येक कृषक तक समान रूप से लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से जिले में सतत निगरानी और सुव्यवस्थित वितरण व्यवस्था लागू की गई है। वर्तमान में जिले में 24 हजार मीट्रिक टन उर्वरकों का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है, जिससे किसानों की मांग के अनुरूप खाद उपलब्ध कराई जा रही है। प्रशासनिक सक्रियता और योजनाबद्ध प्रबंधन के कारण जिले में खाद एवं बीज वितरण व्यवस्था सुचारु रूप से संचालित हो रही है, जिससे किसानों में संतोष और विश्वास का माहौल बना हुआ है।

उप संचालक कृषि ने बताया कि शासन द्वारा निर्धारित खाद वितरण सीमा का उद्देश्य किसी भी किसान को खाद से वंचित करना नहीं है, बल्कि जिले के अंतिम छोर तक बसे किसानों को भी समान रूप से उर्वरक उपलब्ध कराना है। यह व्यवस्था उर्वरकों के संतुलित वितरण और कालाबाजारी पर प्रभावी नियंत्रण के लिए लागू की गई है। कृषि विभाग के उर्वरक निरीक्षक, निगरानी दल और मैदानी अमले प्रतिदिन सहकारी समितियों एवं निजी उर्वरक विक्रय केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। किसानों को उनके खेती के रकबे के अनुसार नियमानुसार उर्वरकों का वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है। किसी भी विक्रय केंद्र में अनियमितता पाए जाने पर तत्काल नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। आगे भी जिले के सभी उर्वरक विक्रय केंद्रों की निगरानी लगातार जारी रहेगी ताकि किसानों को बिना किसी परेशानी के आवश्यक उर्वरक उपलब्ध हो सकें।

कृषि विभाग द्वारा किसानों को डीएपी उर्वरक के विकल्प के रूप में एनपीके, एसएसपी तथा नैनो उर्वरकों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। साथ ही मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने और खेती की लागत कम करने के उद्देश्य से हरी खाद उत्पादन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में दीवार लेखन, जनसंपर्क गतिविधियों और जागरूकता अभियानों के माध्यम से किसानों को संतुलित उर्वरक प्रबंधन की जानकारी दी जा रही है। वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग से किसानों को बेहतर उत्पादन के साथ-साथ आर्थिक लाभ भी मिलेगा। इन प्रयासों का सकारात्मक प्रभाव अब ग्रामीण क्षेत्रों में दिखाई देने लगा है।

प्रयागराज हत्याकांडः दोस्त के साथ मिलकर की माता-पिता और बहन की हत्या, फिर खुद भी मारा गया

एजेंसी, प्रयागराज

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक परिवार के चार लोगों की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने बताया कि कारोबारी वीरेंद्र वैश्य के बेटे अभिषेक ने ही हत्या की साजिश रची थी। उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर पिता, मां अंकिता और 45 वर्षीय बहन मीनाक्षी की हत्या की। बाद में लूटे गए गहनों के बंटवारे को लेकर अभिषेक और उसके दोस्त के बीच झगड़ा हो गया। बात इतनी बढ़ी कि दोस्त ने अभिषेक की भी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपित दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस आयुक्त जोगेन्दर कुमार सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपित का नाम सनी गुप्ता है। वह मुट्ठीगंज थाना क्षेत्र के महाबीरन गली निवासी है। उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त हथियार लोहे की रॉड और करीब डेढ़ करोड़ रुपये के जेवरात बरामद किए हैं। मंगलवार को प्रयागराज जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के साउथ मलाका मोहल्ले में हीवेट चौराहा निवासी वीरेन्द्र वैश्य, पत्नी अनीता वैश्य, बेटी मीनाक्षी वैश्य का शव घर के अंदर और अभिषेक वैश्व का शव नीचे दुकान में मिला था।

पुलिस के अनुसार आरोपित सनी की वीरेंद्र वैश्य की मार्केट में समोसे की दुकान है। आरोपित की वीरेंद्र के बेटे अभिषेक से अच्छी दोस्ती थी और दोनों का एक साथ खाना-पीना था। पूछताछ में पता चला कि अभिषेक भारी कर्ज में था और पिता ने उसे संपत्ति से बेदखल कर रखा था। इसी बात को लेकर अभिषेक और उसके पिता के बीच अक्सर विवाद होता था। ऐसे में अभिषेक ने सनी के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई। 31 मई की रात अभिषेक ने सनी से बीयर और कचौड़ी मंगाया और दोनों ने मिलकर खाया-पिया। इसके बाद सबसे पहले अभिषेक ने अपने बहन की रॉड से हत्या कर दी, उसके बाद मां अनीता एवं पिता की हत्या कर दी। वहां पुलिस को गुमराह करने के लिए अभिषेक ने एक दफ्ती पर बंटी, बबली बहू ने मारा है लिख दिया। इससे घटना का सारा इल्जाम अभिषेक के भाई अश्विनी पर लग जाए। हत्या करने के बाद अभिषेक ने आलमारी से लगभग डेढ़ करोड़ के जेवरात निकाले और सनी के साथ नीचे उसकी दुकान में चला गया।

इसके बाद अभिषेक ने सनी को कुछ जेवर देकर कहा कि तुम यहां से चले जाओ। इसी बंटवारे को लेकर सनी गुप्ता का इरादा बदल गया और वह डेढ़ करोड़ के जेवरात की लालच में उसी रॉड से दुकान के अंदर अभिषेक की हत्या कर दी। सनी ने अभिषेक की हत्या करने के बाद जेवरात एक बैग में रखे और सबूत मिटाने के लिए शव को डिटर्जेंट पाउडर से धो दिया। इसके बाद फरार हो गया। मामले की जांच कर रही पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की मदद से आरोपित सनी को गिरफ्तार कर लिया।

आरोपपत्र में एमआईएम के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील का भी नाम शामिल

नासिक टीसीएस मामला

एजेंसी, नासिक

टीसीएस के नासिक कार्यालय से जुड़े यौन उत्पीड़न और जबरन धर्मांतरण मामले ने अब नया मोड़ ले लिया है। नासिक पुलिस द्वारा दाखिल पहले आरोपपत्र में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील का नाम सीधे तौर पर शामिल होने से राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है।

नासिक के देवलाली कैंप पुलिस स्टेशन में दर्ज इस पहले मामले में बलात्कार, अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण कानून और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप लगाए गए हैं। लगभग 3,500 पन्नों का यह पहला आरोपपत्र अदालत में प्रस्तुत किया गया है। मुख्य आरोपित निदा खान को अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद वह फरार हो गई थी। तकनीकी

जांच और गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की। जांच के दौरान एआईएमआईएम के पूर्व नगरसेवक मतीन पटेल द्वारा उसे छिपाने में मदद करने की बात सामने आई। पूछताछ के दौरान मतीन पटेल ने कथित रूप से कहा की इसके लिए इम्तियाज जलील साहब से पूछना होगा। इसके बाद पुलिस ने नारेगांव-कौसर सिडको इलाके में छापा मारकर निदा खान और उसके परिवार को हिरासत में लिया। जिस घर में निदा खान छिपी हुई थी, उस सहित दो अन्य संपत्तियों पर अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई की गई। इस मामले में घर के मालिक हनीफ खान को भी सह-आरोपित बनाया गया है।

सीईसी ज्ञानेश कुमार ने अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का किया उद्घाटन

एजेंसी, नई दिल्ली

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बुधवार को भारत अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन प्रबंधन संस्थान (आईआईआईडीईएम) में चुनाव आयोग के दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि आयोग देशभर में बीएलओ और बीएलए जैसे जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देता है ताकि 100 करोड़ से अधिक मतदाताओं से सहज संपर्क हो सके।

चुनाव आयोग ने यहां आईआईआईडीईएम में बुधवार को वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं और नवाचारों पर मीडिया की भूमिका विषयक इस दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जो गुरुवार तक चलेगा। इसमें 480 से अधिक प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं, जिनमें जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ), निर्वाचन रजिस्ट्रेशन अधिकारी (ईआरओ), विषय

♦ गलत जानकारियों के प्रसार रोकने पर चर्चा

विशेषज्ञ, शिक्षाविद, शोधार्थी और इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब के सदस्य शामिल हुए।

ज्ञानेश कुमार ने कहा कि सम्मेलन का उद्देश्य व्यावहारिक दृष्टिकोण वाले वैश्विक ज्ञान संसाधन विकसित करना है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय अनुभव, मानक मॉडल और सर्वोत्तम प्रथाओं का दस्तावेजीकरण किया जाएगा। यह प्रयास दिल्ली घोषणा (23 जनवरी) के तहत प्रस्तावित अंतिम विषयगत रिपोर्ट में योगदान देगा।

सभी जिलों के लिए प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति

एजेंसी, चेन्नई

तमिलनाडु सरकार ने राज्य में विकास परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, कल्याणकारी योजनाओं की बेहतर निगरानी और आपदा प्रबंधन व्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से सभी राजस्व जिलों के लिए प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति कर दी है। इस संबंध में राज्य सरकार ने बुधवार को आधिकारिक आदेश जारी किया। सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि विभिन्न जिलों में चल रही विकास परियोजनाओं की नियमित समीक्षा, सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने तथा प्राकृतिक आपदाओं, महामारी और अन्य आपातकालीन परिस्थितियों में राहत एवं पुनर्वास कार्यों के बेहतर समन्वय के लिए मंत्रियों को अतिरिक्त जिला प्रभार सौंपा गया है।

जारी आदेश के अनुसार, ग्रामीण विकास एवं जल संसाधन मंत्री एन. आनंद को विलुप्पुरम और कडलूर जिलों का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, जबकि लोक निर्माण एवं खेल विकास मंत्री आधव अर्जुन को चेन्नई और तिरुवन्नामलाई जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी प्रकार पी. वेंकटरमणन को मयिलाडुथुरै, रा. कुमार को तिरुवल्लूर, ने. मारिया विल्सन को तिरुनेलवेली, राजमोहन को पेरम्बलूर तथा क. थेन्नारसु को कांचीपुरम जिले का प्रभारी बनाया गया है। आर.वी. रंजीतकुमार को तिरुपत्तूर, त. शरदकुमार को चेंगलपट्टु, वन्नी अरसु को कल्लाकुरिची और कांतिराज को रानीपेट जिले की जिम्मेदारी दी गई है।

सरकार ने राजकुमार को धर्मपुरी और अरियालुर, ए.एम. शाजहान को नागपट्टिनम, विनोद को तंजावुर, रमेश को तिरुचिरापल्ली तथा सी. विजयलक्ष्मी को करूर जिले का प्रभारी नियुक्त किया है। वहीं लोकेश तमिलसेल्वन को नामक्कल, डॉ. के.जी. अरुणराज को तिरुप्पुर, से. कमली को नीलगिरि और म. विजय बालाजी को वेल्लोर जिले का दायित्व सौंपा गया है। इसके अलावा के.ए. सेंगोट्टैयन को ईरोड, वे. संपत कुमार को कोयंबटूर, आर. निर्मलकुमार को मदुरै एवं थेनी, मोहम्मद परवेज़ को पुदुकोट्टई तथा डॉ. टी.के. प्रभु को शिवगंगा जिले का प्रभारी बनाया गया है।

सरकारी आदेश के तहत एस. कीर्तना को कृष्णागिरि, कु. जगदीश्वरी को विरुधुनगर, पे. विश्वनाथन को तिरुवारुर, श्रीनाथ को तूतीकोरिन, पे. मदन राजा को रामनाथपुरम, आ. विजय तमिझन पार्थिबन को सेलम, से. राजेशकुमार को कन्याकुमारी, राजीव को तेनकासी तथा विग्नेश को दिंडीगुल जिले का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

सरकार ने सभी प्रभारी मंत्रियों को निर्देश दिया है कि वे संबंधित जिला कलेक्टरों, निगरानी अधिकारियों और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ नियमित समन्वय बनाए रखें। साथ ही विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करें, जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाना सुनिश्चित करें तथा किसी भी आपदा अथवा आपात स्थिति में राहत कार्यों के प्रभावी संचालन में सक्रिय भूमिका निभाएं। सरकार का मानना है कि जिला स्तर पर प्रभारी मंत्रियों की सक्रिय भागीदारी से प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी और योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं का समय पर समाधान किया जा सकेगा। इसके साथ ही राज्य सरकार की प्राथमिकताओं और विकास कार्यक्रमों की नियमित निगरानी भी सुनिश्चित होगी।

अग्निकांडों से सीखः यह केवल एक व्यक्ति या संस्था की नहीं बल्कि पूरे तंत्र की विफ़लता- जवाबदेही संस्थागत विफलताएँ भ्रष्टाचार और भविष्य की सुरक्षा का वैश्विक परिप्रेक्ष्य समग्र व्यापक विश्लेषण

लोकतंत्र की शान

» अग्निकांड केवल एक दुर्घटना नहीं,यह उस पूरे प्रशासनिक, नियामक और सामाजिक तंत्र की प्रणालीगत विफ़लता है जो नागरिकों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है?

» जब तक पारदर्शिता,नियमित निरीक्षण,शून्य- सहिष्णुता वाली भ्रष्टाचार-विरोधी नीति,संस्थागत समन्वय और कठोर जवाबदेही सुनिश्चित नहीं की जाएगी,तब तक ऐसी त्रासदियाँ बार-बार मानव जीवन की भारी कीमत वसूलती रहेंगी -एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र

गोंदिया - वैश्विक स्तर पर फिर एक बार हड़कंप मच गया जब दिल्ली के मालवीय नगर क्षेत्र में 3 जून 2026 को हुए भीषण अग्निकांड में बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु और घायल होने की खबर ने एक बार फिर यह प्रश्न खड़ा कर दिया है कि जब किसी होटल,अस्पताल, मॉल, स्कूल, औद्योगिक इकाई या व्यावसायिक भवन में आग लगती है तो आखिर ऐसी त्रासदी केवल आग के कारण होती है या उसके पीछे वर्षों से जमा होती आ रही प्रशासनिक, तकनीकी और संस्थागत विफलताओं की लंबी श्रृंखला भी जिम्मेदार होती है। दुनियाँ के किसी भी देश में आग लगना एक दुर्घटना हो सकती है,लेकिन आग के कारण बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु होना अक्सर एक प्रणालीगत विफलता माना जाता है। अंतरराष्ट्रीय आपदा प्रबंधन विशेषज्ञों का मानना है कि अधिकांश बड़े अग्निकांडों में मौतें केवल आग से नहीं बल्कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी, निकासी व्यवस्था की कमी, आपातकालीन प्रतिक्रिया में देरी,निरीक्षण तंत्र की कमजोरी और भ्रष्टाचार के कारण होती हैं।इसलिए किसी भी अग्निकांड की जांच केवल यह पता लगाने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए कि आग कैसे लगी, बल्कि यह भी देखा जाना चाहिए कि ऐसी स्थिति बनने ही क्यों दी गई।मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि, 3 जून 2026 की सुबह भारत की राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर स्थित फ्लोरिश स्टे होटल और उससे जुड़े रेस्तरां में लगी भीषण आग ने केवल 21 से अधिक लोगों की जान नहीं ली,बल्कि देश की शहरी सुरक्षा व्यवस्था,नियामक तंत्र, प्रशासनिक जवाबदेही और सार्वजनिक सुरक्षा संस्कृति पर भी गंभीर प्रश्नचिह्न लगा दिया। मीडिया में आए प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार भवन को केवल 6 कमरों की अनुमति थी,जबकि वहां लगभग 25 कमरे संचालित किए जा रहे थे। इससे भी अधिक चिंताजनक तथ्य यह सामने आया कि भवन के पास वैध फायर एनओसी नहीं थी तथा अंदर आने- जाने के लिए प्रभावी आपातकालीन निकास व्यवस्था भी उपलब्ध नहीं थी। बेसमेंट में लोगों के फंस जाने की खबरों ने स्थिति को और भयावह बना दिया।इस त्रासदी में 21 लोगों की मृत्यु हुई, 40 से अधिक लोगों को बचाया गया तथा अनेक गंभीर रूप से घायल अस्पतालों में जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहे हैं। मृतकों में मध्य एशिया और अफ्रीकी देशों के कई विदेशी नागरिक भी शामिल बताए जा रहे हैं, जो भारत में चिकित्सा उपचार या अन्य कारणों से आए थेप्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार लोग धुएं और लपटों से बचने के लिए तीसरी और चौथी मंजिल से कूदने को मजबूर हो गए, जबकि स्थानीय नागरिक नीचे गद्दे बिछाकर उनकी जान बचाने का प्रयास कर रहे थे। यह घटना किसी भूकंप, बाढ़ या प्राकृतिक आपदा का परिणाम नहीं थी, बल्कि प्रथम दृष्टया मानवीय लापरवाही,नियमों कीअवहेलना भ्रष्टाचार, कमजोर निगरानी और जवाबदेही की कमी का परिणाम प्रतीत होती है। यही कारण है कि यह दुर्घटना केवल एक होटल अग्निकांड नहीं बल्कि आधुनिक भारतीय शहरी प्रशासन की विफलताओं का प्रतीक बन गई है। साथियों बात अगर हम ऐसी घटनाओं के भारतीय इतिहास की करें तो, भारत का इतिहास ऐसी दर्दनाक घटनाओं से भरा पड़ा है। वर्ष 1997 में दिल्ली के उपहार सिनेमा फायर में 59 लोगों की मृत्यु हुई थी। जांच में सामने आया कि आपातकालीन निकास मार्ग अवरुद्ध थे, सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया था तथा प्रबंधन और प्रशासन दोनों स्तरों पर गंभीर लापरवाही हुई थी। वर्ष 2004 में कुम्बाकूनम स्कूल फायर में 94 स्कूली बच्चों की मृत्यु हुई।विद्यालय में अग्नि सुरक्षा प्रबंधअत्यंत कमजोर थे और ज्वलनशील सामग्री का उपयोग किया गया था। वर्ष 2019 में अनाज मंडी फायर में 43 लोगों की मृत्यु हुई, जहां फैक्ट्री अवैध रूप से संचालित हो रही थी और निकास व्यवस्था अपर्याप्त थी। उसी वर्ष दिल्ली के मुंडका फायर ट्रेगेडी जैसे मामलों में भी बड़ी संख्या में लोगों की जान गई। पश्चिम बंगाल के अमरी हॉस्पिटल फायर में 90 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी, जहां धुएं और आपातकालीन प्रबंधन की विफलता प्रमुख कारण बने। इन सभी घटनाओं में एक समान पैटर्न दिखाई देता है,नियमों का उल्लंघन, कमजोर निरीक्षण, भ्रष्टाचार, अपर्याप्त फायर ऑडिट और एजेंसियों के बीच सटीकता से समन्वय की कमी। साथियों, किसी भी बड़े शहर में अग्निशमन सेवा या फायर ब्रिगेड अंतिम रक्षा पंक्ति होती है। जब आग लग जाती है तब फायर ब्रिगेड को बुलाया जाता है, लेकिन वास्तविक प्रश्न यह है कि क्या फायर विभाग ने भवन का समय- समय पर निरीक्षण किया था, क्या भवन के पास वैध अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र था,क्या अग्निशमन उपकरण कार्यरत थे, क्या स्प्रिंकलर सिस्टम और स्मोक डिटेक्टर सक्रिय थे और क्या भवन मालिकों ने नियमों का पालन किया था। अनेक मामलों में देखा गया है कि फायर विभाग निरीक्षण तो करता है लेकिन बाद में नियमों के उल्लंघन को नजरअंदाज कर दिया जाता है। कई देशों में जांच रिपोर्टों ने यह दिखाया है कि अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र मिलने के बाद वर्षों तक दोबारा प्रभावी निरीक्षण नहीं होता। परिणामस्वरूप भवनों में अतिरिक्त कमरे, अवैध निर्माण, बंद आपातकालीन निकास और क्षमता से अधिक लोगों को रखने जैसी खतरनाक स्थितियाँ विकसित हो जाती हैं। यदि किसी भवन को छह कमरों की अनुमति मिली हो और बाद में उसमें कई गुना अधिक कमरे बना दिए जाएँ तो यह केवल भवन मालिक की गलती नहीं बल्कि निगरानी तंत्र कीसटीकता से विफलता भी मानी जाएगी। साथियों पुलिस की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है।सामान्यतः पुलिस को आपदा के समय कानून-व्यवस्था बनाए रखने,बचाव कार्यों को सुगम बनाने और अपराध संबंधी जांच करने का दायित्व दिया जाता है। लेकिन कई बार पुलिस का स्थानीय स्तर पर भवनों, होटलों, गेस्ट हाउसों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के बारे में पर्याप्त रिकॉर्ड नहीं होता। कुछ मामलों में अवैध गतिविधियों या नियमों के उल्लंघन की जानकारी होने के बावजूद समय रहते कार्रवाई नहीं की जाती। आपदा के बाद पुलिस अक्सर जांच शुरू करती है,जबकि वास्तविकvआवश्यकता जोखिमों की पूर्व पहचान और निवारक कार्रवाई की होती है।विकसित देशों में पुलिस, अग्निशमन विभाग और स्थानीय प्रशासन के बीच डेटा साझा करने की व्यवस्था होती है जिससे जोखिम वाले भवनों की पहचान पहले से की जा सके। भारत सहित अनेक विकासशील देशों में यह समन्वय अभी भी सीमित दिखाई देता है। साथियों,आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों की जिम्मेदारी केवल आपदा के बाद राहत देना नहीं बल्कि जोखिम को कम करना भी है।यदि किसी महानगर में हजारों होटल, हॉस्टल अस्पताल और व्यावसायिक इमारतें हैं तो यह सुनिश्चित करना आपदा प्रबंधन संस्थाओं का भी दायित्व है कि आपातकालीन निकासी योजना,मॉक ड्रिल, प्रशिक्षण और जन-जागरूकता कार्यक्रम नियमित रूप से संचालित हों। अक्सर पाया जाता है कि मॉक ड्रिल केवल कागजों में पूरी हो जाती है या सीमित स्तर पर आयोजित होती है। जब वास्तविक आपदा आती है तब कर्मचारी, सुरक्षा गार्ड और भवन प्रबंधक नहीं जानते कि लोगों को सुरक्षित बाहर कैसे निकाला जाए। इससे भगदड़, घबराहट और मृत्यु की संख्या बढ़ जाती है। एम्बुलेंस सेवाओं और चिकित्सा आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली की कमियाँ भी अनेक बार सामने आती हैं। अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार किसी बड़े शहर में आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया का समय न्यूनतम होना चाहिए। लेकिन ट्रैफिक जाम, अपर्याप्त एम्बुलेंस, समन्वय की कमी और अस्पतालों में तैयारी के अभाव के कारण घायल लोगों को समय पर उपचार नहीं मिल पाता। अग्निकांडों में धुएँ से दम घुटना एक प्रमुख कारण होता है और ऐसे मामलों में शुरुआती कुछ मिनट अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। यदि चिकित्सा सहायता में देरी होती है तो बचाई जा सकने वाली जानें भी चली जाती हैं। साथियों, स्थानीय निकायों और नगर निगमों की जवाबदेही शायद सबसे महत्वपूर्ण होती है क्योंकि भवन निर्माण की अनुमति,उपयोग परिवर्तन, व्यापार लाइसेंस और भवन सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी इन्हीं के पास होती है। दुनियाँ भर में हुई अनेक त्रासदियों की जांच में पाया गया कि भवन निर्माण नियमों का पालन नहीं किया गया था। कहीं अवैध मंजिलें बनाई गई थीं, कहीं निकास मार्ग बंद थे, कहीं विद्युत तारों का रखरखाव खराब था और कहीं अग्नि सुरक्षाउपकरण केवल दिखावे के लिए लगाए गए थे। यदि किसी नगर निकाय के रिकॉर्ड में भवन की एक स्थिति दर्ज हो और वास्तविकता में वह पूरी तरह अलग हो, तो यह निरीक्षण और प्रवर्तन तंत्र की गंभीर विफलता का संकेत है।

साथियों, भ्रष्टाचार का मुद्दा सबसे संवेदनशील लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है। दुनिया के अनेक देशों में हुई आपदाओं की जांच रिपोर्टों ने यह संकेत दिया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों को कभी-कभी रिश्वत, राजनीतिक संरक्षण या प्रशासनिक उदासीनता के कारण संरक्षण मिल जाता है। जब सुरक्षा प्रमाणपत्र पैसे या प्रभाव के आधार पर जारी होने लगें, जब निरीक्षण केवल औपचारिकता बन जाए और जब अवैध निर्माण को वर्षों तक अनदेखा किया जाए, तब एक प्रकार से भविष्य की त्रासदी की नींव रखी जा रही होती है। भ्रष्टाचार केवल वित्तीय अपराध नहीं बल्कि सार्वजनिक सुरक्षा के लिए प्रत्यक्ष खतरा है क्योंकि इसके कारण लोगों की जान सटीकता से जोखिम में पड़ जाती है। साथियों, शहरीकरण की तेज गति भी एक नई चुनौती बनकर उभरी है। महानगरों में भूमि की कीमतें बढ़ने के कारण भवन मालिक अधिक से अधिक जगह का व्यावसायिक उपयोग करना चाहते हैं। परिणामस्वरूप कई बार सुरक्षा मानकों की अनदेखी कर अतिरिक्त कमरे, अतिरिक्त मंजिलें या अवैध संरचनाएँ बना दी जाती हैं। प्रशासन यदि समय रहते इसे नहीं रोकता तो जोखिम लगातार बढ़ता जाता है।इसलिए शहरी नियोजन और अग्नि सुरक्षा को अलग-अलग विषयों के रूप में नहीं बल्कि एकीकृत दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है।तकनीक का उपयोग भविष्य में ऐसी घटनाओं को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। स्मार्ट सेंसर, रियल-टाइम मॉनिटरिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित जोखिम विश्लेषण, डिजिटल भवन रजिस्टर और स्वचालित अलार्म सिस्टम जैसी तकनीकें जोखिम की प्रारंभिक पहचान कर सकती हैं। लेकिन तकनीक तभी प्रभावी होगी जब उसके साथ प्रशासनिक इच्छाशक्ति और पारदर्शिता भी हो। केवल उपकरण खरीद लेना पर्याप्त नहीं है; उनका नियमित रखरखाव और परीक्षण भी आवश्यक है। साथियों, जनता की भूमिका भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। कई बार लोग सस्ते या सुविधाजनक विकल्पों के कारण ऐसे होटलों और भवनों का उपयोग करते हैं जिनकी सुरक्षा स्थिति संदिग्ध होती है। यदि नागरिक सुरक्षा मानकों के प्रति अधिक जागरूक हों और जोखिमपूर्ण प्रतिष्ठानों के विरुद्ध शिकायत करने की संस्कृति विकसित हो तो प्रशासन पर भी दबाव बनेगा। विकसित देशों में नागरिक सुरक्षा ऑडिट और सामुदायिक निगरानी को आपदा जोखिम न्यूनीकरण का अति महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। साथियों, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो कई देशों ने ऐसी घटनाओं से सीख लेकर कठोर सुधार किए हैं। कुछ देशों में डिजिटल निरीक्षण प्रणाली लागू की गई है जिसमें प्रत्येक निरीक्षण की तस्वीरें, वीडियो और जीपीएस आधारित रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध रहते हैं। इससे निरीक्षक की जवाबदेही बढ़ती है। कुछ स्थानों पर भवनों की अग्नि सुरक्षा स्थिति सार्वजनिक पोर्टल पर प्रदर्शित की जाती है ताकि नागरिक स्वयं देख सकें कि कोई भवन सुरक्षा मानकों का पालन कर रहा है या नहीं। कई देशों में यदि किसी भवन में गंभीर सुरक्षा उल्लंघन पाए जाते हैं तो उसे तत्काल सील कर दिया जाता है और संबंधित अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाती है।जवाबदेही का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत साझी जिम्मेदारी है। अक्सर किसी दुर्घटना के बाद केवल भवन मालिक को दोषी ठहराकर मामला समाप्त कर दिया जाता है, जबकि वास्तविकता में जिम्मेदारी कई स्तरों पर बंटी होती है। यदि अवैध निर्माण हुआ तो उसे रोकने वाला कौन था? यदि अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र जारी हुआ तो किन आधारों पर हुआ? यदि निरीक्षण नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? यदि आपातकालीन निकास बंद थे तो यह किसकी निगरानी में हुआ? यदि बचाव कार्य में देरी हुई तो उसका कारण क्या था? जब तक इन सभी प्रश्नों के उत्तर नहीं खोजे जाते तब तक किसी भी जांच को पूर्ण नहीं माना जा सकता। अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे क्रि किसी भी अग्निकांड को केवल एक दुर्घटना के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।यह उस पूरे प्रशासनिक, नियामक और सामाजिक तंत्र का परीक्षण होता है जो नागरिकों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। यदि एक भवन में क्षमता से अधिक लोग ठहराए गए, यदि सुरक्षा उपकरण काम नहीं कर रहे थे,यदि निरीक्षण प्रभावी नहीं थे, यदि भ्रष्टाचार ने नियमों को कमजोर किया,यदि बचाव में देरी हुई और यदि जवाबदेही तय नहीं हुई, तो यह केवल एक व्यक्ति या संस्था की नहीं बल्कि पूरे तंत्र की विफलता है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो या दुनिया के किसी भी महानगर में सुरक्षा का मूल सिद्धांत एक ही है,आपदा के बाद राहत से अधिक महत्वपूर्ण है आपदा से पहले रोकथाम। जब तक पारदर्शिता, नियमित निरीक्षण, शून्य-सहिष्णुता वाली भ्रष्टाचार-विरोधी नीति, तकनीकी आधुनिकीकरण, संस्थागत समन्वय और कठोर जवाबदेही सुनिश्चित नहीं की जाएगी, तब तक ऐसी त्रासदियाँ बार-बार मानव जीवन की भारी कीमत वसूलती रहेंगी। इसलिए हर अग्निकांड को एक चेतावनी के रूप में लेकर प्रणालीगत सुधार करना ही उन लोगों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी जिन्होंने ऐसी दुर्घटनाओं में अपने प्राण गंवाए हैं।

-संकलनकर्ता लेखक - क्रर विशेषज्ञ स्तंभकार साहित्यकार अंतरराष्ट्रीय लेखक चिंतक कवि संगीत माध्यमा सीए (एटीसी) एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र
9284141425

स्वतंत्रता सेनानी के पुत्रके मनकी पीड़ा , "राम रावण के मुखौटे"

— श्री रमेश कुमार मिश्रा

01- हमारे आत्मीय पूर्वजों स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, वीरांगनाओं और क्रांतिकारी शहीदों ने भारत देश को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराकर भारत में "रामराज्य" स्थापित करने का स्वप्न देखा था, लेकिन आजादी के बाद देश के राजनैतिक दलों के नेता समय-समय पर पक्ष-विपक्ष के खेल में एक दूसरे पर राम -रावण के मुखौटे लगाते रहे, और भारत देश की सीता रूपी जनता का हरण क्रमशः होता चला आ रहा है।

02- आजादी के लगभग अस्सी साल बाद भी भारत देश के लगभग आठ सौ राजनेता क्रमबद्ध हमारे आत्मीय पूर्वजों स्वतंत्रता सेनानियों, वीरांगनाओं और क्रांतिकारी शहीदों के स्वप्नों को कुचलते हुए उनके वास्तविक सम्मान तथा उनके उत्तराधिकारियों के अस्तित्व रूपी झोपड़ी का भाग्य अंधकार मय बनाने में लगे है, और सोने की लंका कोई ढहा नहीं सका। देश की जनता और मतदाता तथा नेता में कायरता फैली हुई है, उत्तम चरित्र का भ्रम पल रहा है। जो जग में अत्यंत गरीब हैं वही दाता बन रहे हैं, मनुष्य अपने हृदय की ज्वाला बुझा कर जानवर भी नहीं रह सकता, जबकि अपने आप को बेकार में देवता का भ्रम पाल लिया है, जबकि वह स्वत्व जनता और मतदाता से छीन रहा है। जय हिन्द, वन्देमातरम।

राहुल गांधी के उत्तराखंड दौरे को लेकर जनता में भारी उत्साह, स्वतंत्रता सेनानी परिवारों में खुशी की लहर

विचार विभाग की वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. जया शुक्ला बोलीं- देवभूमि और वीरभूमि उत्तराखंड में राहुल गांधी का आगमन शुभ संकेत

लोकतंत्र की शान

देहरादून। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के प्रस्तावित उत्तराखंड दौरे को लेकर प्रदेश में उत्साह का माहौल है। कांग्रेस विचार विभाग की वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. जया शुक्ला ने कहा कि राहुल गांधी के आगमन से आम जनता के साथ-साथ स्वतंत्रता सेनानियों के उत्तराधिकारी परिवारों में भी विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है। डॉ. शुक्ला ने कहा कि उत्तराखंड के लगभग 22 हजार स्वतंत्रता सेनानी परिवार राहुल गांधी के दौरे को सम्मान और आत्मीयता से जोड़कर देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश के महान स्वतंत्रता सेनानी परिवार की विरासत और संस्कारों को आगे बढ़ाने वाले राहुल गांधी का इस आंदोलन और बलिदान की धरती पर आगमन इन परिवारों के लिए गर्व का विषय है। उन्हें विश्वास है कि राहुल गांधी उनकी समस्याओं और अपेक्षाओं पर संवेदनशीलता के साथ विचार करेंगे। उन्होंने कहा कि श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने जिन संतस्वभावी गुणों का वर्णन किया है, वे गुण राहुल गांधी के व्यक्तित्व में दिखाई देते हैं। साथ ही वे संघर्षशील और योद्धा प्रवृत्ति के नेता भी हैं। डॉ. जया शुक्ला ने कहा कि उत्तराखंड केवल देवभूमि ही नहीं बल्कि वीरभूमि भी है। ऐसे में राहुल गांधी का यहां आगमन सामाजिक, राजनीतिक और जनभावनाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत शुभ एवं सकारात्मक माना जा रहा है। उन्होंने उत्तराखंड की जनता की ओर से राहुल गांधी का हार्दिक स्वागत करते हुए कहा कि उनका यह दौरा प्रदेश के लिए नई ऊर्जा और उम्मीद लेकर आएगा।— संवाददाता लोकतंत्र की शान

अवसंरचना, पर्यावरण संरक्षण और विकसित भारत के संकल्प को नई उड़ान '39,290 करोड़ के कैबिनेट ने दी मंजूरी

आलेख–विनोद कुमार सिंह 'तकियावाला'

भारत आज उस दौर से गुजर रहा है जहाँ विकास केवल आंकड़ों का खेल नहीं रह गया है,बल्कि नागरिक जीवन की गुणवत्ता, बेहतर संपर्क,स्वच्छ पर्यावरण और आर्थिक अवसरों के विस्तार से जुड़ा हुआ है।इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए केंद्र सरकार की कैबिनेट ने लगभग 39,290 करोड़ की छह महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी है।इन निर्णयों में विमानन क्षेत्र, राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार,तटीय संपर्क मार्गों का निर्माण तथा पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था जैसे विषय शामिल हैं।इन परियोजनाओं का महत्व केवल उनकी वित्तीय लागत में नहीं, बल्कि उनके दीर्घकालिक सामाजिक और आर्थिक प्रभाव में निहित है।यह निर्णय देश की बढ़ती आर्थिक आवश्यकताओं और विकसित भारत के लक्ष्य के अनुरूप दिखाई देते हैं।सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक एविएशन टर्बाइन फ्यूल अर्थात एटीएफ मूल्य स्थिरीकरण कोष की स्थापना है,जिसके लिए 10,000 करोड़ की राशि निर्धारित की गई है। भारत का विमानन क्षेत्र पिछले कुछ वर्षों में तेजी से विकसित हुआ है। क्षेत्रीय संपर्क योजना, नए हवाई अड्डों का निर्माण और बढ़ती यात्री संख्या ने इस क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है।आज वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव का सीधा प्रभाव विमानन ईंधन पर पड़ता है।एटीएफ की कीमतों में अचानक वृद्धि से एयरलाइनों की लागत बढ़ जाती है,जिसका असर यात्रियों पर भी पड़ता है।मूल्य स्थिरीकरण कोष ऐसी परिस्थितियों में सुरक्षा कवच का कार्य करेगा। इससे एयरलाइनों को बेहतर वित्तीय स्थिरता मिलेगी और हवाई यात्रा को अधिक सुलभ एवं किफायती बनाए रखने में सहायता प्राप्त होगी।कैबिनेट का दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय दिल्ली में पुराने ट्रकों और बसों को चरणबद्ध तरीके से हटाने की योजना से संबंधित है। .इस योजना पर 5,041 करोड़ खर्च किए जाएंगे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र लंबे समय से वायु प्रदूषण की चुनौती का सामना कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि पुराने व्यावसायिक वाहनों से निकलने वाला धुआं प्रदूषण का एक बड़ा कारण है।नई योजना के अंतर्गत पुराने वाहनों को हटाकर आधुनिक और कम प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को प्रोत्साहित किया जाएगा। यह केवल पर्यावरणीय सुधार का कदम नहीं है,बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ विषय है।स्वच्छ हवा नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि यह योजना प्रभावी रूप से लागू होती है तो राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता सुधारने में उल्लेखनीय योगदान मिल सकता है।सड़क अवसंरचना के क्षेत्र में सबसे बड़ी परियोजनाओं में रामेश्वरम- कोणार्क-पारादीप तटीय राजमार्ग शामिल है, जिस पर 8,301 करोड़ खर्च किए जाएंगे।भारत की लंबी समुद्री तटरेखा आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।पर्यटन, मत्स्य उद्योग,बंदरगाह आधारित गतिविधियां तथा समुद्री व्यापार इन क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था का आधार हैं।तटीय राजमार्ग के निर्माण से दक्षिण भारत और पूर्वी भारत के अनेक समुद्री क्षेत्रों के बीच संपर्क मजबूत होगा।इससे पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, माल परिवहन की लागत कम होगी तथा तटीय क्षेत्रों में निवेश आकर्षित होगा। यह परियोजना 'ब्लू इकोनॉमी' की अवधारणा को भी मजबूती प्रदान करती है,जिसमें समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग पर विशेष बल दिया जाता है।<बिहार के लिए भी कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। खगड़िया-पूर्णिया खंड के राष्ट्रीय राजमार्ग 31 एवं राष्ट्रीय राजमार्ग 231 को चार लेन में विकसित करने हेतु 3,936 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। बिहार लंबे समय से बेहतर सड़क संपर्क कीआवश्यकता महसूस करता रहा है।राज्य की बड़ी आबादी कृषि और छोटे व्यवसायों पर निर्भर है। बेहतर सड़कें किसानों को बाजारों तक पहुंच प्रदान करती हैं और औद्योगिक निवेश की संभावनाओं को बढ़ाती हैं।उत्तर-पूर्व भारत की ओर जाने वाले मार्गों के लिए भी यह परियोजना रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सड़क विस्तार से यात्रा समय कम होगा,दुर्घटनाओं में कमी आएगी और माल ढुलाई की दक्षता बढ़ेगी। तेलंगाना में राष्ट्रीय राजमार्ग 63 और 563 के विभिन्न खंडों को चार लेन में विकसित करने की परियोजना पर 7,597 करोड़ खर्च किए जाएंगे। तेलंगाना पिछले कुछ वर्षों में औद्योगिक और तकनीकी निवेश का प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है। बेहतर सड़क संपर्क उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। इस परियोजना से राज्य के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों, कृषि मंडियों और शहरी केंद्रों के बीच संपर्क बेहतर होगा। सड़क नेटवर्क मजबूत होने से नए निवेश आकर्षित होंगे तथा क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी।मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 347बी के उन्नयन के लिए 4,415 करोड़ की मंजूरी भी महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश देश के भौगोलिक केंद्र में स्थित होने के कारण परिवहन और लॉजिस्टिक्स की दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। बेहतर राजमार्ग राज्य को उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम भारत के साथ अधिक प्रभावी ढंग से जोड़ने में मदद करेंगे।राजमार्ग उन्नयन से न केवल यातायात सुविधाजनक होगा बल्कि औद्योगिक विकास,पर्यटन और ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। सड़क संपर्क में सुधार से निवेशकों का विश्वास बढ़ता है और विकास के नए अवसर पैदा होते हैं। इन सभी परियोजनाओं को एक साथ देखने पर स्पष्ट होता है कि सरकार का ध्यान केवल एक क्षेत्र विशेष पर केंद्रित नहीं है। विमानन, पर्यावरण, सड़क परिवहन, तटीय विकास और क्षेत्रीय संपर्क—सभी को समान महत्व दिया गया है। यह दृष्टिकोण संतुलित विकास की अवधारणा को दर्शाता है।इन परियोजनाओं का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू रोजगार सृजन है। सड़क निर्माण, पुल,फ्लाईओवर, परिवहन सुविधाओं और अन्य अवसंरचनात्मक कार्यों में बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार अवसर उत्पन्न होते हैं। निर्माण चरण के दौरान लाखों मानव-दिवस का रोजगार सृजित होता है, जबकि परियोजनाओं के पूर्ण होने के बाद व्यापार और सेवाओं के विस्तार से दीर्घकालिक रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। हालांकि किसी भी बड़ी परियोजना की सफलता उसके प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। समय पर भूमि अधिग्रहण,वित्तीय अनुशासन,पारदर्शिता और गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करना आवश्यक होगा।यदि परियोजनाएं निर्धारित समय और लागत सीमा के भीतर पूरी होती हैं, तभी उनका वास्तविक लाभ जनता तक पहुंच सकेगा।39,290 करोड़ के ये कैबिनेट निर्णय स्पष्ट संकेत देते हैं कि भारत अपनी विकास यात्रा को नई गति देने के लिए अवसंरचना और संपर्क सुविधाओं पर निरंतर निवेश कर रहा है।बेहतर सड़कें,स्वच्छ परिवहन,मजबूत विमानन क्षेत्र और तटीय विकास की योजनाएं आने वाले वर्षों में आर्थिक वृद्धि को नया आधार प्रदान कर सकती हैं।विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए ऐसे निर्णय केवल बजटीय घोषणाएं नहीं हैं,बल्कि भविष्य की अर्थव्यवस्था का आधार तैयार करने वाले निवेश हैं।यदि इन परियोजनाओं का प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाता है तो ये देश की विकास गाथा में एक महत्वपूर्ण अध्याय साबित हो सकती हैं।

टीएमसी में बगावत की दस्तक

लेखक-कांतिलाल मांडोत

ममता की पकड़ हुई कमजोर सत्ता के अहंकार और जन असंतोष ने बढ़ाई पार्टी की मुश्किले तुष्टिकरण और जंगलराज की राजनीति का अब सामने आया परिणाम पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक समय ऐसा था जब ममता बनर्जी का नाम ही तृणमूल कांग्रेस की पहचान माना जाता था। वर्ष 2011 में वामपंथी शासन को समाप्त कर सत्ता में आई ममता बनर्जी ने स्वयं को बंगाल की सबसे प्रभावशाली नेता के रूप में स्थापित किया। लेकिन समय के साथ जिस राजनीतिक शैली ने उन्हें सत्ता तक पहुंचाया, वही शैली अब उनकी सबसे बड़ी चुनौती बनती दिखाई दे रही है। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस के भीतर उभरती असंतोष की आवाजें इस बात का संकेत हैं कि पार्टी में सब कुछ सामान्य नहीं है। विधायकों की अलग बैठकें, नेतृत्व पर सवाल और पार्टी में टूट की चर्चाएं इस संकट को और गहरा कर रही हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह स्थिति अचानक पैदा नहीं हुई है। इसके पीछे वर्षों से चल रही ऐसी नीतियां और कार्यशैली रही हैं जिनसे पार्टी के भीतर और बाहर दोनों स्तरों पर असंतोष बढ़ता गया। तुष्टिकरण की राजनीति, भ्रष्टाचार के आरोप, कट मनी संस्कृति, राजनीतिक हिंसा और कानून व्यवस्था को लेकर उठते सवालों ने धीरे-धीरे जनता के बीच टीएमसी की छवि को नुकसान पहुंचाया। चुनावी हार उसी असंतोष की अभिव्यक्ति मानी जा रही है। ममता बनर्जी ने लंबे समय तक खुद को अल्पसंख्यकों की सबसे बड़ी हितैषी नेता के रूप में प्रस्तुत किया। उनकी सरकार ने कई ऐसी योजनाएं शुरू कीं जिनका लाभ समाज के विभिन्न वर्गों को मिला, लेकिन विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा कि राज्य में विकास और सुशासन की बजाय वोट बैंक की राजनीति को प्राथमिकता दी गई। हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच संतुलन बनाने के बजाय विशेष वर्गों को खुश करने की कोशिश ने सामाजिक और राजनीतिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा दिया। इसका प्रभाव धीरे-धीरे चुनावी राजनीति पर भी दिखाई देने लगा। बंगाल में पिछले कुछ वर्षों के दौरान राजनीतिक हिंसा की घटनाएं लगातार चर्चा का विषय बनी रहीं। पंचायत चुनावों से लेकर विधानसभा चुनावों तक हिंसा, धमकी और बूथ कब्जाने के आरोप लगते रहे। विपक्षी दलों का आरोप रहा कि राज्य में लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर हुई हैं और प्रशासन पर राजनीतिक दबाव बढ़ा है। यही कारण है कि राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठते रहे। जनता के एक बड़े वर्ग में यह धारणा बनी कि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती जबकि आम नागरिकों की शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया जाता। कट मनी का मुद्दा भी तृणमूल कांग्रेस के लिए बड़ी परेशानी का कारण बना। विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से कथित तौर पर रिश्वत लेने के आरोपों ने पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाया। चुनावी हार के बाद कई क्षेत्रों में नेताओं द्वारा लोगों को पैसे लौटाने की खबरें सामने आना इस बात का संकेत माना गया कि जनता के बीच इस मुद्दे को लेकर गहरा आक्रोश था। जब किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता और स्थानीय नेता जनता के विश्वास को खोने लगते हैं तो उसका असर अंततः चुनावी नतीजों में दिखाई देता है। आज टीएमसी के सामने सबसे बड़ी चुनौती केवल विपक्ष नहीं बल्कि आंतरिक असंतोष भी है। पार्टी के कई नेता और विधायक महसूस कर रहे हैं कि संगठन में संवाद की कमी है और निर्णय कुछ लोगों तक सीमित हो गए हैं। यही कारण है कि चुनावी हार के तुरंत बाद अलग बैठकों और बागी तेवरों की खबरें सामने आने लगीं। यदि किसी दल के विधायक सार्वजनिक रूप से नेतृत्व पर सवाल उठाने लगें तो यह केवल चुनावी पराजय का परिणाम नहीं बल्कि लंबे समय से पनप रहे असंतोष का संकेत होता है।

WTC का हिस्सा नहीं होगा भारत व अफगान टेस्ट मैच

नई दिल्ली (एजेंसी)। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 समाप्त होने के बाद भारतीय टीम 6 जून को मैदान पर दिखेगी। अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच उसका 2026–27 सत्र शुरू होगा। न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर के महाराजा यादविन्द्र सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में पहली बार टेस्ट मैच खेला जाएगा। हालांकि, यह टेस्ट मैच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025–27 चक्र का हिस्सा नहीं होगा। यानी इसका डब्ल्यूटीसी रैंकिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

भारत–अफगानिस्तान टेस्ट मैच के डब्ल्यूटीसी का हिस्सा न होने का दो कारण है। पहला कारण यहा है कि अफगानिस्तान डब्ल्यूटीसी का हिस्सा नहीं है। दूसरा कारण यह है कि सीरीज में कम से कम दो मैच होने चाहिए। अफगानिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का फुल मेंबर है और उसे टेस्ट का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन यह मौजूदा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल में हिस्सा लेने वाली नौ टीमों में से एक नहीं है। आईसीसी अभी सिर्फ टॉप नौ रैंक वाली टीमों को ही डब्ल्यूटीसी साइकल में हिस्सा लेने की इजाजत देता है। इसलिए, अफगानिस्तान से जुड़े किसी भी टेस्ट मैच में डब्ल्टीसी अंक नहीं मिलते। आईसीसी के डब्ल्यूटीसी में अभी सिर्फ 9 देश भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और वेस्टइंडीज शामिल हैं। तीन फुल मेंबर अफगानिस्तान, आयरलैंड और जिम्बाब्वे इसका हिस्सा नहीं हैं।

कम से कम दो मैच होना जरूरी

फिलहाल आईसीसी नियमों के अनुसार एक टेस्ट मैच की सीरीज डब्ल्यूटीसी का हिस्सा नहीं होती। कम से कम 2 मैच होने पर ही कोई सीरीज डब्ल्यूटीसी का हिस्सा हो सकती है। ऐसे में न्यू चंडीगढ़ में भारत–अफगानिस्तान टेस्ट मैच डब्ल्यूटीसी का हिस्सा नहीं होगा।

भारत–अफगानिस्तान के बीच दूसरी बार टेस्ट मैच– भारत–अफगानिस्तान के बीच दूसरी बार टेस्ट मैच होगा। 2018 में पहली बार भारत पारी और 262 रन से जीता था। दूसरी बार भारत में टेस्ट मैच जून में होगा। पहली बार भी अफगानिस्तान के खिलाफ बेंगलुरु में टेस्ट मैच हुआ था।

टी20 वर्ल्ड कप से पहले किया सरेंडर, इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैच की सीरीज गंवाई

भारत की तैयारी की खुली पोल

सीरीज हारना, पता चलता है, तैयारी कितनी थी

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारतीय महिला टीम ने वूमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 से ठीक पहले इंग्लैंड के सामने सरेंडर कर दिया और 3 मैचों की टी20 सीरीज के आखिरी मुकाबले में भी भारत को 6 विकेट से हार मिली। इस हार से साथ ही भारत ने इस टी20 सीरीज को 1-2 से गंवा दिया। इस टी20 सीरीज के पहले मैच में भारत को जीत मिली थी, लेकिन फिर उसे इंग्लैंड की महिला टीम ने दूसरे और तीसरे मैच में हराते हुए सीरीज पर अपना कब्जा जमा लिया।

महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 12 जून से इंग्लैंड में होगी और भारतीय महिला टीम इस आईसीसी टूर्नामेंट से ठीक पहले इंग्लैंड दौरे पर है। यहां पर भारत ने वर्ल्ड कप से शुरू होने से ठीक पर इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज खेली जिसे तैयारी की लिहाज से काफी अहम माना जा रहा था, लेकिन भारत ने इस सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ सरेंडर कर दिया और उसे हार का सामना करना पड़ा। अब भारत को इस सीरीज में मिली हार के बाद अपनी कमियों को दूर करते हुए इंग्लैंड के खिलाफ मैदान पर उतरना होगा।

भारत ने 1-2 से गंवाई टी20 सीरीज

इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में भारतीय ओपनर स्मृति मंधाना ने 8 रन की पारी खेली जबकि शेफाली वर्मा भी नहीं चलीं और उन्होंने 11 रन बनाए। जेमिमा ने 19 गेंदों पर 29 रन की तेज पारी खेली जबकि कप्तान हरमनप्रीत कौर 56 रन बनाकर नाबाद रहीं। इंग्लैंड की धरती पर किसी टी20 मैच में ये उनका इंग्लैंड के खिलाफ पहला अर्धशतक भी रहा। भारत के लिए इस सीरीज में सबसे बड़ी चिंता की बात ये रही कि टीम की ओपनिंग जोड़ी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। भारत को इस कमी को दूर करना होगा। टी20 वर्ल्ड कप में जीत के लिए मंधाना का बल्ला चलना जरूरी है जो पिछले कुछ वक्त से खामोश है।

भारत को 6 विकेट से मिली हार

इंग्लैंड के खिलाफ इस टी20 सीरीज के तीसरे मुकाबले में पहले बैटिंग करते हुए कप्तान हरमनप्रीत कौर की 56 रन की अर्धशतकीय पारी साथ ही यास्तिका भाटिया और दिप्ती शर्मा की 32–32 रन की पारी के दम पर 20 ओवर में 5 विकेट पर 180 रन बनाए। इंग्लैंड को जीत के लिए 181 रन का लक्ष्य मिला और इस टीम ने एलिस कैप्सी की 82 रन की पारी साथ ही हीथर नाइट की नाबाद 70 रन की पारी के दम पर 18.3 ओवर में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच जीत लिया। एलिस कैप्सी इस मैच में मैन ऑफ द मैच रहीं जबकि उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुना गया।

केएम दीक्षा डोप टेस्ट में फेल

महिलाओं की 1500 मीटर में हैं राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी

नई दिल्ली। महिलाओं की 1500 मीटर की राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी और राष्ट्रीय खेलों की रजत पदक विजेता केएम दीक्षा डोप जांच में विफल हो गई हैं। 27 साल की दीक्षा ने इस साल अप्रैल में सिर्फ एक प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। वह एक प्रतिबंधित पदार्थ के लिए पॉजिटिव पाई गई हैं। यह पदार्थ किस तरह का था और उनकी जांच की और जानकारी का पता नहीं चला है। एक भरोसेमंद सूत्र ने पीटीआई को बताया, 'हां, यह पुष्टि हो गई है कि वह डोप जांच में विफल हो गई हैं।' इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी। दीक्षा ने हाल ही में रांची में हुए फेडरेशन कप में हिस्सा नहीं लिया था, जो ग्लास्गो में 2026 राष्ट्रमंडल खेल (23 जुलाई से दो अगस्त) के लिए चुने जाने वाले खिलाड़ियों के लिए अनिवार्य टूर्नामेंट था।

भारत अभी अयोग्य एथलीटों की सूची में शीर्ष पर

दीक्षा की टाइमिंग भी एएफआई द्वारा तय राष्ट्रमंडल खेलों के क्वालिफाइंग मानक के तौर पर तय 4 :05.09 सेकंड से काफी बाहर थी। उनका राष्ट्रीय रिकॉर्ड 4 :04.78 है, जो उन्होंने मई 2024 में बनाया था। भारत अभी अयोग्य एथलीटों की एथलेटिक्स इंटीग्रिटी इकाई (एआईयू) की सूची में शीर्ष पर है, जिसमें मई 2026 के आखिर तक 154 एथलीटों को निलंबित किया गया, जो कीनिया के 147 और रूस के 65 की तुलना में काफी ज्यादा है।

हरमनप्रीत कौर पाकिस्तान के खिलाफ उतरते ही रचेंगी इतिहास

रोहित शर्मा का रिकॉर्ड भी होगा ध्वस्त

नई दिल्ली (एजेंसी)। आईपीएल खत्म हो चुका है और अब रोमांच शिफ्ट होने वाला है इंटरनेशनल क्रिकेट की ओर। पुरुष टीम जहां इसी साल टी20 चैंपियन बनकर आई है। वहीं नवंबर 2025 में इतिहास रचने वाली वनडे विश्व चैंपियन महिलाओं की नजरें अब टी20 के विश्व कप पर होंगी। 12 जून से इंग्लैंड की मेजबानी में महिला टी20 वर्ल्ड कप का आगाज होने वाला है। इस टूर्नामेंट के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो चुका है और भारतीय टीम विश्व विजेता कप्तान हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में उतरेगी।

टी20 वर्ल्ड कप में हरमनप्रीत कौर का ऐसा रहा प्रदर्शन

भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर महिला टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाली चौथी क्रिकेटर हैं। उन्होंने इस टूर्नामेंट के इतिहास में 2009 से 2024 तक 39 मैच खेलते हुए 25.03 की औसत से 726 रन बनाए हैं। उनके नाम एक शतक भी दर्ज है और 103 रन उनका टी20 विश्व कप में सर्वोच्च स्कोर है। उन्होंने गेंदबाजी करते हुए 11 विकेट भी झटके हैं। आगामी सीजन में उनके ऊपर अत्यधिक नजरें होने वाली हैं। क्योंकि हर भारतवाशी का सपना होगा कि महिला टीम वनडे के बाद अब टी20 विश्व कप की भी चैंपियन बने।

14 जून को पाकिस्तान के साथ है मुकाबला

टीम इंडिया का पहला मैच 14 जून को बर्मिंघम में पाकिस्तान के खिलाफ होगा। टीम इंडिया के अभियान की शुरुआत हाईवोल्टेज मुकाबले से होगी। इस मैच में उतरते ही हरमनप्रीत कौर इतिहास रच देंगी। वह 2009 से लगातार हर टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय महिला टीम का हिस्सा रही हैं और यह उनका 10वां टी20 वर्ल्ड कप होगा। इस मामले में हरमनप्रीत कौर भारत के विश्व विजेता टी20 कप्तान रोहित शर्मा से आगे निकल जाएंगी। महिलाओं में तो हरमनप्रीत कौर पहले से ही सबसे ज्यादा टी20 वर्ल्ड कप खेलने वाली खिलाड़ी हैं। वहीं इस टूर्नामेंट में उतरते ही वह पुरुष क्रिकेटर रोहित शर्मा, शाकिब उल हसन और आयरलैंड के पॉल स्टर्लिंग को भी पीछे छोड़ देंगी। उनका यह 10वां टी20 वर्ल्ड कप होगा। जबकि टी20 से रिटायर हो चुके रोहित शर्मा ने अपने करियर में सबसे ज्यादा 9 टी20 वर्ल्ड कप खेले थे।

व्यापार

एनएचपीसी के सस्ते में शेयर खरीदने का मौका, आम निवेशकों के लिए खुला ओएफएस

नईदिल्ली, एजेंसी। घरेलू शेयर बाजार में गिरावट की आंधी के बीच बुधवार को नवरत्न कंपनी एनएचपीसी लिमिटेड के शेयरों में तूफानी तेजी आई है। एनएचपीसी लिमिटेड के शेयर बुधवार को 5 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 75.99 रुपये पर पहुंच गए हैं। एनएचपीसी लिमिटेड का ऑफर फॉर सेल बुधवार को आम निवेशकों के लिए खुल गया है। ऑफर फॉर सेल में कंपनी के शेयरों को सस्ते में खरीदने का मौका है। कंपनी के शेयर मंगलवार को गिरावट के साथ 72.28 रुपये पर

बंद हुए थे।

केंद्र सरकार नवरत्न कंपनी एनएचपीसी लिमिटेड में अपनी 6 पर्सेंट तक हिस्सेदारी बेच रही है। कंपनी के ऑफर फॉर सेल के लिए 71 रुपये का फ्लोर प्राइस तय किया गया है। यानी, ऑफर फॉर सेल का फ्लोर प्राइस सोमवार के क्लोजिंग प्राइस से करीब 8 पर्सेंट डिस्काउंट पर है। मार्च 2026 तिमाही के आखिर में एनएचपीसी लिमिटेड में आम निवेशकों को 8.28 पर्सेंट हिस्सेदारी रही।

नॉन रिटेल इनवेस्टर्स से ऑफर फॉर सेल को मिला जबरदस्त रिस्पॉन्स–नवरत्न कंपनी एनएचपीसी लिमिटेड का ऑफर फॉर सेल नॉन रिटेल इनवेस्टर्स के लिए मंगलवार 2 जून को खुला।

सीएमआर ग्रीन टेक्नोलॉजी का आईपीओ खुला, जीएमपी तो चढ़ ही रहा है

नई दिल्ली, एजेंसी। अमेरिका-ईरान युद्ध के बीच भारतीय पूंजी बाजार में आज एक अच्छा आईपीओ खुला है। इसे अच्छा आईपीओ इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम लगातार बढ़ता दिख रहा है। यह आईपीओ है नॉन-फेरस मेटल की रिसाइकिलिंग करने वाली कंपनी सीएमआर ग्रीन टेक्नोलॉजीज का। इस कंपनी के आईपीओ में निवेशक शुक्रवार, 5 जून 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। जानते हैं इस आईपीओ के बारे में सबकुछ।

सीएमआर ग्रीन टेक्नोलॉजीज के आईपीओ का प्राइस बैंड 182 से 192 रुपये तय किया गया है। इस आईपीओ में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए 78 शेयर का लॉट तय किया गया है। मतलब कि आवेदकों को कम से कम 78 शेयरों के लिए आवेदन करना होगा। इससे ऊपर इतने ही शेयरों के गुणक में आवेदन

होगा। सीएमआर ग्रीन टेक्नोलॉजीज के सीएमडी मोहन अग्रवाल ने रोड शो के दौरान बताया था कि इस आईपीओ के जरिए कंपनी 3,28,58,323 इक्विटी शेयर जारी कर 630.88 करोड़ रुपये जुटाएगी। यह इश्यू एंकर निवेशकों के लिए अगले मंगलवार को खुला था। आज से रिटेल एवं अन्य श्रेणी के निवेशक आवेदन कर सकेंगे।

क्या करती है कंपनी :दिल्ली एनसीआर में फरीदाबाद की यह कंपनी नॉन फेरस मेटल जैसे अल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, स्टेनलेस स्टील, मैग्नीनिशयम आदि की रिसाइकिलिंग करती है। मतलब कि नॉन-फेरस मेटल के कबाड़ को गला कर उसकी अशुद्धियां दूर करती है। इसके लिए कंपनी देश-दुनिया के विभिन्न देशों से धातुओं के कबाड़ मंगाती है। इसे वैज्ञानिक और इको फ्रेंडली तरीके से रिसाइकिल किया जाता है। इसके अधिकतर इंडस्ट्रियल ग्राहक हैं। इनके ग्राहकों की सूची में होंडा कार्स इंडिया, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, रॉयल इनफील्ड, मारुति सुजुकी, जिंदल स्टेनलेस आदि हैं। 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त अवधि के लिए ष्टरूक्र ग्रीन ने 162.39 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट दर्ज किया है। इस दौरान कंपनी का रेवेन्यू 6,291 करोड़ रुपये रहा।

15 साल की उम्र, करोड़ों की संपत्ति!

नाबालिग वैभव सूर्यवंशी को भरना होगा टैक्स नाबालिगों के लिए क्या हैं नियम

नईदिल्ली, एजेंसी। भारतीय क्रिकेट में उभरते हुए सितारे वैभव सूर्यवंशी इन दिनों खूब चर्चा में हैं। महज 15 साल की उम्र में उन्होंने क्रिकेट की दुनिया में अपनी पहचान बना ली है। मिंट की रिपोर्ट के अनुसार, उनकी कुल संपत्ति करीब 7 करोड़ तक पहुंच चुकी है। कॉन्ट्रैक्ट, क्रिकेट टूर्नामेंटों से मिलने वाली रकम और ब्रांड एंडोर्समेंट्स ने इतनी कम उम्र में उन्हें करोड़पति बना दिया है। लेकिन, इस खबर के साथ एक दिलचस्प सवाल भी उठता है कि क्या इतनी कम उम्र में कमाई करने वाले बच्चों को भी इनकम टैक्स देना पड़ता है अगर हां, तो टैक्स की गणना कैसे होती है आइए इसको जरा विस्तार से समझते हैं।

भारत के आयकर कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति 'नाबालिग' माना जाता है। सामान्य तौर पर नाबालिग की आय को उसके माता-पिता की आय में जोड़ दिया जाता है, जिसे क्लबिंग ऑफ इनकम कहा जाता है, यानी अगर किसी बच्चे के नाम पर बैंक एफडी, निवेश या अन्य स्रोतों से आय होती है, तो वह आय उस माता-पिता की आय में जुड़ती है, जिसकी टैक्सेबल आय अधिक है। इसके बाद उस आय पर टैक्स भी उसी माता-पिता के नाम पर लगाया जाता है।

हालांकि, कानून में कुछ महत्वपूर्ण अपवाद भी हैं। अगर कोई नाबालिग अपनी प्रतिभा, कौशल, ज्ञान या मेहनत के दम पर कमाई करता है, तो उस आय को माता-पिता की आय में नहीं जोड़ा जाता। उदाहरण के लिए क्रिकेट, अभिनय, गायन, सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन, शतरंज, डांस या अन्य प्रोफेशनल एक्टिविटीज से होने वाली कमाई सीधे बच्चे की अपनी आय मानी जाती है।

यही नियम वैभव सूर्यवंशी पर भी लागू होता है। उनकी अधिकांश कमाई क्रिकेट खेलने, टूर्नामेंट फीस, कॉन्ट्रैक्ट और ब्रांड एंडोर्समेंट से आती है। चूंकि यह आय उनकी व्यक्तिगत प्रतिभा और प्रदर्शन के आधार पर अर्जित हुई है, इसलिए इसे उनके माता-पिता की आय में क्लब नहीं किया जाएगा। इस स्थिति में वैभव स्वयं एक टैक्सपेयर माने जाएंगे और उनकी आय पर सामान्य आयकर नियमों के अनुसार टैक्स लगाया जा सकता है।

ऐसे मामलों में नाबालिग के नाम से

अलग इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल की जाती है। चूंकि बच्चा कानूनी रूप से नाबालिग होता है, इसलिए उसके माता-पिता या कानूनी अभिभावक उसकी ओर से फाइल करते हैं। अगर आय प्रोफेशनल गतिविधियों से आती है, तो आमतौर पर या कुछ परिस्थितियों में फॉर्म का उपयोग किया जा सकता है।

इसके अलावा आयकर अधिनियम की धारा 10(32) के तहत माता-पिता को प्रति बच्चे 1,500 तक की छूट भी मिलती है, अगर बच्चे की आय उनके साथ क्लब की गई हो। हालांकि, यह छूट केवल उन मामलों में लागू होती है, जहां बच्चे की आय स्वतंत्र प्रतिभा से नहीं बल्कि निवेश या अन्य स्रोतों से आती हो।

एक्सपर्ट का कहना है कि आज के दौर में कई बच्चे यूट्यूब, सोशल मीडिया, अभिनय, खेल और अन्य क्षेत्रों में लाखों-करोड़ों रुपये कमा रहे हैं। ऐसे में उनके माता-पिता को आयकर नियमों की सही जानकारी होना बेहद जरूरी है, ताकि भविष्य में किसी तरह की टैक्स संबंधी परेशानी न हो। वैभव सूर्यवंशी का उदाहरण यह दिखाता है कि उम्र चाहे कम हो, लेकिन अगर कमाई प्रतिभा और मेहनत के दम पर हो रही है, तो भारतीय कर कानून उसे एक स्वतंत्र आय के रूप में मान्यता देता है। यही कारण है कि 15 साल की उम्र में करोड़ों रुपये कमाने वाले वैभव को भी आयकर नियमों के तहत अलग टैक्स रिटर्न दाखिल करनी पड़ सकती है।

भारत से आगे निकले ताइवान-साउथ कोरिया, उदय कोटक ने दी वेक-अप कॉल

नई दिल्ली, एजेंसी। एआई शेयरों में आई तेजी की बदौलत पहले ताइवान और फिर साउथ कोरिया ने इक्विटी मार्केट के मामले में भारत को पछाड़ दिया है। भारत के पिछड़ने की सबसे बड़ी वजह यह मानी जा रही है कि वह एआई टेक्नोलॉजी में निवेश के मामले में दुनिया के दूसरे देशों से काफी पीछे है। पिछले कुछ समय में एआई कंपनियों के शेयरों में काफी तेजी आई है। इसकी बदौलत ताइवान और साउथ कोरिया जैसे देश भारत से आगे निकल गए हैं। इस बीच देश के सबसे रईस बैंकर उदय कोटक ने भारतीय कंपनियों से एआई में निवेश करने की अपील की है।

कोटक ने इंडिया इंक से भारत के भविष्य के लिए निवेश करने का आग्रह किया है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि दुनिया की टॉप टेक कंपनियों में से एक गूगल कैश-रिच होने के बावजूद 80 बिलियन (करीब 7.6 लाख करोड़ रुपये) जुटा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिलिकॉन वैली की टेक कंपनी अपने एआई इन्फ्रास्ट्रक्चर और वैश्विक कंप्यूटिंग क्षमता को तेजी से बढ़ाने के लिए फंड जुटा रही है। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट 4.342 ट्रिलियन डॉलर के मार्केट कैप के साथ दुनिया की तीसरी बड़ी वैल्यूएबल कंपनी है।

बिजनेस पर फोकस करने का समय

कोटक ने कहा कि गूगल का सालाना प्रॉफिट .160 अरब था और पिछली तिमाही में कंपनी ने 62 अरब का प्रॉफिट कमाया। उन्होंने कहा कि यह भारत की सभी लिस्टेड कंपनियों के कुल प्रॉफिट और मार्केट कैप के लगभग बराबर है। यह सभी कंपनियों के लिए भविष्य में निवेश करने का एक वेक–अप कॉल है। उन्होंने कहा, 'अब आईपीएल खत्म हो चुका है, तो भारत के लिए बिजनेस के बिजनेस पर फोकस करने का समय आ गया है।' कारोबारी हलकों में अक्सर आईपीएल को अक्सर क्रिकेट का बिजनेस कहा जाता है। कोटक की यह चेतावनी ऐसे समय में आई है जब भारत को एआई टेक्नोलॉजी में निवेश के मामले में पीछे माना जा रहा है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक सैयद ज़की हैदर के लिए इरानीयन आर्ट प्रिंटर्स 1534 कासिमजान स्ट्रीट दरियागंज नई दिल्ली 11006 से मुद्रित कराकर, 2684 गली काले खां कूचा चलान दरियागंज नई दिल्ली 02 से प्रकाशित किया।
संपादक : सैयद ज़की हैदर- हैड ऑफिस :- एफ19/4 सेकेंड फ्लोर नफीश रोड जामिया नगर दिल्ली- 110025., सम्पर्क सूत्र :- 9911371802, 9810383593 RNI No.: DELHIN/2008/23928
जितेन्द्र कुमार बिस्वाल ब्यूरो चीफ उड़ीसा/ गोविंद कनोडिया/ पटना/ सैय्यद यूसुफ अली नक़वी-पॉलिटिकल एडिटर। ई-मेलः- (LOKTANTRAKISHAAN@GMAIL.COM

किसी भी प्रकार के विवाद हेतु निपटारे के लिए केवल दिल्ली न्यायालय ही मान्य होगी।
नोट- किसी भी समाचार/आलेख पर दावा प्रति दावा/आपत्ति समाचार प्रकाशन के 15 दिनों के अन्तराल तक ही मान्य होगा। समाचार पत्र में प्रकाशित आलेख से संपादक/प्रकाशक का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

क्षेत्रीय कार्यालय अनवार मंजिल नया टोला गंज नंबर 01 बेतिया/ बिहार/ पिन नंबर 84 5438/>> संवाददाता, सना खान/(डॉ. अमानुल हक) स्थानीय संपादक/बिहार)